IASBABA

One Stop Destination for UPSC/IAS Preparation

60 Days Final Compilation

DELHI

5B, Pusa Road, Karol Bagh, New Delhi –110005. Landmark: Just 50m from Karol Bagh Metro Station, GATE No. 8 (Next to Croma Store)

Ph:0114167500

BANGALORE

#1737/37, MRCR Layout, Vijaynagar Service Road, Vijaynagar, Bangalore 560040. PH: 09035077800 / 7353277800

Q.1) भारतीय अर्थव्यवस्था के संदर्भ में, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें

1. पिछले पांच वर्षों में सकल घरेलू उत्पाद में लगातार वृद्धि हुई है
2. पिछले पांच वर्षों में प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि दर लगातार बढ़ी है

ऊपर दिए गए कथनों में से कौन सा सही है / हैं?

a) केवल 1
b) केवल 2
c) 1 और 2 दोनों
d) न तो 1 और न ही 2

Q.1) Solution (a)

कथन 1	कथन 2
सत्य	असत्य
पिछले पांच वर्षों में जीडीपी की वृद्धि दर में उतार-चढ़ाव आया है, जबकि यह कभी भी नकारात्मक नहीं रहा है। पिछले पांच वर्षों में सकल घरेलू उत्पाद में लगातार वृद्धि हुई है।	2016-17 में प्रति व्यक्ति आय की वृद्धि दर 2017-18 में 9.3% से घटकर 8.6% हो गई। यह 2018-19 में बढ़कर 10.0% हो गयी है।

- इस तरह के प्रश्नों में, यह देखें कि क्या 'निरपेक्ष मूल्य' में वृद्धि / कमी पूछी जा रही है या 'वृद्धि दर' में वृद्धि / कमी पूछी जा रही है।

Q.2) निम्नलिखित में से कौन मानव पूंजी में संवृद्धि कर सकता है?

1. शिक्षा में निवेश
2. नौकरी में प्रशिक्षण
3. प्रवास (Migration)

नीचे दिए गए कूट का उपयोग करके सही उत्तर चुनें

a) केवल 1
b) केवल 1 और 2
c) केवल 1 और 3
d) उपरोक्त सभी

Q.2) Solution (d)

कथन 1	कथन 2	कथन 3
सत्य	सत्य	सत्य
शिक्षा में निवेश बेहतर कौशल की ओर ले जाता है तथा इस प्रकार मानव पूंजी निर्माण में जुड़ जाता है।	नौकरी में प्रशिक्षण भी बेहतर कौशल की ओर जाता है तथा इस प्रकार मानव पूंजी निर्माण में जुड़ जाता है	लोगों का प्रवासन भी मानव पूंजी निर्माण जोड़ता है क्योंकि यह एक व्यक्ति के निष्क्रिय और अविकसित कौशल के उपयोग की सुविधा प्रदान करता है

मानव पूंजी को निम्न द्वारा संवर्धित किया जा सकता है

- शिक्षा में निवेश
- स्वास्थ्य में निवेश
- नौकरी में प्रशिक्षण
- प्रवास
- सूचना (Information)

Q.3) भारत में सकल राष्ट्रीय उत्पाद (Gross National Product) है

a) देश के केवल निवासी और अनिवासी नागरिकों की आय
b) किसी देश के केवल निवासी नागरिकों की आय
c) भारतीय क्षेत्र में रहने वाले निवासी नागरिकों और विदेशियों दोनों की आय
d) निवासी, गैर-निवासी नागरिकों और विदेशियों की आय जो भारतीय क्षेत्र के भीतर रहते हैं

Q.3) Solution (a)
GNP (सकल राष्ट्रीय उत्पाद)

- यहाँ "राष्ट्रीय" शब्द का अर्थ किसी देश के सभी नागरिकों से है
- यह किसी देश के नागरिकों द्वारा दी जाने वाली अंतिम वस्तुओं और सेवाओं के कुल उत्पादन का समग्र/ कुल मूल्य होता है, जो एक निश्चित अवधि के दौरान होता है।
- यह किसी देश के निवासी और अनिवासी दोनों नागरिकों की आय पर विचार करता है, जबकि विदेशियों की आय, जो देश की भौगोलिक सीमा के भीतर होती है, को बाहर रखा जाता है।

Q.4) निम्न में से किसे अंतिम उत्पाद (Final Goods) माना जाता है?

1. एक डॉक्टर की सेवाएं
2. ग्राहकों की सेवा के लिए एक रेस्तरां द्वारा खरीदी गई सब्जियां
3. एक कंपनी द्वारा निवेश के रूप में खरीदी गई मशीन

नीचे दिए गए कूट का उपयोग करके सही उत्तर चुनें

a) केवल 1
b) केवल 1 और 3
c) इनमें से कोई भी नहीं
d) उपरोक्त सभी

Q.4) Solution (b)
Elimination:
दूसरे कथन को आसानी से समाप्त किया जा सकता है क्योंकि रेस्तरां अंतिम उपभोक्ता नहीं हैं। वे सब्जियों के लिए मूल्य (खाना पकाने और परोसने से) जोड़ते हैं और ग्राहकों से शुल्क लेते हैं।

कथन 1	कथन 2	कथन 3
सत्य	असत्य	सत्य
एक डॉक्टर की सेवा को उपभोक्ता के लिए अंतिम उत्पाद	एक रेस्तरां द्वारा खरीदी गई सब्जियों को मध्यवर्ती उत्पाद माना जाता है।	किसी कंपनी द्वारा खरीदे गए पूंजीगत सामान को अंतिम

माना जाता है।		उत्पाद माना जाता है।

- एक वस्तु, जो अंतिम उपयोग के लिए होती है तथा आगे उत्पादन या परिवर्तनों के किसी भी अन्य चरण से नहीं गुजरती है, इसे अंतिम उत्पाद कहा जाता है।
- अंतिम उत्पाद दो प्रकार के होते हैं -
  - कंपनियों द्वारा निवेश के रूप में खरीदी गयी पूंजीगत वस्तुएं (जैसे मशीनरी)।
  - घरों द्वारा अंतिम उपभोग के लिए उपयोग की जाने वाली वस्तुएं।
- उपभोक्ता अंतिम वस्तु फिर से विभाजित होते हैं
  - टिकाऊ - टीवी, कार आदि।
  - अर्ध-टिकाऊ - कपड़े, जूते आदि।
  - गैर-टिकाऊ - दूध, रोटी आदि।
  - सेवाएँ - शिक्षकों, डॉक्टरों आदि की।

Q.5) भारत में राष्ट्रीय आय (NI) एक शब्द है, जिसका प्रयोग किया जाता है

a) बाजार लागत पर शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद
b) कारक लागत पर सकल राष्ट्रीय उत्पाद
c) कारक लागत पर शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद
d) बाजार लागत पर शुद्ध घरेलू उत्पाद

Q.5) Solution (a)
राष्ट्रीय आय (National Income)

- पहले, राष्ट्रीय आय, शब्द का प्रयोग कारक लागत पर शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद (NNPFC) के लिए किया जाता था।
- जनवरी 2015 से, सीएसओ ने बाजार मूल्य पर इसकी गणना करने के लिए स्विच किया है।
- एनएनपी = जीएनपी - मूल्यह्रास

Q.6) वास्तविक (Real) और नाममात्र (Nominal) जीडीपी के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें

1. आधार वर्ष में वस्तुओं एवं सेवाओं की कीमत का उपयोग करके वास्तविक जीडीपी की गणना की जाती है
2. नाममात्र जीडीपी की गणना उस विशेष वर्ष में वस्तु एवं सेवाओं की कीमत का उपयोग करके की जाती है

नीचे दिए गए कूट का उपयोग करके सही उत्तर चुनें

a) केवल 1
b) केवल 2
c) 1 और 2 दोनों
d) न तो 1 और न ही 2

Q.6) Solution (c)

कथन 1	कथन 2
सत्य	सत्य

वास्तविक जीडीपी स्थिर मूल्य (constant price) पर राष्ट्रीय आय है।	नाममात्र जीडीपी मौजूदा कीमत (current price) पर राष्ट्रीय आय है।

वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद (Real GDP)

- स्थिर मूल्य पर राष्ट्रीय आय = Q*P
- जहां Q किसी विशेष वर्ष में वस्तुओं और सेवाओं की मात्रा है
- P आधार वर्ष का मूल्य है (स्थिर मूल्य)

नाममात्र जीडीपी (Nominal GDP)

- वर्तमान मूल्य पर राष्ट्रीय आय = Q*P
- जहां Q किसी विशेष वर्ष में वस्तुओं और सेवाओं की मात्रा है
- P उस विशेष वर्ष में वस्तुओं और सेवाओं का मूल्य (वर्तमान मूल्य) है

Q.7) निम्नलिखित गतिविधियों में से कौन एक अर्थव्यवस्था में द्वितीयक क्षेत्र का गठन करती है

1. खनन (Mining)
2. निर्माण (Construction)
3. विनिर्माण (Manufacturing)

नीचे दिए गए कूट का उपयोग करके सही उत्तर चुनें

a) केवल 1 और 3
b) केवल 2 और 3
c) केवल 3
d) उपरोक्त सभी

Q.7) Solution (b)
प्राथमिक क्षेत्रक (Primary Sector)

- कृषि
- खनन
- वानिकी
- चराई
- शिकार करना और एकत्रित करना
- मछली पकड़ना
- उत्खनन (Quarrying)

माध्यमिक क्षेत्रक (Secondary Sector)

- विनिर्माण
- प्रसंस्करण
- निर्माण

Q.8) मानव विकास सूचकांक (HDI) के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें।

1. यह संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम द्वारा तैयार एक सूचकांक है

2. मूल आयाम - लंबा एवं स्वस्थ जीवन, शिक्षा तथा जीवन जीने का एक सभ्य स्तर है

नीचे दिए गए कूट का उपयोग करके सही उत्तर चुनें

a) केवल 1
b) केवल 2
c) 1 और 2 दोनों
d) न तो 1 और न ही 2

Q.8) Solution (c)

कथन 1	कथन 2
सत्य	सत्य
यह संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम द्वारा तैयार एक सूचकांक है।	मूल आयाम - लंबा और स्वस्थ जीवन, शिक्षा तथा जीवन जीने का एक सभ्य स्तर है।

- बुनियादी आयामों निम्न द्वारा निर्धारित किया जाता है -
- लंबा एवं स्वस्थ जीवन - जन्म के समय जीवन प्रत्याशा द्वारा मापा जाता है।
- शिक्षा तक पहुंच - स्कूल में प्रवेश की उम्र में बच्चों के स्कूली शिक्षा के वर्ष तथा वयस्क आबादी के स्कूली शिक्षा के वर्षों से मापा जाता है।
- जीवन जीने का एक सभ्य स्तर - देश के मूल्य स्तर के लिए समायोजित प्रति व्यक्ति सकल राष्ट्रीय आय द्वारा मापा जाता है।

Q.9) वह वस्तु, जिसकी क़ीमत बढ़ाने पर मांग बढ़ जाती है, क्योंकि उसकी विशेष प्रकृति तथा पदस्थिति के प्रतीक के रूप में मानी जाती है

a) गिफेन वस्तुएं
b) वेब्लेन वस्तुएं
c) विलासिता की वस्तुएं
d) निम्न कोटि की वस्तुएं

Q.9) Solution (b)

- वेब्लेन (Veblen) और गिफेन (Giffen) दोनों सामान मानक आर्थिक और उपभोक्ता मांग सिद्धांत को परिभाषित करते हैं।
- वेब्लेन वस्तु - एक वस्तु, जिसकी मांग बढ़ जाती है, जब कीमतें बढ़ जाती है क्योंकि लोगों को लगता है कि इसकी उच्च कीमत उच्च पदस्थिति को दर्शाती है।
- गिफेन वस्तु - एक गिफेन वस्तु एक कम आय, गैर-लक्जरी उत्पाद है जिसमें बहुत कम सीमित विकल्प होते हैं। चूंकि गिफेन वस्तु के लिए सीमित विकल्प हैं, इसलिए कीमत बढ़ने पर भी उपभोक्ता गिफेन वस्तु को खरीदने के लिए तैयार रहते हैं।

Q.10) भारतीय अर्थव्यवस्था के संदर्भ में, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें

1. पिछले पाँच वर्षों में भारत के GVA (सकल मूल्य वर्धित) में सेवा क्षेत्र का हिस्सा, लगातार बढ़ा है
2. पिछले पांच वर्षों में भारत के GVA (सकल मूल्य वर्धित) में प्राथमिक क्षेत्र का हिस्सा लगातार घटा है

नीचे दिए गए कूट का उपयोग करके सही विवरण चुनें

a) केवल 1

b) केवल 2
c) 1 और 2 दोनों
d) न तो 1 और न ही 2

Q.10) Solution (a)

कथन 1	कथन 2
सत्य	असत्य
पिछले पाँच वर्षों में सेवा क्षेत्र की हिस्सेदारी में लगातार वृद्धि हुई है	वित्त वर्ष 15-16 में प्राथमिक क्षेत्र का हिस्सा 17.7% था। वित्त वर्ष 16-17 में यह बढ़कर 17.9 हो गया तथा फिर वित्त वर्ष 17-18 में घटकर 17.1 रह गया। इस प्रकार इसमें लगातार गिरावट नहीं आई है। वित्त वर्ष 18-19 में यह बढ़कर 18.57 हो गया है।

Q.11) अगर स्वचालन (automation) शुरू करने के कारण कुछ मैनुअल मजदूरों को कंपनी से निकाल दिया जाता है, तो वे किस तरह की बेरोजगारी का सामना करते हैं?

a) प्रच्छन्न बेरोजगारी
b) संरचनात्मक बेरोजगारी
c) छिपी हुई बेरोजगारी
d) घर्षणात्मक बेरोजगारी

Q.11) Solution (b)

- बेरोजगारी और उपलब्ध नौकरियों के बीच कौशल के एक असंतुलन के कारण संरचनात्मक बेरोजगारी होती है।
- संरचनात्मक बेरोजगारी आमतौर पर तकनीकी परिवर्तन के कारण होती है। जब नई तकनीकों को प्रस्तुत किया जाता है, तो कुछ नौकरियों और कौशल को मशीनों द्वारा प्रतिस्थापित किया जा सकता है, एक प्रक्रिया जिसे स्वचालन (automation) कहा जाता है।

Q.12) प्रधानमंत्री युवा योजना के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें

1. इसका उद्देश्य युवाओं में उद्यमशीलता को बढ़ावा देने के लिए एक सक्षम पारिस्थितिकी तंत्र बनाना है
2. इसे युवा मामले और खेल मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया गया है

नीचे दिए गए कूट का उपयोग करके सही उत्तर चुनें

a) केवल 1
b) केवल 2
c) 1 और 2 दोनों
d) न तो 1 और न ही 2

Q.12) Solution (a)

Elimination

यदि आपको योजना का उद्देश्य पता है, तो कथन 2 को समाप्त किया जा सकता है।

कथन 1	कथन 2
सत्य	असत्य
इसका उद्देश्य युवाओं में उद्यमशीलता को बढ़ावा देने के लिए एक सक्षम पारिस्थितिकी तंत्र बनाना है	इसे कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय द्वारा कार्यान्वित किया जा रहा है।

पीएम युवा योजना

- यह उद्यमिता शिक्षा और प्रशिक्षण पर केन्द्र प्रायोजित योजना है।
- इसे कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय द्वारा कार्यान्वित किया जा रहा है।
- इस योजना का उद्देश्य उद्यमिता शिक्षा और प्रशिक्षण को बढ़ावा देने के माध्यम से उद्यमिता विकास के लिए एक सक्षम पारिस्थितिकी तंत्र बनाना तथा उद्यमशीलता सहायता नेटवर्क तक आसान पहुंच और समावेशी विकास के लिए सामाजिक उद्यमों को बढ़ावा देना है।

Q.13) निम्नलिखित वस्तुओं पर विचार करें

1. चारागाह भूमि
2. स्ट्रीट लाइट
3. पुलिस की सेवा

उपरोक्त वस्तुओं को प्रदान करने के लिए किसकी अवसर लागत (opportunity cost) शून्य है?

a) केवल 1
b) केवल 1 और 3
c) केवल 2 और 3
d) उपरोक्त सभी

Q.13) Solution (a)

कथन 1	कथन 2	कथन 3
सत्य	असत्य	असत्य
अवसर लागत शून्य है। लेकिन उपभोग में प्रतिद्वंद्विता मौजूद है।	अवसर लागत शून्य नहीं है। उपभोग में प्रतिद्वंद्विता मौजूद नहीं है।	अवसर लागत शून्य नहीं है। उपभोग में प्रतिद्वंद्विता मौजूद नहीं है।

- अवसर लागत एक अर्थशास्त्र संबंधी शब्द है, जो कुछ और चुनने के लिए आपके द्वारा दिए गए मूल्य को दर्शाता है।
- माइक्रोइकॉनॉमिक्स के अनुसार, नि: शुल्क सामान जैसे हवा और सामान्य सामान जैसे मछली / चरागाह भूमि के लिए अवसर लागत शून्य होती है।
- सार्वजनिक वस्तुओं जैसे स्ट्रीट लाइट, पुलिस सेवा, न्यायपालिका सेवा, रक्षा आदि के लिए अवसर लागत शामिल है।
- यदि पुलिस सेवा प्रदान नहीं की जाती तो सरकार स्ट्रीट लाइट पर अधिक पैसा खर्च कर सकती थी। इसी तरह, अगर स्ट्रीट लाइट की जरूरत नहीं है, तो पुलिस बल में अधिक पैसा लगाया जा सकता है। इस प्रकार, एक अवसर लागत शामिल है।

Q.14) कृषि जनगणना 2015-16 के आंकड़ों से पता चलता है कि

1. परिचालन धारकों (operational holding) के औसत आकार में गिरावट आई है
2. महिला परिचालन धारकों का प्रतिशत शेयर बढ़ा है

नीचे दिए गए कूट का उपयोग करके सही उत्तर चुनें

a) केवल 1
b) केवल 2
c) 1 और 2 दोनों
d) न तो 1 और न ही 2

Q.14) Solution (c)

कथन 1	कथन 2
सत्य	सत्य
अस्थायी आंकड़ों (provisional data) के अनुसार, 2010-11 में 1.15 हेक्टेयर की तुलना में 2015-16 में परिचालन होल्डिंग का औसत आकार घटकर 1.08 हेक्टेयर रह गया है।	जनगणना में यह भी पाया गया कि 2010-11 में महिला परिचालकों की प्रतिशत हिस्सेदारी 12.79 प्रतिशत से बढ़कर 2015-16 में 13.87 प्रतिशत हो गई है।

- 2015-16 की कृषि जनगणना में 2010-11 के आंकड़ों की तुलना में 157.14 मिलियन हेक्टेयर में कुल संचालित क्षेत्र में 1.53 प्रतिशत की गिरावट देखी गई।
- संचालित क्षेत्र के संदर्भ में, महिलाओं की हिस्सेदारी 10.36 प्रतिशत से बढ़कर 11.57 प्रतिशत हो गई।

Q.15) गरीबी उन्मूलन के लिए सरकार ने निम्नलिखित में से कौन से कदम उठाए हैं?

1. राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम
2. प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना
3. महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम

नीचे दिए गए कूट का उपयोग करके सही उत्तर चुनें

a) केवल 1 और 2
b) केवल 1 और 3
c) केवल 2 और 3
d) उपरोक्त सभी

Q.15) Solution (d)

सभी तीनों सरकारी योजनाएँ गरीबी उन्मूलन के अप्रत्यक्ष तरीके हैं। वे गरीबी के दुष्चक्र से निपटती हैं तथा इस तरह इसके उन्मूलन में सहायता करती हैं।

Q.16) भारत में किस प्रकार की कर प्रणाली अपनायी गयी है

a) प्रगतिशील (Progressive)
b) आनुपातिक (Proportional)
c) प्रतिगामी (Regressive)
d) इनमें से कोई भी नहीं

Q.16) Solution (a)

- प्रगतिशील कराधान (Progressive taxation) - एक प्रगतिशील कर, एक ऐसा कर होता है, जो उच्च आय वाले लोगों की तुलना में, कम आय वाले लोगों पर कम कर की दर लगाता है। भारत इस प्रणाली का अनुसरण करता है।
- आनुपातिक कर (Proportional tax) - एक आनुपातिक कर एक आयकर प्रणाली है जहां, कर का एक समान प्रतिशत, उनकी आय की परवाह किए बिना, सभी करदाताओं पर लगाया जाता है।
- प्रतिगामी कर (Regressive tax) - एक प्रतिगामी कर एक ऐसा कर है, जो कम आय वालों से अधिक आय वाले लोगों की तुलना में अधिक प्रतिशत कर लेता है।

Q.17) भारत के कर संग्रह के संबंध में, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें

1. व्यक्तिगत आय कर का हिस्सा पिछले पांच वर्षों से लगातार बढ़ा है
2. वर्ष 2019-20 के लिए निगम कर (Corporate Tax) की हिस्सेदारी, वस्तु एवं सेवा कर की हिस्सेदारी से अधिक है

नीचे दिए गए कूट का उपयोग करके सही उत्तर चुनें

a) केवल 1
b) केवल 2
c) 1 और 2 दोनों
d) न तो 1 और न ही 2

Q.17) Solution (a)

कथन 1	कथन 2
सत्य	असत्य
व्यक्तिगत आय कर का हिस्सा पिछले पांच वर्षों से लगातार बढ़ा है	निगम कर की हिस्सेदारी वर्ष 2019-20 के लिए वस्तु एवं सेवा कर की हिस्सेदारी से कम है

व्यक्तिगत आय कर का हिस्सा –

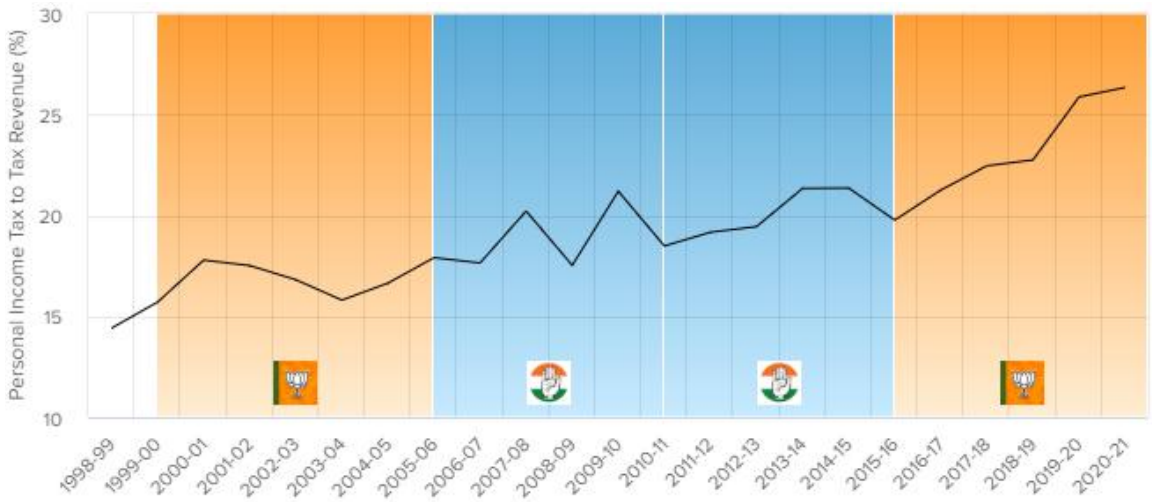

जीएसटी की हिस्सेदारी, निगम कर की हिस्सेदारी से अधिक हो गयी है। प्रथम संशोधित अनुमान के अनुसार, कुल निगम कर संग्रह 610,500 करोड़ है, जबकि कुल जीएसटी संग्रह 612,327 करोड़ है।

Q.18) आर्थिक वृद्धि (Growth) एवं विकास (Development) के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें

1. वृद्धि मात्रात्मक है जबकि विकास गुणात्मक है
2. विकास के लिए आर्थिक संवृद्धि आवश्यक है

नीचे दिए गए कूट का उपयोग करके सही उत्तर चुनें

a) केवल 1
b) केवल 2
c) 1 और 2 दोनों
d) न तो 1 और न ही 2

Q.18) Solution (c)

कथन 1	कथन 2
सत्य	सत्य
वृद्धि (Growth) एक मात्रात्मक कारक है। यह सकारात्मक या नकारात्मक हो सकती है। विकास (Development) एक गुणात्मक कारक है और हमेशा सकारात्मक मूल्य होता है।	मात्र संवृध्दि विकास की गारंटी नहीं देती है, विकास के लिए संवृद्धि आवश्यक है यानी आर्थिक संवृद्धि आवश्यक है, लेकिन विकास के लिए अपर्याप्त स्थिति है।

Q.19) निम्नलिखित कथनों पर विचार करें

1. वास्तविक जीडीपी गणना मुद्रास्फीति को ध्यान में रखती है, जबकि नाममात्र जीडीपी नहीं
2. नाममात्र जीडीपी, वास्तविक जीडीपी की तुलना में अक्सर अधिक होती है
3. भारत में जीडीपी की गणना केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय द्वारा की जाती है

उपरोक्त कथनों में से कौन सा सही है / हैं?

a) केवल 1 और 2

b) केवल 1 और 3
c) केवल 2 और 3
d) उपरोक्त सभी

Q.19) Solution (c)

कथन 1	कथन 2	कथन 3
सत्य	सत्य	सत्य
वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) एक मुद्रास्फीति-समायोजित उपाय है, जो किसी भी वर्ष में अर्थव्यवस्था द्वारा उत्पादित सभी वस्तुओं और सेवाओं के मूल्य को दर्शाता है, जिसे आधार-वर्ष की कीमतों में व्यक्त किया जाता है, तथा अक्सर इसे "स्थिर-मूल्य", "मुद्रास्फीति समायोजित" जीडीपी, या "स्थिर डॉलर जीडीपी" कहा जाता है। नाममात्र जीडीपी के विपरीत, वास्तविक जीडीपी मूल्य स्तरों में परिवर्तन के लिए उत्तरदायी है और आर्थिक विकास का अधिक सटीक आंकड़ा प्रदान करती है।	नाममात्र जीडीपी अपने माप में मौजूदा कीमतों का उपयोग करके वस्तुओं और सेवाओं के मूल्य का एक व्यापक आर्थिक मूल्यांकन है। जबकि नाममात्र जीडीपी परिभाषा के अनुसार मुद्रास्फीति को दर्शाता है, वास्तविक जीडीपी मुद्रास्फीति के लिए समायोजित करने के लिए जीडीपी डिफ्लेटर का उपयोग करता है, इस प्रकार केवल वास्तविक उत्पादन में परिवर्तन को दर्शाता है। चूंकि मुद्रास्फीति आम तौर पर एक सकारात्मक संख्या है, इसलिए किसी देश की नाममात्र जीडीपी आम तौर पर अपनी वास्तविक जीडीपी से अधिक होती है।	भारत में जीडीपी की गणना केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय द्वारा की जाती है यह त्रैमासिक आधार पर प्रकाशित होता है तथा 60 दिनों के अंतराल के साथ आता है

Q.20) प्रधानमंत्री श्रम योगी मान-धन योजना के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें

1. इसे श्रम और रोजगार मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया गया है
2. असंगठित क्षेत्र का कोई भी श्रमिक योजना में नामांकन कर सकता है

नीचे दिए गए कूट का उपयोग करके सही उत्तर चुनें

a) केवल 1
b) केवल 2
c) 1 और 2 दोनों
d) न तो 1 और न ही 2

Q.20) Solution (a)

कथन 1	कथन 2
सत्य	सत्य
श्रम और रोजगार मंत्रालय द्वारा प्रधानमंत्री श्रम योगी मान धन योजना शुरू की गई है।	संगठित क्षेत्र के सभी श्रमिक नामांकन नहीं कर सकते। कुछ पात्रता मानदंड हैं।

- यह असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों के लिए 3,000 रुपये मासिक पेंशन का आश्वासन देती है।
- पात्रता -
    - 15,000 प्रति माह से कम आय।
    - NPS, EPFO या ESIC के तहत कवर नहीं किया जाना चाहिए
    - आयु 18-40 वर्ष के बीच होनी चाहिए।
- यह एक स्वैच्छिक और अंशदायी योजना है।

Q.21) निम्नलिखित में से कौन सा ग्राफ, किसी समाज में असमानता का स्तर दर्शाता है

a) लोरेंज वक्र
b) फिलिप्स वक्र
c) एंजेल वक्र
d) लाफ़र वक्र

Q.21) Solution (a)

- लोरेंज वक्र एक ऐसा ग्राफ है, जिसका उपयोग अर्थशास्त्र में आय के प्रसार या धन में असमानता दर्शाने के लिए किया जाता है।
- गिनी सूचकांक की गणना लोरेंज वक्र से की जा सकती है।
- लोरेंज वक्र पर x- अक्ष आम तौर पर कुल जनसंख्या के हिस्से या प्रतिशत को दर्शाता है, तथा y-अक्ष कुल आय या धन के हिस्से को दर्शाता है।

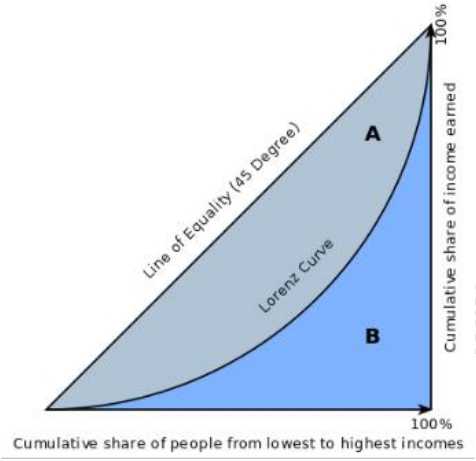

Q.22) निम्नलिखित में से कौन सी समिति गरीबी के आकलन से संबंधित है?

a) लकड़वाला समिति
b) अलघ समिति
c) सक्सेना समिति
d) उपर्युक्त सभी

Q.22) Solution (d)

- सभी 3 समितियां गरीबी के आकलन से संबंधित हैं
- **लकड़वाला समिति -** 1993 में भारत सरकार द्वारा एक टास्क फोर्स का गठन किया गया, जिसके अध्यक्ष के रूप में डी.टी. लकड़वाला थे। इसने सिफारिश की कि उपभोग व्यय की गणना पहले की तरह कैलोरी के उपभोग के आधार पर की जानी चाहिए।

- **अलघ समिति** - 1979 में योजना आयोग द्वारा गरीबी आकलन के लिए गठित एक टास्क फोर्स, जिसकी अध्यक्षता वाई.के. अलघ ने की थी। इसने पोषण संबंधी आवश्यकताओं के आधार पर ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों के लिए गरीबी रेखा का निर्माण किया।
- **एन.सी. सक्सेना समिति** - ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा बीपीएल जनगणना के लिए उपयुक्त पद्धति पर सलाह देने के लिए, न कि गरीबी के आकलन के लिए स्थापित की गई थी। लेकिन इसने गरीबी आकलन से संबंधी सिफारिशें भी दी थीं।

Q.23) यदि कोई व्यक्ति, अपनी नौकरी को बेहतर नौकरी की तलाश में छोड़ता है, तो उसे किस तरह की बेरोजगारी का सामना करना पड़ता है?

a) प्रच्छन्न बेरोजगारी
b) संरचनात्मक बेरोजगारी
c) छिपी हुई बेरोजगारी
d) घर्षणात्मक बेरोजगारी

Q.23) Solution (d)
घर्षणात्मक बेरोजगारी:

- घर्षण बेरोजगारी, जिसे खोज बेरोजगारी भी कहा जाता है, नौकरियों के बीच समय अंतराल को संदर्भित करता है, जब कोई व्यक्ति नई नौकरी की तलाश कर रहा है या नौकरियों के बीच स्विच कर रहा है।
- दूसरे शब्दों में, एक कर्मचारी को नई नौकरी की तलाश करने या मौजूदा से नई नौकरी में शिफ्ट करने के लिए समय की आवश्यकता होती है, यह अपरिहार्य समय देरी घर्षण बेरोजगारी का कारण बनती है।
- इसे अक्सर स्वैच्छिक बेरोजगारी के रूप में माना जाता है क्योंकि यह नौकरी की कमी के कारण नहीं होता है, लेकिन वास्तव में, श्रमिकों ने बेहतर अवसरों की तलाश में अपनी नौकरी छोड़ी होती है।

Q.24) गरीबी आकलन पर तेंदुलकर समिति के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें

1. गरीबी के मौजूदा आधिकारिक उपाय तेंदुलकर गरीबी रेखा पर आधारित हैं
2. यह गरीबी का आकलन करते हुए स्वास्थ्य और शिक्षा पर निजी व्यय को शामिल करता है
3. उपभोग व्यय की गणना कैलोरी की खपत के आधार पर की जाती है

नीचे दिए गए कूट का उपयोग करके सही उत्तर चुनें

a) केवल 1
b) केवल 1 और 2
c) केवल 1 और 3
d) ऊपर के सभी

Q.24) Solution (b)

कथन 1	कथन 2	कथन 3
सत्य	सत्य	असत्य
गरीबी के मौजूदा आधिकारिक उपाय तेंदुलकर गरीबी रेखा पर	यह गरीबी का आकलन करते हुए स्वास्थ्य और शिक्षा पर निजी	कैलोरी उपभोग आधारित गरीबी अनुमान से एक परिवर्तन - इसने

आधारित हैं।	व्यय को शामिल करता है	अनाज, दाल, दूध, शिक्षा आदि वस्तुओं की खपत पर अपनी गणना आधारित की।

तेंदुलकर समिति

- सुरेश तेंदुलकर की अध्यक्षता में 2009 में योजना आयोग द्वारा एक विशेषज्ञ समूह का गठन किया गया था, जिसने गरीबी आकलन के लिए कार्यप्रणाली की समीक्षा की तथा पिछली विधियों की निम्न कमियों को दूर किया।
- तेंदुलकर समिति ने 2004-05 के लिए गरीबी रेखा की गणना एक स्तर पर की थी, जो क्रय शक्ति समानता (पीपीपी) में 33 रुपये प्रतिदिन थी।

Q.25) सतत विकास लक्ष्यों भारत सूचकांक के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें

1. इसे सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के सहयोग से नीति आयोग द्वारा किया जाता है
2. यह सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की सामाजिक, आर्थिक और पर्यावरणीय स्थिति पर एक समग्र दृष्टिकोण प्रदान करता है

नीचे दिए गए कूट का उपयोग करके सही उत्तर चुनें

a) केवल 1
b) केवल 2
c) 1 और 2 दोनों
d) न तो 1 और न ही 2

Q.25) Solution (c)

कथन 1	**कथन 2**
सत्य	**सत्य**
इसे सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के सहयोग से नीति आयोग द्वारा किया जाता है।	एसडीजी इंडिया इंडेक्स का उद्देश्य देश तथा उसके राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों की सामाजिक, आर्थिक और पर्यावरणीय स्थिति पर समग्र दृष्टिकोण प्रदान करना है।

एसडीजी इंडिया इंडेक्स

- इसे सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के सहयोग से नीति आयोग द्वारा किया जाता है।
- सूचकांक 62 राष्ट्रीय संकेतकों के एक सेट पर सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों (UTs) की प्रगति को ट्रैक करता है।
- एसडीजी इंडिया इंडेक्स का उद्देश्य देश तथा उसके राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की सामाजिक, आर्थिक और पर्यावरणीय स्थिति पर समग्र दृष्टिकोण प्रदान करना है।
- हिमाचल प्रदेश, केरल और तमिलनाडु SDG लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए शीर्ष 3 में हैं।
- असम, बिहार और यूपी रैंकिंग में सबसे नीचे हैं।

Q.26) भारत में गरीबी का आकलन किसके द्वारा किया जाता है

a) नीति आयोग
b) राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण कार्यालय
c) रंगराजन समिति
d) सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय

Q.26) Solution (a)

- भारत में गरीबी का आकलन **नीति आयोग की टास्क फोर्स** द्वारा किया जाता है।
- नीति आयोग द्वारा गरीबी रेखा की गणना सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय (MOSPI) के तहत राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण कार्यालय द्वारा संग्रहित किए गए डेटा पर आधारित है।
- इससे पहले, योजना आयोग भारत में गरीबी रेखा की गणना के लिए उत्तरदायी था।

Q.27) राष्ट्रीय ग्रामीण आर्थिक परिवर्तन परियोजना के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें

1. यह ग्रामीण गरीब महिलाओं और युवाओं के लिए उद्यम विकास कार्यक्रमों का समर्थन करता है
2. यह दीनदयाल अंत्योदय योजना - राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन का एक हिस्सा है

नीचे दिए गए कूट का उपयोग करके सही उत्तर चुनें

a) केवल 1
b) केवल 2
c) 1 और 2 दोनों
d) न तो 1 और न ही 2

Q.27) Solution (c)

कथन 1	**कथन 2**
सत्य	**सत्य**
यह ग्रामीण गरीब महिलाओं और युवाओं के लिए उद्यम विकास कार्यक्रमों का समर्थन करता है	यह दीनदयाल अंत्योदय योजना - राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन का एक हिस्सा है

राष्ट्रीय ग्रामीण आर्थिक परिवर्तन परियोजना (NRETP)

- यह ग्रामीण गरीब महिलाओं और युवाओं के लिए उद्यम विकास कार्यक्रमों का समर्थन करता है।
- सबसे गरीब और सबसे कमजोर समुदायों तथा उनके वित्तीय समावेशन को लक्षित करने पर विशेष जोर।
- यह युवाओं में कौशल विकास का भी समर्थन करेगा।
- यह दीनदयाल अंत्योदय योजना - राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन का एक हिस्सा है।
- परियोजना के लिए विश्व बैंक द्वारा ऋण सहायता प्रदान की गई है।

Q.28) निश्चित अवधि के रोजगार (Fixed-term Employment) के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें

1. श्रमिक के प्रदर्शन के अनुसार अनुबंध को नवीनीकृत या समाप्त किया जा सकता है
2. श्रमिक स्थायी श्रमिकों के लिए उपलब्ध लाभों के हकदार होंगे
3. वर्तमान में, निश्चित अवधि के रोजगार की अनुमति केवल कपड़ा क्षेत्र में है

नीचे दिए गए कूट का उपयोग करके विवरण चुनें

a) केवल 1
b) केवल 1 और 2
c) केवल 2 और 3
d) उपरोक्त सभी

Q.28) Solution (b)

कथन 1	कथन 2	कथन 3
सत्य	सत्य	असत्य
श्रमिकों के प्रदर्शन के अनुसार अनुबंध को नवीनीकृत या समाप्त किया जा सकता है।	श्रमिक स्थायी श्रमिकों के लिए उपलब्ध लाभों के हकदार होंगे।	निश्चित अवधि के रोजगार (फिक्स्ड-टर्म रोजगार) सभी क्षेत्रों के लिए लागू है।

- निश्चित अवधि के रोजगार के तहत, एक कंपनी या एक उद्यम एक विशिष्ट अवधि के लिए एक कर्मचारी को काम पर रखता है।
- श्रमिक के प्रदर्शन के अनुसार, अनुबंध को नवीनीकृत या समाप्त किया जा सकता है
- FTE के तहत, श्रमिक स्थायी श्रमिकों के लिए उपलब्ध लाभों के हकदार होंगे।
- इस प्रकार, कॉन्ट्रैक्ट वर्कर्स, अगर FTE वर्कर्स का स्थान लेते हैं, तो वैधानिक लाभों के संदर्भ में लाभ पाने के अधिकारी होते हैं
- मार्च 2018 में, केंद्र ने सभी क्षेत्रों के लिए निश्चित अवधि के रोजगार (FTE) को अधिसूचित किया। इससे पहले, यह केवल कपड़ा क्षेत्र के लिए लागू था।

Q.29) संकल्प योजना (Sankalp Scheme) के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें

1. इसका उद्देश्य राष्ट्रीय कौशल विकास मिशन के जनादेश (mandate) को लागू करना है
2. यह विश्व बैंक के सहयोग से एक केंद्रीय क्षेत्र की योजना है

नीचे दिए गए कूट का उपयोग करके सही उत्तर चुनें

a) केवल 1
b) केवल 2
c) 1 और 2 दोनों
d) न तो 1 और न ही 2

Q.29) Solution (a)

कथन 1	कथन 2
सत्य	असत्य
इसका उद्देश्य राष्ट्रीय कौशल विकास मिशन (NSDM) के जनादेश को लागू करना है।	यह विश्व बैंक के सहयोग से केंद्र प्रायोजित योजना है।

- आजीविका के लिए कौशल अधिग्रहण और ज्ञान जागरूकता (SANKALP) विकेंद्रीकृत योजना और गुणवत्ता में सुधार पर विशेष ध्यान देने के साथ कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय (MSDE) का एक परिणाम उन्मुख कार्यक्रम है।

Q.30) गरीबी और साझा समृद्धि रिपोर्ट (Poverty and Shared Prosperity Report) किसके द्वारा प्रकाशित की जाती है

a) अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष
b) व्यापार और विकास पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन
c) विश्व आर्थिक मंच
d) विश्व बैंक

Q.30) Solution (d)

- गरीबी और साझा समृद्धि, वैश्विक गरीबी और साझा समृद्धि के रुझानों पर अनुमान प्रदान करती है।
- 2018 संस्करण - गरीबी की पहेली को एक साथ जोड़ना (Piecing Together the Poverty Puzzle) — गरीबी को परिभाषित करने और मापने के तरीकों को बताता है
- यह एक बहुआयामी गरीबी उपाय का परिचय देता है, जो घरेलू उपभोग और प्रति दिन प्रति व्यक्ति 1.90 डॉलर की अंतरराष्ट्रीय गरीबी रेखा पर आधारित है।
- यह विश्व बैंक द्वारा प्रकाशित किया जाता है।

Q.31) वैश्विक बहुआयामी गरीबी सूचकांक (Global Multidimensional Poverty Index) के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें

1. यह ऑक्सफोर्ड गरीबी और मानव विकास पहल (OPHI) तथा संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम द्वारा विकसित किया गया है
2. भारत में, इसकी नवीनतम रिपोर्ट के अनुसार बहुआयामी गरीबी में रहने वाले लोगों की सबसे बड़ी संख्या है

नीचे दिए गए कूट का उपयोग करके सही उत्तर चुनें

a) केवल 1
b) केवल 2
c) 1 और 2 दोनों
d) न तो 1 और न ही 2

Q.31) Solution (c)

कथन 1	कथन 2
सत्य	सत्य
वैश्विक MPI को 2010 में UNDP की प्रमुख मानव विकास रिपोर्ट में शामिल करने के लिए संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम (UNDP) के साथ OPHI द्वारा विकसित किया गया था।	वैश्विक एमपीआई 2018 के अनुसार, भारत में सबसे अधिक संख्या में लोग बहुआयामी गरीबी में रहते हैं।

- वैश्विक बहुआयामी गरीबी सूचकांक (MPI) 100 से अधिक विकासशील देशों को कवर करने वाली तीव्र बहुआयामी गरीबी का एक अंतरराष्ट्रीय उपाय है।
- MPI व्यक्तिगत स्तर पर गरीबी का आकलन करता है। यदि किसी को तीसरे अथवा दस से अधिक संकेतकों (भारांक) में वंचित किया जाता है, तो वैश्विक सूचकांक उन्हें 'एमपीआई गरीब' के रूप में चिन्हित करता है।

Q.32) अटल टिंकरिंग लैब् (Atal Tinkering Labs) का लक्ष्य है

a) कक्षा 6 से 12 वीं के छात्रों के बीच नवाचार को बढ़ावा देना
b) देश में फास्ट ट्रैक अनुसंधान और शैक्षणिक अवसंरचना विकास
c) उच्च शिक्षा एजेंसियों में नवाचार की संस्कृति को बढ़ावा देना
d) वैश्विक विश्वविद्यालयों के साथ संयुक्त अनुसंधान को बढ़ावा देना

Q.32) Solution (a)

- अटल टिंकरिंग लैब् (एटीएल) 1500 वर्ग फुट में नामित, अत्याधुनिक सुविधाओं के साथ स्थान, नवाचार के लिए अलग से समर्पित हैं।
- अटल टिंकरिंग लैब का उद्देश्य कक्षा 6 से 12 वीं के छात्रों के बीच नवाचार को प्रोत्साहित करना है।
- टिंकरिंग लैब एक ऐसा कार्यक्षेत्र है, जहाँ युवा दिमाग अपने विचारों को हाथों-हाथ कर सकते हैं, यहां स्वयं विचारों को लैब के माध्यम से एक रूप दे सकते हैं तथा नवाचार कौशल सीख सकते हैं।
- यह नीति आयोग के अटल नवाचार मिशन के तहत मुख्य घटकों में से एक है।

Q.33) निम्नलिखित में से कौन सा उपाय, भारत को जनसांख्यिकीय लाभांश (demographic dividend) का पूर्ण लाभ प्राप्त करने में मदद करेगा

1. कौशल विकास को बढ़ावा देना
2. उच्च शिक्षा का निजीकरण
3. बालिका शिक्षा को बढ़ावा देना

नीचे दिए गए कूट का उपयोग करके उत्तर चुनें

a) केवल 1 और 2
b) केवल 1 और 3
c) केवल 2 और 3
d) ऊपर के सभी

Q.33) Solution (b)

कथन 1	कथन 2	कथन 3
सत्य	असत्य	सत्य
कौशल विकास को बढ़ावा देने से भारत को जनसांख्यिकीय लाभांश का पूर्ण लाभ प्राप्त करने में मदद मिलेगी।	उच्च शिक्षा के निजीकरण के लिए जरूरी नहीं कि इससे बेहतर शैक्षिक परिणाम सामने आएं। इस प्रकार यह नहीं कहा जा सकता है कि उच्च शिक्षा के निजीकरण से बेहतर जनसांख्यिकीय लाभांश प्राप्त होगा	बालिका शिक्षा को बढ़ावा देने से साक्षरता स्तर और रोजगार में सुधार होगा।

Q.34) यू.के. सिन्हा समिति ने हाल ही में किससे संबंधित अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की है?

a) विशेष आर्थिक क्षेत्र नीति
b) एमएसएमई (MSMEs) का कायाकल्प करने के लिए आवश्यक उपाय
c) आधिकारिक आँकड़ों के डेटाबेस की समीक्षा करना तथा उसे पुनः जारी करना
d) वित्तीय प्रौद्योगिकी क्षेत्र

Q.34) Solution (b)

- एमएसएमई की समस्याओं का अध्ययन करने के लिए समिति की अध्यक्षता यू. के. सिन्हा ने की थी।
- यह भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा स्थापित की गयी थी।
- समिति ने घरेलू सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों (MSMEs) के लिए 5000,000 रु. तनावग्रस्त संपत्ति कोष (stressed asset fund) का सुझाव दिया है।
- यह कोष भारतीय रिजर्व बैंक की अनिवार्य पुनर्गठन योजनाओं या एमएसएमई के लिए बैंक के नेतृत्व वाले एनपीए पुनरुद्धार समाधान के साथ मिलकर काम कर सकता है।

Q.35) भारत में असमानता के लिए निम्नलिखित में से कौन से कारक उत्तरदायी हैं?

1. रोजगार विहीन विकास
2. कर-वंचन (Tax evasion)
3. सामाजिक समावेश

नीचे दिए गए कूट का उपयोग करके उत्तर चुनें

a) केवल 1 और 2
b) केवल 1 और 3
c) केवल 2 और 3
d) उपरोक्त सभी

Q.35) Solution (a)

Elimination

सामाजिक समावेशन को आसानी से समाप्त किया जा सकता है क्योंकि समावेशन से और अधिक समान और समावेशी विकास होगा।

- भारत में असमानता के कुछ कारण हैं
  - **कर वंचन,**
  - **बेरोजगारी,**

- संपत्ति के स्वामित्व में असमानता,
- विरासत के नियम,
- पेशेवर प्रशिक्षण की लागत,
- मुद्रास्फीति की दर,
- भ्रष्टाचार और तस्करी,
- अप्रत्यक्ष कराधान का अधिक बोझ
- **सामाजिक बहिष्कार**

Q.36) श्रम शक्ति में महिलाओं की भागीदारी के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें

1. पिछले एक दशक में, शिक्षा की पहुंच में वृद्धि से भारत की महिला श्रम बल भागीदारी दर में वृद्धि हुई है
2. मातृत्व लाभ अधिनियम और कार्यस्थल पर महिलाओं का यौन उत्पीड़न अधिनियम जैसे कानून महिला श्रम बल भागीदारी दर पर सकारात्मक प्रभाव डाल सकते हैं

नीचे दिए गए कूट का उपयोग करके सही उत्तर चुनें

a) केवल 1
b) केवल 2
c) 1 और 2 दोनों
d) न तो 1 और न ही 2

Q.36) Solution (b)

Elimination

महिला श्रम भागीदारी का निम्न स्तर लगातार समाचारों में है। इस प्रकार इसे आसानी से समाप्त किया जा सकता है।

कथन 1	कथन 2
असत्य	सत्य
भारत में महिला श्रम बल की भागीदारी 2005 में 36.7% से घटकर 2017-18 में 23.3% तक ऐतिहासिक रूप से कम हो गई है।	मातृत्व लाभ अधिनियम और कार्यस्थल पर महिलाओं का यौन उत्पीड़न अधिनियम जैसे कानून महिला श्रम बल भागीदारी दर पर सकारात्मक प्रभाव पड़ा हैं।

- भारत में महिला श्रम बल की भागीदारी 2005 में 36.7% से घटकर 2017-18 में 23.3% तक ऐतिहासिक रूप से कम हो गई है।
- सीरिया और इराक सहित विश्व भर के सिर्फ नौ देशों में अब भारत की तुलना में कामकाजी महिलाओं का अनुपात कम है।
- कार्यस्थल पर महिलाओं द्वारा सामना किए जाने वाले मुद्दों को संबोधित करना जैसे कि यौन उत्पीड़न, लैंगिक मज़दूरी में अंतर, गर्भावस्था और मातृत्व के दौरान लचीलापन उनकी कार्यबल भागीदारी दर पर सकारात्मक प्रभाव डाल सकते हैं।
- इस प्रकार, मातृत्व लाभ अधिनियम तथा कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न अधिनियम का महिला श्रम बल भागीदारी दर पर सकारात्मक प्रभाव पड़ा है।

Q.37) आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण 2107-18 (Periodic Labor Force Survey 2107-18) के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें

1. यह केंद्रीय सांख्यिकी संगठन द्वारा जारी एक वार्षिक सर्वेक्षण है
2. सर्वेक्षण विभिन्न राज्यों के लिए केवल बेरोजगारी डेटा प्रदान करता है
3. राज्यों के बीच नागालैंड में सबसे अधिक बेरोजगारी दर है

उपरोक्त कथनों में से कौन सा सही हैं?

a) केवल 1 और 2
b) केवल 2 और 3
c) केवल 1 और 3
d) केवल 3

Q.37) Solution (d)

कथन 1	कथन 2	कथन 3
असत्य	असत्य	सत्य
सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय ने अप्रैल, 2017 के दौरान एक नया नियमित रोजगार-बेरोजगारी सर्वेक्षण, आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण (पीएलएफएस) आरंभ किया है, जिसमें सर्वेक्षण पद्धति, डेटा संग्रह तंत्र और नमूना डिजाइन में कुछ बदलाव किया है। पहले पंचवर्षीय (हर पांच साल में एक बार) एनएसएसओ का रोजगार और बेरोजगारी सर्वेक्षण।	पीएलएफएस को शहरी क्षेत्रों में विभिन्न श्रम बाजार सांख्यिकीय संकेतकों के त्रैमासिक परिवर्तनों को मापने के साथ-साथ ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों के लिए इन संकेतकों के वार्षिक अनुमान उत्पन्न करने के उद्देश्य से आरंभ किया गया है, जिसका उपयोग नीति निर्माण के लिए किया जा सकता है।	गोवा और मणिपुर के बाद नागालैंड में सबसे ज्यादा 21.4% बेरोजगारी दर है मेघालय में सबसे कम 1.5% है

Q.38) प्रधानमंत्री-किसान योजना (PM-KISAN scheme) के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें?

1. यह कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा लागू एक केंद्रीय क्षेत्र की योजना है
2. यह प्रति वर्ष 6,000 रुपये की आय सहायता प्रदान करती है, जिसे देश भर के सभी किसान परिवारों को 2,000 रुपये की तीन समान किस्तों में प्रदान किया जाता है।
3. लाभार्थी किसान परिवारों की पहचान की संपूर्ण जिम्मेदारी राज्य / केन्द्र शासित प्रदेशों की सरकारों पर टिकी हुई है

उपरोक्त कथनों में से कौन सा सही हैं?

a) केवल 1 और 2
b) केवल 2 और 3
c) केवल 1 और 3
d) उपरोक्त सभी

Q.38) Solution (d)

कथन 1	कथन 2	कथन 3
सत्य	सत्य	सत्य
प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि (PM-KISAN) एक केंद्रीय क्षेत्र की योजना है, जिसमें भारत सरकार से 100% वित्त पोषण होता है।	इस योजना के तहत देश भर के सभी किसान परिवारों को प्रत्येक चार महीने में 2,000 रुपये की तीन समान किस्तों में 6,000 रुपये प्रति वर्ष की आय सहायता प्रदान की जाती है। योजना के लिए परिवार की परिभाषा पति, पत्नी और नाबालिग बच्चे हैं। सभी संस्थागत भूमि धारक योजना में शामिल नहीं हैं	लाभार्थी किसान परिवारों की पहचान की पूरी जिम्मेदारी राज्य / केन्द्र शासित प्रदेशों की सरकारों के ऊपर है। फंड सीधे लाभार्थियों के बैंक खातों में स्थानांतरित किया जाता है।

Q.39) अर्थशास्त्र विज्ञान में 2019 का नोबेल मेमोरियल पुरस्कार अभिजीत बनर्जी, एस्थर डफ्लो और माइकल क्रेमर को किस लिए प्रदान किया गया

a) वैश्विक गरीबी को कम करने के लिए उनके प्रयोगात्मक दृष्टिकोण के लिए
b) जलवायु परिवर्तन को दीर्घकालीन आर्थिक विश्लेषण में एकीकृत करना
c) लंबे समय तक चलने वाले आर्थिक विश्लेषण में तकनीकी नवाचारों को एकीकृत करने के लिए
d) व्यवहार अर्थशास्त्र में उनके योगदान के लिए

Q.39) Solution (a)

2019 के अर्थशास्त्र विज्ञान में नोबेल मेमोरियल पुरुस्कार अभिजीत बनर्जी, एस्थर डुफ्लो और माइकल क्रेमर को **"वैश्विक गरीबी को कम करने के लिए उनके प्रयोगात्मक दृष्टिकोण के लिए"** प्रदान किया गया था। उनके प्रयोगात्मक कार्य ने अर्थशास्त्र की संस्कृति को बदल दिया है, विशेष रूप से विकास अर्थशास्त्र को।

इसने गहरी धारणा को बदलने में मदद की कि कैसे व्यक्ति निर्णय लेते हैं और आर्थिक विकास क्या है। इसने कई विकास अर्थशास्त्रियों के काम करने के तरीके को बदल दिया, जहाँ वे काम करते हैं, और वे जिस तरह के लोगों के साथ काम करते हैं।

Q.40) निम्नलिखित में से कौन से विषय आकांक्षी जिला परियोजना (Aspirational District's Programme) में शामिल हैं?

1. स्वास्थ्य और पोषण
2. शिक्षा
3. कृषि और जल संसाधन
4. वित्तीय समावेशन और कौशल विकास
5. बुनियादी ढांचे

सही कूट चुनें

a) केवल 1, 2, 3 और 4
b) केवल 2, 3, 4 और 5
c) केवल 1, 3, 4 और 5
d) उपरोक्त सभी

Q.40) Solution (d)

भारत में जीवन स्तर महत्वपूर्ण अंतर-राज्य और अंतर-जिला विविधताओं से प्रभावित हैं। इस विषमता को दूर करने के लिए, सरकार ने जनवरी 2018 में 'आकांक्षी जिलों का सुधार कार्यक्रम' (ADP) आरंभ किया है।

आकांक्षी जिला कार्यक्रम (Aspirational Districts' Programme)

- आकांक्षी जिले भारत में वे जिले हैं, जो खराब सामाजिक-आर्थिक संकेतकों से प्रभावित हैं।
- ये इस संदर्भ में आकांक्षी हैं कि इन जिलों में सुधार से भारत में मानव विकास में समग्र सुधार हो सकता है।
- 115 जिलों की पहचान 28 राज्यों से की गई थी, प्रत्येक राज्य से कम से कम एक।
- भारत सरकार के स्तर पर, कार्यक्रम की अध्यक्षता नीति आयोग द्वारा की जाती है। इसके अलावा, व्यक्तिगत मंत्रालयों ने जिलों की प्रगति को देखने के लिए जिम्मेदारी संभाली है।
- कार्यक्रम का उद्देश्य आकांक्षी जिलों की वास्तविक समय में प्रगति की निगरानी करना है।
- ADP 5 पहचाने गए विषयगत क्षेत्रों के 49 संकेतकों पर आधारित है, जो लोगों के **स्वास्थ्य और पोषण, शिक्षा, कृषि और जल संसाधन, वित्तीय समावेशन और कौशल विकास और बुनियादी ढाँचे** में सुधार लाने पर ध्यान केंद्रित करता है।
- मुख्य चालकों के रूप में राज्यों के साथ, ADP प्रत्येक जिले की शक्ति पर ध्यान केंद्रित करने, तत्काल सुधार के लिए आसान लाभदायक क्षेत्रों की पहचान करना, प्रगति को मापना और जिलों की रैंक करना है।
- कार्यक्रम के व्यापक रूप हैं: अभिसरण (केंद्रीय और राज्य योजनाओं का) जो सरकार के क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर स्तरों को एक साथ लाता है।
- सहयोग (केंद्रीय, राज्य स्तर के प्रभारी अधिकारी और जिला कलेक्टर) जो सरकार, बाजार और नागरिक समाज के बीच प्रभावशाली भागीदारी को सक्षम बनाता है।
- जन आंदोलन की भावना से संचालित जिलों के बीच प्रतिस्पर्धा, यह जिला सरकारों पर जवाबदेही को बढ़ाती है।

Q.41) निम्नलिखित कथनों पर विचार करें

1. चलती मुद्रास्फीति (Walking inflation) वह है जो एक वर्ष में 3-10% के बीच रहती है तथा अर्थव्यवस्था के लिए हानिकारक होती है क्योंकि इसमें आर्थिक विकास को बहुत तीव्र होता है
2. सरपट मुद्रास्फ़ीति (Galloping inflation) के दौरान मुद्रा मूल्य इतनी तेज़ी से घटता है कि व्यवसाय और कर्मचारी आय को लागत और कीमतों के साथ नहीं रख सकते हैं
3. मुद्रास्फीतिजनित मंदी (Stagflation) तब होता है जब आर्थिक विकास स्थिर होता है लेकिन अभी भी मूल्य मुद्रास्फीति होती है

उपरोक्त कथनों में से कौन सा सही है / हैं?

a) केवल 1 और 2
b) केवल 2 और 3
c) केवल 1 और 3
d) उपरोक्त सभी

Q.41) Solution (d)

कथन 1	कथन 2	कथन 3

सत्य	सत्य	सत्य
चलती मुद्रास्फीति एक प्रकार की मजबूत या हानिकारक होती है, यह मुद्रास्फीति प्रति वर्ष 3-10% के बीच होती है। यह अर्थव्यवस्था के लिए हानिकारक होती है क्योंकि यह आर्थिक विकास को अत्यधिक तेजी से बढ़ाती है। लोग, केवल आने वाले समय में बहुत अधिक कीमतों से बचने के लिए ज़रूरत से ज़्यादा खरीदारी करने लगते हैं। यह कारक आगे भी मांग को बढ़ाता है जिसे आपूर्तिकर्ता संभाल नहीं पाता है। परिणामस्वरूप, सामान्य वस्तुओं और सेवाओं की कीमत अधिकांश लोगों की पहुंच से बाहर हो जाती है।	जब मुद्रास्फीति 10% या उससे अधिक हो जाती है, तो यह अर्थव्यवस्था पर पूरी तरह विनाशकारी होती है। मुद्रा मूल्य इतनी तेज़ी से घटता है कि व्यवसाय और कर्मचारी आय को लागत और कीमतों के साथ नहीं रख सकते हैं। विदेशी निवेशक ऐसे देश से बचते हैं, जो इसे आवश्यक पूंजी से वंचित करता हैं। अर्थव्यवस्था अस्थिर हो जाती है, तथा सरकार विश्वसनीयता खो देती हैं। सरपट मुद्रास्फीति को हर कीमत पर रोका जाना चाहिए	मुद्रास्फीतिजनित मंदी (Stagflation) का अर्थ, कीमतों में वृद्धि और आर्थिक विकास में ठहराव का एक साथ होना है। स्टैगफ्लेशन को पहली बार 20 वीं शताब्दी के बाद व्यापक रूप से मान्यता प्राप्त हुई थी, विशेष रूप से 1970 के दशक के दौरान अमेरिकी अर्थव्यवस्था में, जो लगातार तीव्र मुद्रास्फीति और उच्च बेरोजगारी का अनुभव कर रही थी। तात्कालिक पूर्व-प्रभावी आर्थिक सिद्धांत आसानी से यह नहीं बता सकते थे कि स्टैगफ्लेशन कैसे हो सकता है। 1970 के बाद से, धीमी या नकारात्मक आर्थिक वृद्धि की अवधि के दौरान बढ़ते मूल्य स्तर एक असाधारण स्थिति के बजाय आदर्श बन गए हैं।

Q.42) निम्न में से कौन सी घटना फिलिप्स वक्र के आर्थिक सिद्धांत का विरोध करती है?

a) अपस्फीति (Deflation)
b) पुन: मुद्रास्फीति
c) मुद्रास्फीतिजनित मंदी (Stagflation)
d) मूल स्फीति (Core inflation)

Q.42) Solution (c)

Elimination

फिलिप्स वक्र एक आर्थिक अवधारणा है जिसे ए. डब्ल्यू फिलिप्स द्वारा विकसित किया गया है, जिसमें कहा गया है कि मुद्रास्फीति और बेरोजगारी में एक स्थिर और व्युक्रमानुपाती संबंध होता है। सिद्धांत का दावा है कि आर्थिक विकास के साथ मुद्रास्फीति आती है, जो बदले में अधिक नौकरियों और कम बेरोजगारी का कारण बनती है।

यदि कोई फिलिप्स वक्र की अवधारणा के बारे में स्पष्ट है, तो उत्तर आसानी से निकाला जा सकता है

मुद्रास्फीतिजनित मंदी (Stagflation) धीमी आर्थिक वृद्धि और अपेक्षाकृत उच्च बेरोजगारी या बढ़ती कीमतों या मुद्रास्फीति के साथ आर्थिक ठहराव की स्थिति है। इसे मुद्रास्फीति और सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) में गिरावट के रूप में भी परिभाषित किया जा सकता है।

स्टैगफ्लेशन को लंबे समय तक असंभव माना जाता था क्योंकि अकादमिक और नीतिगत समुदायों पर प्रभावी होने वाले आर्थिक सिद्धांतों ने संरचनागत तौर पर इसे अपने मॉडल से बाहर कर दिया था। विशेष रूप से फिलिप्स वक्र के आर्थिक सिद्धांत, जो कीनेशियन अर्थशास्त्र के संदर्भ में विकसित हुआ था, ने बेरोजगारी और मुद्रास्फीति के बीच व्यापार-सिद्धांत के रूप में व्यापक आर्थिक नीति को चित्रित किया था।

1970 के बाद से, धीमी या नकारात्मक आर्थिक वृद्धि की अवधि के दौरान बढ़ते मूल्य स्तर एक असाधारण स्थिति के बजाय आदर्श बन गए हैं।

Q.43) निम्नलिखित कथनों पर विचार करें

1. लागत-जनित मुद्रास्फीति मजदूरी और कच्चे माल की लागत में वृद्धि के कारण होती है जबकि प्रभावित उत्पाद की मांग अभी भी स्थिर रहती है।
2. मुद्रास्फीति उपभोक्ता की क्रय शक्ति को नष्ट कर सकती है
3. मांग-जनित मुद्रास्फीति की विशेषता "बहुत अधिक रुपयों के साथ कुछ वस्तुओं का पीछा करने" से है।

उपरोक्त कथनों में से कौन सा सही है / हैं?

a) केवल 1 और 2
b) केवल 2 और 3
c) केवल 1 और 3
d) उपरोक्त सभी

Q.43) Solution (d)

कथन 1	कथन 2	कथन 3
सत्य	सत्य	सत्य
लागत-जनित मुद्रास्फीति तब होती है जब मजदूरी और कच्चे माल की लागत में वृद्धि के कारण समग्र कीमतें (मुद्रास्फीति) बढ़ जाती हैं। उत्पादन की उच्च लागत अर्थव्यवस्था में कुल आपूर्ति (कुल उत्पादन की मात्रा) को कम कर सकती है। चूंकि वस्तुओं की मांग में बदलाव नहीं हुआ है, इसलिए उत्पादन से मूल्य वृद्धि उपभोक्ताओं द्वारा लागत-जनित मुद्रास्फीति पैदा करने पर आधारित होती है। लागत-जनित मुद्रास्फीति को होने के लिए, उस समय जब उत्पादन लागत में परिवर्तन हो रहा हो, उस समय प्रभावित उत्पाद की माँग स्थिर बनी रहनी चाहिए। उत्पादन की बढ़ती लागत की भरपाई करने	मुद्रास्फीति, चयनित वस्तुओं और सेवाओं की एक टोकरी के लिए एक अर्थव्यवस्था में मूल्य वृद्धि की दर की एक माप है। मुद्रास्फीति एक उपभोक्ता की क्रय शक्ति को नष्ट कर सकती है यदि मजदूरी पर्याप्त नहीं बढ़ी है या बढ़ती कीमतों के साथ समायोजित नहीं रखी गई है। मान लीजिए कि अर्थव्यवस्था में मुद्रास्फीति एक विशेष वर्ष में 5% है जब मजदूरी स्थिर रहेगी, तो यह उपभोक्ता के लिए बोझ होगा क्योंकि उसके पास की मुद्रा का मूल्य कम हो जाएगा	मांग-जनित मुद्रास्फीति उन कीमतों पर ऊपर की ओर दबाव है जो आपूर्ति में कमी का अनुसरण करती है। अर्थशास्त्रियों ने इसे "बहुत अधिक रुपयों के साथ कुछ वस्तुओं का पीछा करने" के रूप में वर्णित किया है। मांग-जनित मुद्रास्फीति कीनेशियन अर्थशास्त्र का एक सिद्धांत है जो कुल आपूर्ति और मांग में असंतुलन के प्रभावों का वर्णन करता है। जब एक अर्थव्यवस्था में निश्चित आपूर्ति सकल मांग को अत्यधिक बढ़ा देती है, तो कीमतें बढ़ जाती हैं। यह मुद्रास्फीति का सबसे सामान्य कारण होता है।

के लिए, उत्पादक अपेक्षित मांग के साथ तालमेल रखते हुए उपभोक्ता को लाभ का स्तर बनाए रखने के लिए कीमत बढ़ाते हैं।		

Q.44) निम्नलिखित में से कौन लागत-जनित मुद्रास्फीति का उदाहरण नहीं है?

a) तेल की कीमत में वृद्धि के कारण कीमतों के सामान्य स्तर में वृद्धि होना
b) 2012 में पंजाब और सिंध क्षेत्र में बाढ़ आई, जिसके कारण आपूर्ति में व्यापक व्यवधान होना
c) 2011 में जापान के भूकंप जैसी प्राकृतिक आपदाओं के कारण आपूर्ति में व्यवधान होना
d) 2008 का वित्तीय संकट, जिसके परिणामस्वरूप संपत्ति मुद्रास्फीति (asset inflation) जो सोने और तेल में हुई

Q.44) Solution (d)

लागत-जनित मुद्रास्फीति, मुद्रास्फीति का एक रूप है जो उत्पादन की लागत में वृद्धि या उत्पादन की मात्रा में कमी से उत्पन्न होती है। लागत-जनित मुद्रास्फीति में, समग्र आपूर्ति वक्र बाईं ओर झुकता है, जिससे कीमतों में वृद्धि होती है, और इसलिए, लागत-जनित कहा जाता है।

- आपूर्ति के व्यवधान के कारण लागत-जनित मुद्रास्फीति सबसे अधिक उत्पन्न होती है। उदाहरण के लिए, तेल की कीमत में वृद्धि से लगभग सभी वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन की लागत बढ़ जाती है तथा इसके परिणामस्वरूप मुद्रास्फीति में तुरंत वृद्धि होती है। इस तरह की मुद्रास्फीति लागत-जनित मुद्रास्फीति है। इसी तरह श्रमिक हड़ताल, युद्ध, बाढ़ आदि आपूर्ति कम करते हैं और कीमतें बढ़ाते हैं।
- 2012 में, गंभीर बाढ़ ने पाकिस्तान के पंजाब और सिंध प्रांत में फसलों को नष्ट कर दिया था, रिफाइनरी को बंद कर दिया, मवेशियों को मार डाला था और आपूर्ति में व्यापक व्यवधान पैदा किया था। इसने कीमतों के सामान्य स्तर में वृद्धि की थी। यह इसी प्रकार की मुद्रास्फीति है
- सकल आपूर्ति में गिरावट के कारण मूल्य में वृद्धि लागत-जनित मुद्रास्फीति है।
- प्राकृतिक आपदाएँ आपूर्ति बाधित होने से मुद्रास्फीति का कारण बनती हैं। 2011 में जापान के भूकंप के बाद एक अच्छा उदाहरण है। इसने ऑटो पार्ट्स की आपूर्ति को बाधित कर दिया। ऐसा तूफान कैटरीना के बाद भी हुआ था। जब तूफान ने तेल रिफाइनरियों को नष्ट कर दिया, तो गैस की कीमतें बढ़ गईं थीं।

2008 के वित्तीय संकट के बाद, सोने और तेल की कीमतों में परिसंपत्ति मुद्रास्फीति हुई थी। आवास की कीमतों और व्यक्तिगत आय में गिरावट हुई। सोने की कीमतों में मांग-जनित मुद्रास्फीति जारी रही, जब तक कि वे एक रिकॉर्ड स्तर तक नहीं पहुंच गए।

Q.45) मांग-जनित मुद्रास्फीति के निम्नलिखित में से कौन से कारण हो सकते हैं?

1. एक विकसित होती अर्थव्यवस्था
2. निम्न बेरोजगारी दर
3. सरकारी व्यय में बढ़ोत्तरी
4. मुद्रास्फीति की आशाएं
5. संपत्ति मुद्रास्फीति

नीचे दिए गए कूट का उपयोग करके सही उत्तर चुनें

a) केवल 1, 2, 3 और 5

b) केवल 2, 3, 4 और 5
c) केवल 1, 3, 4 और 5
d) उपरोक्त सभी

Q.45) Solution (d)
जब मांग आपूर्ति से अधिक हो जाती है, जिसका परिणाम उच्च कीमतें होती हैं। इसे मांग-जनित मुद्रास्फीति कहते हैं।

निम्न बेरोजगारी दर सामान्य रूप से निर्विवाद रूप से अच्छी है, लेकिन यह मुद्रास्फीति का कारण बन सकती है क्योंकि अधिक लोगों के पास अधिक व्यय-योग्य (डिस्पोजेबल) आय होती है।

सरकार का बढ़ा हुआ व्यय अर्थव्यवस्था के लिए भी अच्छा है, लेकिन इससे कुछ वस्तुओं में कमी आ सकती है तथा जिससे महंगाई दर बढ़ जाएगी।

मांग-जनित मुद्रास्फीति के कारण

1. एक विकसित होती अर्थव्यवस्था: जब उपभोक्ताओं को आत्मविश्वास महसूस होता है, तो वे अधिक खर्च करते हैं और अधिक कर्ज लेते हैं। इससे मांग में लगातार वृद्धि होती है, जिसका परिणाम उच्च कीमतें होती हैं।
2. संपत्ति मुद्रास्फीति (Asset inflation): निर्यात कारकों में अचानक वृद्धि शामिल मुद्राओं के एक अल्पमूल्यन (undervaluation) को बल देती है।
3. सरकारी व्यय: जब सरकार अधिक स्वतंत्र रूप से व्यय करती है, तो कीमतें बढ़ जाती हैं।
4. मुद्रास्फीति प्रत्याशा: कंपनियां निकट भविष्य में मुद्रास्फीति की उम्मीद में अपनी कीमतें बढ़ा सकती हैं।
5. प्रणाली में अधिक मुद्रा: खरीदने के लिए बहुत कम वस्तु के साथ पैसे की आपूर्ति का विस्तार कीमतों को बढ़ाता है।

Q.46) "ऑपरेशन ग्रीन योजना" (Operation greens scheme) के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें।
1. यह केवल टमाटर, प्याज और आलू के उत्पादन और प्रसंस्करण को बढ़ावा देने के लिए एक कार्यक्रम है, जिसके एक उद्देश्य के रूप में उनमें मूल्य अस्थिरता की जांच करना है।
2. इसकी घोषणा 5,000 करोड़ के परिव्यय के साथ 2018-19 के वार्षिक बजट के दौरान की गई थी

उपरोक्त कथन में से कौन सा सही है / हैं?
a) केवल 1
b) केवल 2
c) 1 और 2 दोनों
d) इनमें से कोई भी नहीं

Q.46) Solution (a)
ऑपरेशन ग्रीन योजना (Operation greens scheme)

केंद्रीय बजट 2018-19 के बजट भाषण में, किसान उत्पादक संगठनों (एफपीओ), कृषि-लॉजिस्टिक्स, प्रसंस्करण सुविधाओं और पेशेवर प्रबंधन को बढ़ावा देने के लिए 500 करोड़ रुपये के परिव्यय के साथ, "ऑपरेशन ग्रीन्स" की एक नई योजना की घोषणा "ऑपरेशन फ्लड" की तर्ज पर की गई थी। तदनुसार,

खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय ने टमाटर, प्याज और आलू (TOP) मूल्य श्रृंखला के एकीकृत विकास के लिए एक योजना तैयार की है।

उद्देश्य:

- टीओपी (TOP) उत्पादन समूहों और उनके एफपीओ को मजबूत करने के लिए लक्षित हस्तक्षेपों द्वारा टीओपी किसानों के मूल्य वर्धन को बढ़ाना, और उन्हें बाजार से जोड़ना।
- TOP क्लस्टरों में उचित उत्पादन योजना और दोहरे उपयोग वाली किस्मों की शुरूआत द्वारा उत्पादकों और उपभोक्ताओं के लिए मूल्य स्थिरीकरण करना।
- फ़ार्म गेट इंफ्रास्ट्रक्चर के निर्माण, उपयुक्त कृषि-लॉजिस्टिक्स के विकास और उपभोग केंद्रों को जोड़ने वाली उचित भंडारण क्षमता के निर्माण से फसल के बाद के नुकसान में कमी लाना।
- खाद्य प्रसंस्करण क्षमताओं में वृद्धि और उत्पादन समूहों के साथ फर्म लिंकेज के साथ TOP वैल्यू चेन में मूल्यवर्धन करना।
- शीर्ष फसलों की मांग और आपूर्ति तथा कीमत पर वास्तविक समय के डेटा को एकत्रित करने और अंतर्संबंधित करने के लिए एक बाजार खुफिया नेटवर्क की स्थापना करना।

Q.47) निम्नलिखित में से कौन लागत-जनित मुद्रास्फीति का कारण हो सकता है?

1. वेतन में वृद्धि
2. व्यवसाय का एकाधिकार
3. सरकार विनियमन और कर
4. विनिमय दरें (Exchange rates)
5. बढ़ती उत्पादन लागत

नीचे दिए गए कूट का उपयोग करके सही उत्तर चुनें

a) केवल 1, 2, 3 और 5
b) केवल 2, 3, 4 और 5
c) केवल 1, 3, 4 और 5
d) उपरोक्त सभी

Q.47) Solution (d)

लागत -जनित मुद्रास्फीति (Cost-Push Inflation):

सामान्यतः उत्पादन लागत में वृद्धि के कारण यह मूल्य वृद्धि होती है। जैसा कि हम जानते हैं, उत्पादन और परिवहन की लागत के कारण सेब की कीमतों में वृद्धि हुई थी। यह लागत-जनित मुद्रास्फीति है।

इसके कुछ प्रमुख कारण हैं:

- **मजदूरी में वृद्धि:** मजदूरों या किसी अन्य परिस्थिति के कारण मजदूरों की मजदूरी में वृद्धि के साथ, उत्पादन लागत में वृद्धि होती है, जिससे उत्पाद की कीमतें बढ़ जाती हैं
- **व्यापारिक एकाधिकार:** जब किसी कंपनी का किसी विशेष उत्पाद पर एकाधिकार होता है, तो वह उत्पाद की मात्रा और कीमत तय कर सकती है, जिससे कीमतों में वृद्धि हो सकती है
- **सरकारी विनियमन और कर:** अप्रत्यक्ष कर सीधे किसी भी उत्पाद की बिक्री मूल्य में वृद्धि करते हैं। इसके अलावा, सरकार के नियमों जैसे कि विशेष संसाधन पर प्रतिबंध लगाने या एमएसपी बढ़ाने से उत्पाद की उत्पादन लागत में वृद्धि हो सकती है।
- **विनिमय दर (Exchange rates):** यदि विनिमय दरों में गिरावट होती है, तो कच्चे माल की लागत में वृद्धि होती है इसलिए उत्पादों की कीमतों में वृद्धि होती है

- **उत्पादन लागत बढ़ाना:** उत्पादन के चार कारकों में से किसी एक में वृद्धि से उत्पादन की लागत बढ़ जाती है।

Q.48) निम्नलिखित में से किसे "मिश्रित मुद्रास्फीति" (mixed inflation) का उन्नत रूप माना जाता है?

a) मार्क-अप मुद्रास्फीति (Mark-up inflation)
b) मुद्रास्फीतिजनित मंदी (Stagflation)
c) विस्फीति (Dis-inflation)
d) अति स्फीति (Hyperinflation)

Q.48) Solution (a)

अधिकांश अर्थशास्त्रियों का मानना है कि मुद्रास्फीति न तो पूरी तरह से 'मांग जनित' है और न ही पूरी तरह से 'लागत जनित' है, वास्तविक मुद्रास्फीति प्रक्रिया में दोनों के तत्व शामिल होते हैं। अत्यधिक मांग और वेतन में वृद्धि एक ही समय में होता है, लेकिन यह आवश्यक नहीं है कि वे एक ही समय में आरंभ हों।

गार्नर अकले (Garner Akley) ने **'मार्कअप मुद्रास्फीति' (markup inflation)** के सिद्धांत को आगे रखा। सरल शब्दों में यह 'मिश्रित मुद्रास्फीति' का एक उन्नत विवरण है। अकले के अनुसार पहले मांग जनित मुद्रास्फीति आती है, और इसके बाद लागत जनित मुद्रास्फीति होती है। मार्कअप मुद्रास्फीति तब होती है जब अतिरिक्त मांग कीमतों में वृद्धि करती है, जो उत्पादन को उत्तेजित करती है। बढ़ता हुआ उत्पादन उत्पादन के कारकों की अत्यधिक माँग पैदा करता है, और उत्पादन के कारकों की अत्यधिक माँग कीमतों को और बढ़ा देती है।

Q.49) निम्नलिखित कथनों पर विचार करें

1. पुन:स्फीति (Reflation) उस स्थिति को संदर्भित करती है जहां मुद्रास्फीति को रोकने के लिए उपाय किए जाते हैं
2. अपस्फीति (deflation) के दौरान मुद्रा की क्रय शक्ति बढ़ जाती है
3. उपभोक्ता मूल्य सूचकांक आधारित मुद्रास्फीति को हेडलाइन मुद्रास्फीति (headline inflation) कहा जाता है

नीचे दिए गए कूट का उपयोग करके सही उत्तर चुनें

a) केवल 1 और 2
b) केवल 2 और 3
c) केवल 1 और 3
d) उपरोक्त सभी

Q.49) Solution (b)

कथन 1	कथन 2	कथन 3
असत्य	सत्य	सत्य
पुन:स्फीति (Reflation): इस शब्द का उपयोग उस स्थिति को संदर्भित करने के लिए किया जाता है जहां **अपस्फीति (deflation)** को रोकने के लिए उपाय किए जाते हैं। यह कदम राजकोषीय नीति (करों	सामयिक अवधि में अपस्फीति (Deflation) सामान्य मूल्य स्तर में कमी है। अपस्फीति मुद्रास्फीति के विपरीत है। विशेष रूप से अर्थशास्त्रियों के लिए, इस शब्द का उपयोग कभी-कभी मुद्रा की आपूर्ति के	उपभोक्ता मूल्य सूचकांक आधारित मुद्रास्फीति को हेडलाइन मुद्रास्फीति कहा जाता है

को कम करने) या मौद्रिक नीति (धन की आपूर्ति बढ़ाने या ब्याज दरों को कम करने) की तरह हो सकते हैं	आकार में कमी (सामान्य मूल्य स्तर में कमी का एक अनुमानित कारण के रूप में) के लिए किया जाता है। उत्तरवर्ती को अब अक्सर मुद्रा की आपूर्ति के 'संकुचन' के रूप में जाना जाता है। अपस्फीति के दौरान वस्तुओं या ब्याज की प्राथमिकता में तरलता की मांग बढ़ जाती है। अपस्फीति के दौरान मुद्रा की क्रय शक्ति बढ़ जाती है। अपस्फीतिक सर्पिल (deflationary spiral) की क्षमता और महामंदी से इसके जुड़ाव के कारण अपस्फीति को एक आधुनिक अर्थव्यवस्था में एक समस्या माना जाता है, हालांकि अपस्फीति के सभी प्रकरण ऐतिहासिक रूप से खराब आर्थिक विकास के समय के अनुरूप नहीं होते हैं।	

Q.50) निम्नलिखित में से कौन "ग्रामीण आबादी के लिए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक संख्या" को लाता है?

a) भारतीय रिजर्व बैंक
b) आर्थिक मामलों का विभाग
c) श्रम ब्यूरो
d) राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय

Q.50) Solution (d)

- उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (CPI) घरों द्वारा उपभोग की जाने वाली आवश्यक वस्तुओं और सेवाओं के खुदरा मूल्यों में परिवर्तन को ट्रैक करता है
- सूचकांक ग्रामीण, शहरी और साथ ही अखिल भारतीय स्तर पर वस्तुओं और सेवाओं की संपूर्ण टोकरी के मूल्य आंदोलन को ट्रैक करता है।
- सूचकांक में टोकरी में विभिन्न वस्तुओं से जुड़े अलग-अलग भारांश होते हैं। एकल तत्व का भार शहरी और ग्रामीण सूचकांक के लिए भी भिन्न हो सकता है। उदाहरण के लिए, खाद्य और पेय पदार्थ श्रेणी ग्रामीण सीपीआई में 54.18% भार वहन करते हैं, जबकि यह शहरी सूचकांक में केवल 36.29% भार वहन करते है।
- सामयिक अवधि में सूचकांक में बदलाव सीपीआई मुद्रास्फीति है। सीपीआई का व्यापक रूप से अधिकांश देशों द्वारा मुद्रास्फीति के एक व्यापक आर्थिक संकेतक के रूप में, सरकारों और केंद्रीय बैंकों द्वारा मुद्रास्फीति लक्ष्यीकरण और मूल्य स्थिरता की निगरानी के लिए, तथा राष्ट्रीय खातों में अपस्फीति के रूप में उपयोग किया जाता है। वर्तमान में, भारतीय रिज़र्व बैंक 4% लक्ष्य के 2% के भीतर CPI- आधारित मुद्रास्फीति को लक्षित करता है।
- राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय (एनएसओ), सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय 2012 = 100 आधार पर सीपीआई (ग्रामीण, शहरी, संयुक्त) को मासिक आधार पर लाता है।

Q.51) निम्नलिखित कथनों पर विचार करें

1. जीडीपी अपस्फीतिकारक (deflator) उत्पादित सभी वस्तुओं और सेवाओं की कीमतों को मापता है, जबकि सीपीआई केवल उपभोक्ताओं द्वारा खरीदी गयी वस्तुओं और सेवाओं की कीमतों को मापता है।
2. सीपीआई और डब्ल्यूपीआई में भारांक स्थिर (टोकरी में) होते है, लेकिन वे जीडीपी अपस्फीतिकारक (deflator) में प्रत्येक वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन स्तर के अनुसार भिन्न होते हैं।
3. जीडीपी अपस्फीतिकारक (deflator) में केवल उन्हीं वस्तुओं को शामिल किया जाता है जो घरेलू स्तर पर उत्पादित होती हैं।

नीचे दिए गए कूट का उपयोग करके सही उत्तर चुनें

a) केवल 1 और 3
b) केवल 2 और 3
c) केवल 1 और 2
d) उपरोक्त सभी

Q.51) Solution (d)

कथन 1	कथन 2	कथन 3
सत्य	सत्य	सत्य
जीडीपी अपस्फीतिकारक (deflator) उत्पादित सभी वस्तुओं और सेवाओं की कीमतों को मापता है, जबकि सीपीआई या आरपीआई केवल उपभोक्ताओं द्वारा खरीदी गई वस्तुओं और सेवाओं की कीमतों को मापता है। इस प्रकार, फर्मों या सरकार द्वारा खरीदे गए सामानों की कीमत में वृद्धि जीडीपी डिफ्लेटर में दिखाई देगी लेकिन सीपीआई या आरपीआई में नहीं।	सीपीआई या आरपीआई अलग-अलग वस्तुओं की कीमतों के लिए निश्चित भार (weights) प्रदान करता है, जबकि जीडीपी डिफ्लेटर बदलते भार को असाइन करता है। दूसरे शब्दों में, सीपीआई या आरपीआई की गणना वस्तु की एक निश्चित टोकरी का उपयोग करके की जाती है, जबकि जीडीपी डिफ्लेटर वस्तु की टोकरी को समय के साथ बदलने की अनुमति देता है क्योंकि जीडीपी की संरचना बदल जाती है।	जीडीपी डिफ्लेटर में केवल उन्हीं वस्तुओं को शामिल किया जाता है जो घरेलू स्तर पर उत्पादित होती हैं। आयातित माल जीडीपी का हिस्सा नहीं है और जीडीपी डिफ्लेटर में नहीं दिखता है। उदाहरण के लिए, जापान में बने टोयोटा की कीमत में वृद्धि और यू.के. में बेची गई सीपीआई या आरपीआई को प्रभावित करती है, क्योंकि टोयोटा को यू.के. में उपभोक्ताओं द्वारा खरीदा जाता है, लेकिन यह जीडीपी डिफ्लेटर को प्रभावित नहीं करता है।

Q.52) निम्नलिखित कथनों पर विचार करें

1. उच्च मुद्रास्फीति हमारे निर्यात के अधिक कीमत तथा आयात के कम कीमत का कारण बनेगी।
2. अपस्फीति (Deflation) अर्थव्यवस्था की सहायक होती है जो निरंतर तकनीकी प्रगति में निवेश करती है।
3. शून्य मुद्रास्फीति (Zero inflation) अर्थव्यवस्था के लिए खराब होती है क्योंकि उत्पादन और मांग दोनों ही स्थिर होते हैं।

नीचे दिए गए कूट का उपयोग करके सही उत्तर का चयन करें

a) केवल 1 और 3
b) केवल 2 और 3

c) केवल 1 और 2
d) उपरोक्त सभी

Q.52) Solution (d)

कथन 1	कथन 2	कथन 3
सत्य	सत्य	सत्य
जैसा कि आप जानते हैं, मुद्रास्फीति आपकी मुद्रा को कम मूल्यवान बनाती है। उच्च मुद्रास्फीति हमारे निर्यात के अधिक कीमत तथा आयात के कम कीमत का कारण बनेगी। इसलिए, कम निर्यात और अधिक आयात होगा जिससे भुगतान संतुलन बिगड़ जाएगा।	ऐसे कुछ मामले हैं जहां यह अच्छा हो सकता है लेकिन इस 21 वीं सदी में यह शायद ही कभी देखा जा सकता है। मान लीजिए अगर लगातार तकनीकी सुधार होते हैं: तो अधिकांश सामान हर साल कम लागत पर उत्पादित किया जा सकता है तथा इसलिए कीमतें गिर सकती हैं। यह निश्चित रूप से एक अच्छा संकेत है भले ही कोई अपस्फीति हो। यह भी हो सकता है कि जापान के साथ ऐसा कैसे हुआ, अगर अधिकांश पड़ोसी देशों में मुद्रास्फीति हो रही है, तो अपस्फीति वाले देश को बेहतर प्रतिस्पर्धात्मक लाभ होता है क्योंकि उनके सामान स्पष्ट रूप से मुद्रास्फीति वाले अन्य देशों की तुलना में सस्ते लगते हैं।	मुद्रास्फीति अक्सर (लेकिन हमेशा नहीं) विकास से संबंधित होती है। जब 'शून्य' या बहुत निम्न मुद्रास्फीति होती है, तो: • अर्थव्यवस्था में मुद्रा लगभग स्थिर रहती है • उत्पादन स्थिर रहेगा और • मांग भी स्थिर रहेगी। • इसलिए, यह बढ़ती अर्थव्यवस्था के लिए अच्छा नहीं है।

Q.53) निम्नलिखित कथनों पर विचार करें

1. उपभोक्ता मूल्य सूचकांक आधारित मुद्रास्फीति पिछले 5 वर्षों के दौरान लगातार बढ़ी है।
2. जीडीपी अपस्फीतिकारक (GDP deflator) में पिछले 5 वर्षों के दौरान लगातार वृद्धि हुई है।
3. थोक मूल्य सूचकांक आधारित मुद्रास्फीति पिछले 5 वर्षों के दौरान लगातार बढ़ी है।

नीचे दिए गए कूट का उपयोग करके उत्तर चुनें

a) केवल 1 और 2
b) केवल 1 और 3
c) केवल 2
d) इनमें से कोई भी नहीं

Q.53) Solution (c)

भारत में उपभोक्ता मूल्य मुद्रास्फीति 2020 की जनवरी में 7.59% बढ़ गयी, जो दिसंबर में 7.35% थी, जो 7.4% की अपेक्षा से अधिक थी। मई, 2014 से सीधे 6 वें महीने के लिए मुद्रास्फीति में तेजी आई है।

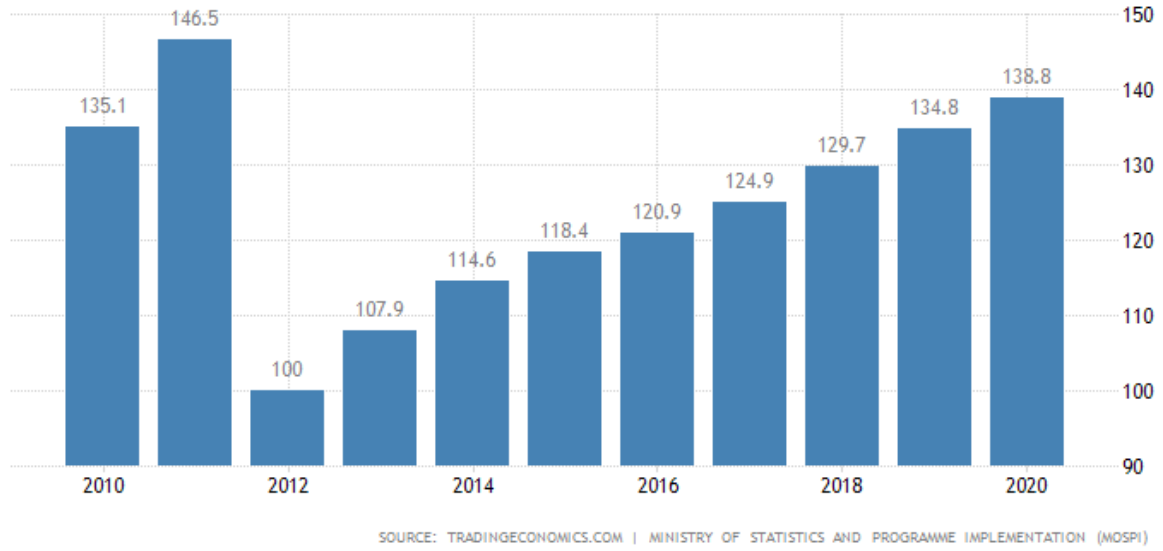

भारत में जीडीपी डिफ्लेटर 2019 में 134.80 अंकों से 2020 में 138.80 अंक तक बढ़ गया। जैसा कि हम ऊपर ग्राफ से देख सकते हैं कि जीडीपी डिफ्लेटर पिछले 5 वर्षों में लगातार बढ़ा है।

समग्र थोक मूल्य सूचकांक में पिछले 5 वर्षों में उतार-चढ़ाव देखा गया है

Q.54) निम्न में से कौन मासिक मुद्रास्फीति के आंकड़े में विकृति को दर्शाता है जो वर्ष-महीने में असामान्य रूप से उच्च या निम्न स्तर की मुद्रास्फीति से होता है?

a) आधार प्रभाव (Base effect)
b) दूरगामी प्रभाव (Domino effect)
c) लागत-जनित प्रभाव
d) मार्क-अप प्रभाव (mark-up effect)

Q.54) Solution (a)
आधार प्रभाव (base effect) एक मासिक मुद्रास्फीति के आंकड़े में विकृति है जो वर्ष-महीने में असामान्य रूप से उच्च या निम्न स्तर की मुद्रास्फीति से होता है। एक आधार प्रभाव समय के साथ मुद्रास्फीति के स्तर का सही आकलन करना मुश्किल बना सकता है।

मुद्रास्फीति अक्सर महीने-दर-महीने के आंकड़े या साल-दर-साल के आंकड़े के रूप में व्यक्त की जाती है। आमतौर पर, अर्थशास्त्री और उपभोक्ता जानना चाहते हैं कि एक साल पहले की तुलना में आज कितनी अधिक या कम कीमतें हैं। लेकिन एक महीने में मुद्रास्फीति की वृद्धि एक साल बाद विपरीत प्रभाव पैदा कर सकती है, अनिवार्य रूप से यह धारणा बना सकती है कि मुद्रास्फीति धीमा हो गई है।

आधार प्रभाव के उदाहरण

मुद्रास्फीति की गणना मूल्य के स्तरों के आधार पर की जाती है जो एक सूचकांक में संक्षेपित होते हैं। सूचकांक जून में बढ़ सकता है, उदाहरण के लिए, शायद गैसोलीन की कीमतों में वृद्धि के कारण। अगले 11 महीनों में, महीने-दर-महीने परिवर्तन सामान्य हो सकता है, लेकिन जब जून फिर से आता है तो इसकी कीमत का स्तर एक साल पहले की तुलना में होगा जिसमें सूचकांक ने गैसोलीन की कीमतों में बढ़ोतरी को दर्शाया था। उस स्थिति में, क्योंकि उस महीने का सूचकांक उच्च था, इस जून में मूल्य परिवर्तन कम होगा, जिसका अर्थ है कि मुद्रास्फीति तब नियंत्रण में हो गई है, जबकि वास्तव में, सूचकांक में छोटा परिवर्तन आधार प्रभाव का एक प्रतिबिंब है - जो एक साल पहले के उच्च सूचकांक मूल्य का परिणाम है।

Q.55) भारत में परिवारों का 'मुद्रास्फीति प्रत्याशा सर्वेक्षण' (inflation expectation survey) किसके द्वारा किया जाता है

a) केंद्रीय सांख्यिकी संगठन
b) राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण संगठन
c) भारतीय रिजर्व बैंक
d) वित्त मत्रांलय

Q.55) Solution (c)
रिज़र्व बैंक ने जनवरी 2020 के राउंड ऑफ इन्फ्लेशन एक्सपेक्टेशंस सर्वे ऑफ़ हाउसेज़ (IESH) के परिणाम जारी किए। सर्वेक्षण 18 प्रमुख शहरों में आयोजित किया गया था तथा परिणाम 5,868 शहरी परिवारों की प्रतिक्रियाओं पर आधारित हैं।
यह सर्वेक्षण भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा द्विमासिक अंतराल पर आयोजित किया जाता है। यह उत्तरदाताओं द्वारा अपेक्षित के रूप में निकट अवधि के मुद्रास्फीति के दबावों पर दिशात्मक जानकारी प्रदान करता है तथा अपने स्वयं के उपभोग पैटर्न को प्रतिबिंबित कर सकता है। इसलिए, उन्हें मुद्रास्फीति पर घरों की प्रत्याशाओं के रूप में माना जाना चाहिए।

Q.56) निम्न में से किस स्थिति में RBI को नीति दर को उच्च स्तर पर रखने की आवश्यकता हो सकती है?
1. अर्थव्यवस्था में मुद्रास्फीति अधिक हो
2. अर्थव्यवस्था में मुद्रास्फीति की प्रत्याशा (expectation) अधिक हो

नीचे दिए गए कूट का उपयोग करके सही उत्तर चुनें
a) केवल 1
b) केवल 2
c) 1 और 2 दोनों
d) न तो 1 और न ही 2

Q.56) Solution (c)
आरबीआई रेपो दर को उच्च बनाए रखता है या अर्थव्यवस्था में मुद्रास्फीति बढ़ने पर इसे बढ़ाता है।

जब लोगों की "मुद्रास्फीति की प्रत्याशा" अधिक होती है, यानी वे उम्मीद कर रहे हैं कि भविष्य में मुद्रास्फीति बढ़ेगी, और फिर लोगों के इस तरह के व्यवहार से अंततः अर्थव्यवस्था में उच्च मुद्रास्फीति होती है जिसके कारण RBI रेपो दर को बढ़ाता है।

अतः, दोनों कथन सही हैं।

Q.57) भारत में मुद्रास्फीति लक्ष्यीकरण (Inflation targeting) के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें
1. मुद्रास्फीति का लक्ष्य सरकार द्वारा प्रत्येक चार वर्ष में एक बार RBI के परामर्श से निर्धारित किया जाता है।
2. मुद्रास्फीति लक्ष्य को उपभोक्ता मूल्य सूचकांक-संयुक्त (CPI-C) द्वारा मापा जाता है।
3. 5 अगस्त, 2016 से 31 मार्च, 2021 की अवधि के लिए मुद्रास्फीति का लक्ष्य 4% (+/-) 2% है।

उपरोक्त कथन में से कौन सा सही है / हैं?
a) केवल 1 और 2
b) केवल 2 और 3
c) केवल 1 और 3
d) केवल 3

Q.57) Solution (b)

कथन 1	कथन 2	कथन 3
असत्य	सत्य	सत्य
मुद्रास्फीति का लक्ष्य, आरबीआई के परामर्श से, **हर पांच साल में एक बार** सरकार द्वारा निर्धारित किया जाता है।	मुद्रास्फीति लक्ष्य को उपभोक्ता मूल्य सूचकांक-संयुक्त (CPI-C) द्वारा मापा जाता है	5 अगस्त, 2016 से 31 मार्च, 2021 की अवधि के लिए मुद्रास्फीति का लक्ष्य 4% (+/-) 2% है। यदि औसत मुद्रास्फीति 4% + 2% के ऊपरी सहिष्णु स्तर से अधिक है, अर्थात 6%, या 4% के निम्न सहिष्णु स्तर से कम है - 2%, जो कि 2% है, किसी भी 3 लगातार तिमाहियों के लिए, यह मुद्रास्फीति के लक्ष्य को प्राप्त करने में विफलता का अर्थ होगा।

Q.58) मुद्रास्फीति के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है?

1. मुद्रास्फीति का लाभ लेनदारों को मिलता है
2. मुद्रास्फीति का लाभ देनदारों को मिलता है
3. मुद्रास्फीति से लाभ बॉन्ड धारकों (bondholders) को मिलता है
4. मुद्रास्फीति का लाभ जमाकर्ताओं को मिलता है

नीचे दिए गए कूट का उपयोग करके सही उत्तर चुनें

a) केवल 1, 2 और 3
b) केवल 2
c) केवल 1 और 3
d) केवल 2 और 3

Q.58) Solution (d)

- लेनदार का अर्थ उस व्यक्ति से है जिसने किसी को पैसा दिया है
- कर्जदार का मतलब है जिसने किसी से पैसा लिया हो
- जमाकर्ताओं का अर्थ है, जिन्होंने बैंकों या वित्तीय संस्थानों में पैसा जमा किया है
- बॉन्ड धारकों का अर्थ उस व्यक्ति से है जो बॉन्ड धारण कर रहा है

जब कोई व्यक्ति भौतिक संपत्ति रखता है जिसकी कीमत रुपये में अंकित होती है तो वह मूल्य वृद्धि या मुद्रास्फीति से लाभान्वित होता है।

लेकिन एक व्यक्ति जो वित्तीय संपत्ति रखता है (जैसे 100 रुपये का नोट) या कोई भी वित्तीय साधन जो भविष्य में नकद भुगतान की वापसी की गारंटी देता है तो वह मूल्य वृद्धि से हानि सहता है। ऐसा इसलिए है क्योंकि मुद्रास्फीति के कारण रुपये की क्रय शक्ति घट जाती है।

इसलिए, मुद्रास्फीति के मामले में, जमाकर्ताओं, लेनदारों और बॉन्डहोल्डर्स को हानि होगी।

तो, केवल 2 कथन सही है।

Q.59) मुद्रास्फीतिक अंतराल (Inflationary Gap) के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें

1. यह वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) के मौजूदा स्तर और प्रत्याशित जीडीपी के बीच अंतर का वर्णन करता है जो कि अनुभव होगा यदि अर्थव्यवस्था पूर्ण रोजगार स्तर पर है।
2. यह तब मौजूद होता है जब समग्र रोजगार के उच्च स्तर, व्यापार गतिविधियों में वृद्धि या सरकारी व्यय में वृद्धि जैसे कारकों के कारण वस्तुओं और सेवाओं की मांग, उत्पादन से अधिक हो जाती है।

उपरोक्त कथन में से कौन सा सही है / हैं?

a) केवल 1
b) केवल 2
c) 1 और 2 दोनों
d) इनमें से कोई भी नहीं

Q.59) Solution (c)

कथन 1	कथन 2
सत्य	सत्य
एक मुद्रास्फीतिक अंतराल (Inflationary Gap) एक व्यापक आर्थिक अवधारणा है जो बीच के अंतर का वर्णन करती है वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) और प्रत्याशित जीडीपी का मौजूदा स्तर जो कि अनुभव होगा यदि कोई अर्थव्यवस्था पूर्ण रोजगार स्तर पर है, जिसे संभावित जीडीपी भी कहा जाता है। मुद्रास्फीति को अंतर मानने के लिए, वर्तमान वास्तविक जीडीपी दो मीट्रिक (two metrics) से अधिक होनी चाहिए।	मुद्रास्फीतिक अंतराल तब मौजूद होता है जब समग्र रोजगार के उच्च स्तर, व्यापार गतिविधियों में वृद्धि या सरकारी व्यय जैसे कारकों के कारण वस्तुओं और सेवाओं की मांग उत्पादन से अधिक हो जाती है। इससे वास्तविक जीडीपी संभावित जीडीपी को पार कर सकती है, जिसके परिणामस्वरूप मुद्रास्फीति में कमी होगी। मुद्रास्फीतिक अंतराल को इसलिए नाम दिया गया है क्योंकि वास्तविक जीडीपी में सापेक्ष वृद्धि के कारण अर्थव्यवस्था में उपभोग बढ़ जाता है, जिसके कारण कीमतें लंबे समय तक बढ़ती हैं।

Q.60) यदि किसी देश को मुद्रास्फीति का सामना करना पड़ रहा है, तो निम्नलिखित में से कौन अवश्य घटता है?

a) मजदूरी का स्तर
b) वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन
c) किसी दी गयी वस्तुओं और सेवाओं को खरीदने के लिए आवश्यक मुद्रा की मात्रा
d) क्रय क्षमता

Q.60) Solution (d)

जब कोई देश मुद्रास्फीति का सामना करता है, तो हमें किसी दी गयी वस्तु और सेवाओं को खरीदने के लिए अधिक मुद्रा की आवश्यकता होती है और रुपये की क्रय शक्ति कम हो जाती है। मुद्रास्फीति के मामले में आम तौर पर मजदूरी बढ़ती है लेकिन आउटपुट (उत्पादन) के बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता है।

Q.61) 'पूंजीगत संरक्षण बफर' (Capital Conservation Buffer) के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें।

1. यह अनिवार्य पूंजी है जिसे वित्तीय संस्थानों को न्यूनतम नियामक आवश्यकता से ऊपर रखने की आवश्यकता होती है।

2. पूंजी पर्याप्तता अनुपात RBI द्वारा निर्धारित किया जाता है, जबकि पूंजीगत संरक्षण बफर सरकार द्वारा निर्धारित किया जाता है।

ऊपर दिए गए कथनों में से कौन सा सही है / हैं?

a) केवल 1
b) केवल 2
c) 1 और 2 दोनों
d) न तो 1 और न ही 2

Q.61) Solution (a)

कथन 1	कथन 2
सत्य	असत्य
यह अनिवार्य पूंजी होती है, जिसे वित्तीय संस्थानों को न्यूनतम नियामक आवश्यकता से ऊपर रखने की आवश्यकता होती है। CCB के मानदंडों के अनुसार, बैंकों को कॉमन इक्विटी के रूप में 2.5% रिस्क-वेटेड एसेट्स (RWAs), 9% से अधिक को पूंजीगत पर्याप्तता अनुपात के रूप में आवश्यक बफर रखना होगा।	CCB बेसल 3 मानदंडों के आधार पर RBI द्वारा ही निर्धारित किया जाता है। इसे बैंकों के घाटे के प्रति लचीला बनाने के लिए लागू किया गया है।

Q.62) 'गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों (NBFC)' के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें।

1. कोई भी एनबीएफसी सावधि जमा (Time deposits) को स्वीकार नहीं कर सकता है।
2. एनबीएफसी उन बैंकों के विपरीत शेयर बाजार में पैसा लगा सकते हैं, जिन्हें ऐसा करने की अनुमति नहीं होती है।
3. CRR किसी भी NBFC पर लागू नहीं होता है, जबकि SLR केवल जमा (deposit) स्वीकार करने वाली NBFC के लिए लागू होता है।

ऊपर दिए गए कथनों में से कौन सा सही है / हैं?

a) केवल 1 और 2
b) केवल 1 और 3
c) केवल 2 और 3
d) उपरोक्त सभी

Q.62) Solution (c)

कथन 1	कथन 2	कथन 3
असत्य	सत्य	सत्य
एनबीएफसी मांग जमा स्वीकार नहीं कर सकते हैं, लेकिन कुछ एनबीएफसी आवधिक/ सावधि जमा को स्वीकार कर सकते हैं तथा ये जमा स्वीकार करने वाले	एनबीएफसी उन बैंकों के विपरीत शेयर बाजार में पैसा लगा सकते हैं, जिन्हें ऐसा करने की अनुमति नहीं होती है।	CRR किसी भी NBFC पर लागू नहीं होता है जबकि SLR (15% का) केवल जमा स्वीकार करने वाले NBFC के लिए लागू होता है।

(Deposit taking) एनबीएफसी कहलाते हैं।		

Q.63) 'प्राथमिकता क्षेत्र के ऋणों' के तहत निम्न में से कौन सी श्रेणी शामिल नहीं है?

a) आवास
b) स्वास्थ्य देखभाल
c) शिक्षा
d) नवीकरणीय ऊर्जा

Q.63) Solution (b)

- प्राथमिकता क्षेत्र की श्रेणियां इस प्रकार हैं
  - कृषि
  - सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम
  - शिक्षा
  - आवास
  - सामाजिक अवसंरचना
  - नवीकरणीय ऊर्जा
  - अन्य
- स्वास्थ सुविधा के निर्माण को सामाजिक अवसंरचना श्रेणी के तहत शामिल किया गया है, क्योंकि स्वास्थ्य सेवा समग्र रूप से आरबीआई की प्राथमिकता क्षेत्र की ऋण सूची में नहीं आती है।

Q.64) 'डिजिटल पब्लिक क्रेडिट रजिस्ट्री' (Digital Public Credit Registry) के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें।

1. यह व्यक्तियों और कॉर्पोरेट उधारकर्ताओं की ऋण जानकारी को संग्रहित करेगा तथा वित्तीय जानकारी के बुनियादी ढांचे के रूप में काम करेगा।
2. यह वाई.एम. देवस्थले समिति द्वारा दी गई सिफारिशों के आधार पर स्थापित किया गया था।

ऊपर दिए गए कथनों में से कौन सा सही है / हैं?

a) केवल 1
b) केवल 2
c) 1 और 2 दोनों
d) न तो 1 और न ही 2

Q.64) Solution (c)

कथन 1	**कथन 2**
सत्य	**सत्य**
यह व्यक्तियों और कॉर्पोरेट उधारकर्ताओं की ऋण जानकारी को संग्रहित करेगा तथा वित्तीय जानकारी के बुनियादी ढांचे के रूप में काम करेगा।	यह RBI द्वारा वाई.एम. देवस्थले समिति द्वारा दी गई सिफारिशों के आधार पर स्थापित किया गया था।

- यह वित्त उद्योग में विभिन्न हितधारकों और मौजूदा क्रेडिट जानकारी पारिस्थितिकी तंत्र को समृद्ध करेगा

- उपयोगी क्रेडिट जानकारी बैंकों को खराब ऋण को कम करने में मदद करेगी।

Q.65) इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक (IPPB) सरकार की एक पहल है, जिसका उद्देश्य बैंकिंग सेवाओं को लोगों के घर पर उपलब्ध कराना है। IPPB के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें

1. IPPB डाक विभाग की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी है तथा पूरी तरह से इसके द्वारा शासित होगी।
2. यह जमा स्वीकार करेगा, प्रेषण (remittance) सेवाओं, मोबाइल बैंकिंग तथा बीमा और म्यूचुअल फंड जैसी सेवाएं प्रदान करेगा।

ऊपर दिए गए कथनों में से कौन सा सही है / हैं?

a) केवल 1
b) केवल 2
c) 1 और 2 दोनों
d) न तो 1 और न ही 2

Q.65) Solution (d)

कथन 1	कथन 2
असत्य	असत्य
IPPB डाक विभाग की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी है, लेकिन यह RBI द्वारा शासित होगी क्योंकि यह भुगतान बैंक है।	यह जमा स्वीकार करेगा, प्रेषण सेवा, मोबाइल बैंकिंग प्रदान करेगा। यह अपने आप बीमा और म्यूचुअल फंड जैसी सेवाएं प्रदान नहीं करेगा, बल्कि यह बीमा और म्यूचुअल फंड जैसी तृतीय-पक्ष सेवाओं तक पहुंच प्रदान करता है।

Q.66) 'भारत 22' हाल ही में समाचारों में देखा गया है, जो किससे संबंधित है

a) एक विनिमय व्यापार फंड (Exchange Traded Fund)
b) भारत की सबसे तेज़ स्वदेशी ट्रेन
c) 2022 तक सस्ते इन्फ्लूएंजा टीका विकसित करने का मिशन
d) 2022 तक सभी असमान डिजिटल पहलों को समेकित करने का मिशन

Q.66) Solution (a)

- भारत 22 (Bharat 22) वित्त मंत्रालय द्वारा आरंभ किया गया एक एक्सचेंज ट्रेडेड फंड (ETF) है।
- ईटीएफ, या एक्सचेंज-ट्रेडेड फंड, एक बाजार योग्य प्रतिभूति है जो स्टॉक इंडेक्स, कमोडिटी, बॉन्ड या परिसंपत्तियों की एक टोकरी को ट्रैक करता है। इसका ट्रेडिंग मूल्य अंतर्निहित स्टॉक के शुद्ध परिसंपत्ति मूल्य पर आधारित होता है, जिसका यह प्रतिनिधित्व करता है।
- भारत 22 में 22 शेयर शामिल हैं, जिनमें केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यम, सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक और होल्डिंग ऑफ इंडिया के यूनिट ट्रस्ट के निर्दिष्ट उपक्रम शामिल हैं।

Q.67) गैर-निष्पादित परिसंपत्तियों (NPA) के मुद्दे को हल करने के लिए सरकार ने निम्नलिखित में से कौन से कदम उठाए हैं?

1. इन्द्रधनुष योजना
2. प्रोजेक्ट सशक्त
3. प्रोजेक्ट इनसाइट

नीचे दिए गए कूट का उपयोग करके सही उत्तर चुनें:

a) केवल 1
b) केवल 1 और 2
c) केवल 1 और 3
d) केवल 2 और 3

Q.67) Solution (b)

विकल्प 1	विकल्प 2	विकल्प 3
सत्य	सत्य	असत्य
सरकार ने अगस्त 2015 में सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों (पीएसबी) को पुनर्संरचित करने के लिए इंद्रधुनुश योजना की घोषणा की। सरकार द्वारा पीएसबी में पूंजी की आसव (infusion) की योजना को चार वित्तीय वर्षों में 70,000 करोड़ रूपए के साथ पूरा किया जायेगा।	सुनील मेहता समिति की सिफारिश के अनुसार प्रोजेक्ट सशक्त तनावग्रस्त परिसंपत्तियों के समाधान की दिशा में पाँच-स्तरीय रणनीति है। 5 दीर्घ रणनीति - • MSME दृष्टिकोण • बैंक के नेतृत्व में समाधान • IBC दृष्टिकोण • AMC नेतृत्व में समाधान • एसेट ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म (Asset trading platform)	प्रोजेक्ट इनसाइट संभावित कर अपवंचकों की जांच करने के लिए आयकर विभाग द्वारा सोशल मीडिया से बिग डेटा माइनिंग करने की एक पहल है।

Q.68) एक अर्थव्यवस्था में मौद्रिक गुणक (Money Multiplier) के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें

1. वैधानिक तरलता अनुपात में कमी के साथ मौद्रिक गुणक बढ़ता है।
2. मौद्रिक गुणक, उधार की मांग में कमी के साथ बढ़ता है।

ऊपर दिए गए कथनों में से कौन सा सही है / हैं?

a) केवल 1
b) केवल 2
c) 1 और 2 दोनों
d) न तो 1 और न ही 2

Q.68) Solution (a)

- मौद्रिक गुणक (money multiplier) वह धन है जो बैंक प्रत्येक रुपये रिज़र्व के साथ उत्पन्न करते हैं। रिज़र्व डिपॉज़िट की वह राशि होती है, जिसे सेंट्रल बैंक के अनुसार बैंकों को अपने पास रखने की आवश्यकता होती है, न कि उधार देने की। मौद्रिक गुणक बैंकिंग प्रणाली में रिज़र्व के लिए जमा का अनुपात है।

कथन 1	कथन 2

सत्य	असत्य
मौद्रिक गुणक में प्रत्यक्षतः वैधानिक आरक्षित अनुपात (एसएलआर, सीआरआर) में कमी के साथ सुधार होता है।	मौद्रिक गुणक अप्रत्यक्ष रूप से अर्थव्यवस्था के विकास, उपभोग / ऋण की मांग बढ़ने के साथ-साथ बैंकिंग पहुँच में सुधार करता है।

Q.69) 'संकीर्ण बैंकिंग' (Narrow Banking) शब्द से क्या तात्पर्य है

a) बैंक जो केवल संकीर्ण मुद्रा पर निवेश करते हैं
b) बैंक जो जोखिम-मुक्त संपत्ति में अपनी जमा के बड़े हिस्से का निवेश करते हैं
c) बैंक जो केवल कुछ विशिष्ट उद्योगों में निवेश करते हैं
d) बैंक जो केवल कुछ चुनिंदा ग्राहकों की सेवा करते हैं

Q.69) Solution (b)

- संकीर्ण बैंकिंग, जिसे सुरक्षित बैंकिंग भी कहा जाता है, में जमा के बड़े हिस्से को निवेश करना शामिल है जहाँ बैंकों को सरकारी प्रतिभूतियों आदि जैसे जोखिम-मुक्त संपत्ति में मिलते हैं।
- तारापोर समिति एनपीए के समाधान के रूप में संकीर्ण बैंकिंग की अवधारणा देने के लिए जानी जाती है।
- भारतीय बैंक आमतौर पर आंशिक संकीर्ण बैंकिंग का पालन करते हैं - एसएलआर निर्धारित प्रतिशत सुरक्षित प्रतिभूतियों में होगा। कुछ बैंक अपने जोखिम को कम करने के लिए निर्धारित एसएलआर से अधिक निवेश करते हैं।

Q.70) पंजाब और महाराष्ट्र सहकारी बैंक हाल ही में समाचारों में थे। सहकारी बैंकों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें।

1. वे आरबीआई द्वारा नियंत्रित और विनियमित होते हैं।
2. वे पूरे भारत में समान रूप से फैले हुए हैं।

ऊपर दिए गए कथनों में से कौन सा सही है / हैं?

a) केवल 1
b) केवल 2
c) 1 और 2 दोनों
d) न तो 1 और न ही 2

Q.70) Solution (d)

कथन 1	कथन 2
असत्य	असत्य
सहकारी बैंकों को आरबीआई द्वारा नियंत्रित किया जाता है तथा राज्य द्वारा नियंत्रित किया जाता है क्योंकि सहकारी समितियां राज्य सूची में हैं। इससे शक्ति में अस्पष्टता आ गई है।	लगभग 90% सहकारी समितियाँ 7 राज्यों में स्थित हैं तथा इस प्रकार असमान रूप से वितरित हैं।

Q.71) भारतीय प्रतिभूति विनिमय बोर्ड (SEBI) द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा विनियमित किया जाता है

1. उद्यम पूंजी (Venture Capital)
2. चिट फंड कंपनियां
3. पेंशन निधि

नीचे दिए गए कूट का उपयोग करके सही उत्तर चुनें:

a) केवल 1
b) केवल 1 और 2
c) केवल 3
d) इनमें से कोई भी नहीं

Q.71) Solution (a)

विकल्प 1	विकल्प 2	विकल्प 3
सत्य	असत्य	असत्य
वेंचर कैपिटल, इक्विटी खरीदकर स्टार्टअप्स का वित्तीयन होता है। वे सेबी द्वारा विनियमित होते हैं।	चिट फंड कंपनियों को राज्य सरकारों द्वारा विनियमित किया जाता है। सदस्य पैसे का योगदान करते हैं और बोली लगाने के माध्यम से अपने सदस्यों को देते हैं।	पेंशन फंड को 2003 में भारत सरकार द्वारा स्थापित पेंशन फंड नियामक और विकास प्राधिकरण (PFRDA) द्वारा विनियमित किया जाता है।

Q.72) RBI की सीमांत स्थायी सुविधा (Marginal Standing Facility- MSF) के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें

1. केवल अनुसूचित बैंक ही RBI से MSF का लाभ उठा सकते हैं।
2. MSF दर आमतौर पर रेपो दर से अधिक होती है।
3. MSF के तहत बैंक एसएलआर कोटे से 1% तक सरकारी प्रतिभूतियों में रख सकते हैं।

ऊपर दिए गए कथनों में से कौन सा सही है / हैं?

a) केवल 1 और 2
b) केवल 1 और 3
c) केवल 2 और 3
d) उपरोक्त सभी

Q.72) Solution (d)

कथन 1	कथन 2	कथन 3
सत्य	सत्य	सत्य
गैर-अनुसूचित बैंक भी रेपो दर का उपयोग करके उधार ले सकते हैं, जबकि केवल अनुसूचित बैंक ही RBI से MSF का लाभ उठा सकते हैं।	एमएसएफ दर आमतौर पर रेपो दर से 100 आधार अंक अधिक होती है।	एमएसएफ के तहत बैंक एसएलआर कोटे से 1% तक सरकारी प्रतिभूतियों में रख सकती हैं।

Q.73) डिजिटल भुगतान के संदर्भ में, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें

1. BHIM ऐप उपयोगकर्ता को केवल UPI- सक्षम बैंक खाते वाले किसी व्यक्ति को धन हस्तांतरित करने की अनुमति देता है।
2. BHIM ऐप वाणिज्यिक प्रकृति के लेनदेन की अनुमति नहीं देता है।

ऊपर दिए गए कथनों में से कौन सा सही है / हैं?

a) केवल 1
b) केवल 2
c) 1 और 2 दोनों
d) न तो 1 और न ही 2

Q.73) Solution (d)

कथन 1	कथन 2
असत्य	असत्य
BHIM ऐप उपयोगकर्ता को किसी को भी UPI-सक्षम बैंक खाते तथा बैंक खाता संख्या और IFSC कोड विवरण के माध्यम से किसी को धन हस्तांतरित करने की अनुमति देता है।	BHIM ऐप वाणिज्यिक लेनदेन का समर्थन करता है। यहां तक कि यह स्कैन और भुगतान जैसी सुविधाएं भी प्रदान करता है।

Q.74) शब्द 'शून्य कूपन बॉन्ड' किससे संबंधित है

a) बांड जो इसके अंकित मूल्य पर छूट के साथ जारी किए जाते हैं, लेकिन कोई ब्याज नहीं देते हैं।
b) बांड जो इसके अंकित मूल्य पर जारी किए जाते हैं, लेकिन ब्याज का भुगतान करते हैं।
c) बांड जो संपार्श्विक या सुरक्षा द्वारा समर्थित नहीं होते हैं।
d) यदि बांड जारी करने वाली कंपनी / इकाई दिवालिया हो जाती है तो शून्य ब्याज प्राप्त होता है।

Q.74) Solution (a)

- शून्य कूपन बॉन्ड, जिसे डिस्काउंट बॉन्ड के रूप में भी जाना जाता है, बॉन्डधारकों को कोई ब्याज नहीं देते हैं। इसके बजाय, आपको बांड के अंकित मूल्य पर बड़ी छूट मिलती है।
- परिपक्वता पर, बांडधारक को अपने निवेश का अंकित मूल्य प्राप्त होता है।
- भारत में ट्रेजरी बिल जीरो कूपन बॉन्ड का एक उदाहरण है।

Q.75) ट्रेजरी बिल के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें

1. ट्रेजरी बिल केवल सरकारी खजाने (ट्रेज़री) द्वारा जारी की जाने वाली प्रतिभूतियां हैं।
2. व्यक्ति, फर्म, ट्रस्ट, संस्थान और बैंक ट्रेजरी बिल खरीद सकते हैं।

ऊपर दिए गए कथनों में से कौन सा सही है / हैं?

a) केवल 1
b) केवल 2
c) 1 और 2 दोनों
d) न तो 1 और न ही 2

Q.75) Solution (c)

कथन 1	कथन 2
सत्य	सत्य

ट्रेजरी बिल केवल केंद्र सरकार द्वारा उधार लिए गए अल्पावधि (एक वर्ष से कम की परिपक्वता) के लिए साधन हैं। ट्रेजरी बिल के अलावा अन्य बिलों को वाणिज्यिक बिल के रूप में जाना जाता है।	व्यक्ति, फर्म, ट्रस्ट, संस्थान और बैंक T-Bills खरीद सकते हैं। वाणिज्यिक और सहकारी बैंक अपनी एसएलआर आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए टी-बिल का उपयोग करते हैं।

Q.76) पार्टिसिपेटरी नोट्स (पी-नोट्स) के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है?

a) पी-नोट विदेशी निवेशकों के लिए सेबी द्वारा जारी किए गए उपकरण हैं जो भारत के शेयर बाजारों में निवेश करना चाहते हैं।
b) कोई भी इकाई सेबी के तहत पंजीकरण के बिना पार्टिसिपेटरी नोटों में निवेश कर सकती है।
c) पार्टिसिपेटरी नोट देश में व्यापार को आसान बनाने वाले अनुमोदनों और वितरण के माध्यम से हस्तांतरणीय हैं।
d) पी-नोट्स लेन-देन की लागत को कम करने के साथ-साथ निवेशक का नाम गुमनाम रखने में भी मदद करते हैं।

Q.76) Solution (a)

- पार्टिसिपेटरी नोट्स जिन्हें पी-नोट्स (पीएन) भी माना जाता है, पंजीकृत एफआईआई द्वारा जारी किए गए उपकरण हैं।
- उनका उपयोग विदेशी संस्थागत निवेशकों (एफआईआई) के ग्राहकों द्वारा किया जाता है जो सीधे भारतीय शेयर बाजार में भाग नहीं लेना चाहते हैं।
- कोई भी इकाई सेबी के तहत पंजीकरण के बिना पार्टिसिपेटरी नोटों में निवेश कर सकती है जबकि सेबी के तहत पंजीकरण सभी एफआईआई के लिए अनिवार्य है।
- विदेशी संस्थागत निवेशक (एफआईआई) भारत के बाहर स्थापित संस्थाएं हैं जो भारत में निवेश प्रस्ताव बनाने के लिए उत्तरदायी होते हैं।

Q.77) निम्नलिखित में से कौन भारत में तत्काल भुगतान सेवा (IMPS) प्रदान करता है?

a) भारतीय बैंकों का संघ
b) नेशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड
c) भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम
d) भारतीय रिजर्व बैंक

Q.77) Solution (c)

भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम (NPCI)

- भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम (NPCI) भारतीय रिज़र्व बैंक और भारतीय बैंक संघ (IBA) द्वारा भारत में खुदरा भुगतान और निपटान प्रणाली को संचालित करने के लिए एक पहल है।
- भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम (NPCI) भारत में खुदरा भुगतान के संचालन के लिए एक अम्ब्रेला निकाय के रूप में कार्य करता है।
- एनपीसीआई निम्नलिखित भुगतान प्रणाली को संचालित कर सकता है:
  - राष्ट्रीय वित्तीय स्विच (NFS)
  - तत्काल भुगतान प्रणाली (IMPS)
  - राष्ट्रीय स्वचालित समाशोधन गृह (ACH)

  - आधार सक्षम भुगतान प्रणाली (AEPS)
  - चेक ट्रंकेशन सिस्टम का संचालन
- एनपीसीआई के उत्पाद
  - RuPay
  - BHIM ऐप
  - UPI
  - भारत बिल भुगतान प्रणाली

Q.78) कई सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों का विलय हाल ही में समाचारों में था। निम्नलिखित में से बैंकों के विलय के क्या लाभ हैं?

1. बैंक की परिचालन लागत को कम करता है।
2. बाजार से संसाधन जुटाने की बेहतर क्षमता होती है।
3. बैंक की सभी गैर-निष्पादित संपत्तियों (एनपीए) को समाप्त करता है।

नीचे दिए गए कूट का उपयोग करके सही उत्तर चुनें:

a) केवल 1 और 2
b) केवल 1 और 3
c) केवल 2 और 3
d) उपरोक्त सभी

Q.78) Solution (a)

कथन 1	कथन 2	कथन 3
सत्य	सत्य	असत्य
बैंकों के विलय में साझा ओवरलैपिंग नेटवर्क की उपस्थिति के कारण परिचालन लागत को कम करने की क्षमता होती है। यह बढ़ी हुई परिचालन दक्षता बैंकों की ऋण लागत को कम करेगी।	बड़े बैंकों में राज्य के खजाने पर निर्भर होने के बजाय बाजार से संसाधन जुटाने की बेहतर क्षमता होती है।	बैंकों का विलय विलय वाले बैंक के एनपीए को समाप्त नहीं करता है। हालांकि, यह एनपीए को कम करने में मदद करेगा क्योंकि बड़े बैंक के पास बड़ी पूंजी होगी।

Q.79) डिजिटल लेनदेन के लिए लोकपाल (Ombudsman for Digital Transactions- OSDT) किसके द्वारा स्थापित किया गया है

a) इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय
b) वित्त मत्रांलय
c) भारतीय रिजर्व बैंक
d) उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय

Q.79) Solution(c)

डिजिटल लेनदेन के लिए लोकपाल योजना

- डिजिटल लेनदेन के लिए लोकपाल भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा ग्राहकों की शिकायतों के निवारण के लिए नियुक्त एक वरिष्ठ अधिकारी है।

- यह भुगतान और निपटान प्रणाली अधिनियम, 2007 के तहत स्थापित किया गया है।
- ग्राहकों की शिकायतों को दर्ज / हल करने के लिए कोई शुल्क या कोई फीस नहीं है।

Q.80) इन्फ्रास्ट्रक्चर लीजिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज (IL&FS) हाल ही में समाचारों में था। IL&FS के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें

1. यह एक व्यवस्थित रूप से महत्वपूर्ण गैर-जमा (Non-Deposit) कोर निवेश कंपनी (CIC-ND-SI) है।
2. यह पूरी तरह से भारत सरकार के स्वामित्व में है।

ऊपर दिए गए कथनों में से कौन सा सही है / हैं?

a) केवल 1
b) केवल 2
c) 1 और 2 दोनों
d) न तो 1 और न ही 2

Q.80) Solution (a)

कथन 1	कथन 2
सत्य	असत्य
IL&FS एक व्यवस्थित रूप से महत्वपूर्ण गैर-जमा कोर निवेश कंपनी (CIC-ND-SI) है। यह एक एनबीएफसी है।	IL&FS का स्वामित्व GOI के पास नहीं है। इसके कई शेयरधारक हैं जैसे LIC, SBI, अबू धाबी निवेश प्राधिकरण आदि।

Q.81) वित्तीय स्थिरता और विकास परिषद की अध्यक्षता कौन करता है

a) वित्त मंत्री
b) आरबीआई गवर्नर
c) वित्त सचिव
d) प्रधान मंत्री

Q.81) Solution (a)

वित्तीय स्थिरता और विकास परिषद (FSDC)

- एफएसडीसी वित्त मंत्री की अध्यक्षता वाले क्षेत्रक नियामकों (sectoral regulators) का सर्वोच्च निकाय है।
- सभी वित्तीय क्षेत्रक नियामक प्राधिकरणों जैसे कि RBI, SEBI, IRDA, PFRDA आदि के प्रमुख, FSDC के सदस्य होते हैं।
- राज्य मंत्री, आर्थिक मामलों के विभाग के प्रभारी तथा इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के सचिव, परिषद में नए जोड़े गए हैं।

Q.82) भारत के कर संग्रह के बारे में, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें

1. व्यक्तिगत आयकर का हिस्सा पिछले पांच वर्षों से लगातार बढ़ा है।
2. निगम कर का हिस्सा वर्ष 2019-20 के लिए वस्तु एवं सेवा कर की हिस्सेदारी से अधिक है।

नीचे दिए गए कूट का उपयोग करके सही उत्तर चुनें

a) केवल 1
b) केवल 2
c) 1 और 2 दोनों
d) न तो 1 और न ही 2

Q.82) Solution (a)

कथन 1	कथन 2
सत्य	असत्य
व्यक्तिगत आयकर का हिस्सा पिछले पांच वर्षों से लगातार बढ़ा है।	निगम कर की हिस्सेदारी वर्ष 2019-20 के लिए वस्तु एवं सेवा कर की हिस्सेदारी से कम है

Q.83) छोटी बचत योजनाओं, भविष्य निधि योजनाओं के माध्यम से संचित धन कहाँ रखा जाता है

a) भारतीय समेकित कोष
b) भारतीय सार्वजानिक खाते
c) भारतीय आकस्मिकता निधि
d) संबंधित राज्य के समेकित निधि

Q.83) Solution (b)

- भारतीय सार्वजनिक खाता संविधान के अनुच्छेद 266 (2) के तहत स्थापित किया गया है।
- भारत के समेकित कोष में शामिल धन के अलावा प्राप्त सभी सार्वजनिक धन भारत के सार्वजानिक खाते में आयोजित किए जाते हैं।
- इस खाते में मुख्य रूप से छोटी बचत योजनाओं, भविष्य निधि योजनाओं आदि के माध्यम से धन संचित किया जाता है।
- सरकार केवल इन फंडों की संरक्षक होती है। इसे या तो परिपक्वता तिथि पर या जब भी लोगों द्वारा दावा किया जाता है, चुकाना पड़ता है।

Q.84) निम्नलिखित में से किसे सरकार के गैर-कर राजस्व प्राप्तियों (Non-Tax Revenue receipts) के रूप में माना जाता है

1. स्थायी संपत्ति के निपटान के कारण प्राप्तियां
2. मुद्रा और सिक्कों के प्रचलन से लाभ।
3. निजी उद्यमों में सरकारों द्वारा रखे गए शेयरों से लाभांश।

ऊपर दिए गए कथनों में से कौन सा सही है / हैं?

a) केवल 1 और 2
b) केवल 1 और 3
c) केवल 2 और 3
d) उपरोक्त सभी

Q.84) Solution (c)

कथन 1	कथन 2	कथन 3
असत्य	सत्य	सत्य
स्थायी संपत्ति के निपटान के कारण प्राप्तियां, पूंजीगत प्राप्तियों का हिस्सा होती हैं।	मुद्रा, सिक्का और टकसाल अन्य गैर-कर प्राप्तियों की वित्तीय सेवाओं के तहत आते हैं।	गैर-कर राजस्व - लाभांश निजी उद्यमों में सरकारों द्वारा रखे गए शेयरों से आय है।

गैर-कर राजस्व प्राप्तियां

- ब्याज प्राप्तियां
- लाभांश और लाभ
- मुद्रा, सिक्का, टकसाल
- सामाजिक सेवा
- सहायता अंशदान में अनुदान
- आर्थिक सेवाएँ

पूंजीगत प्राप्तियां

- स्थायी संपत्ति के निपटान के कारण प्राप्तियां
- दूसरों को दिए गए ऋणों की वसूली
- सरकार द्वारा लिया गया उधार

Q.85) स्थायी संपत्ति बनाने तथा समय-समय पर आय अर्जित करने वाले व्यय को कहा जाता है

a) राजस्व व्यय
b) परिसंपत्ति व्यय
c) पूंजीगत व्यय
d) प्राथमिक व्यय

Q.85) Solution (c)

- पूंजीगत व्यय, वे व्यय हैं
  - जो स्थायी संपत्ति बनाते हैं और समय-समय पर आय देते हैं।
  - राज्य सरकारों और स्थानीय निकायों को ऋण के रूप में दिए जाते हैं।
- यह दो तरफा भुगतान होते हैं। इसका मतलब है कि व्यय किए गए धन को आवधिक आय और / या बनाई गई संपत्ति के निपटान के माध्यम से वापस प्राप्त किया जा सकता है।

Q.86) राजकोषीय घाटे (Fiscal deficit) को संदर्भित करता है

a) उधार को छोड़कर, सरकार की कुल प्राप्तियों और कुल व्यय के बीच अंतर।
b) राजस्व प्राप्तियों और राजस्व व्यय के बीच अंतर।
c) ब्याज आय और भुगतान को छोड़कर सरकार की कुल आय और व्यय के बीच अंतर।
d) इनमें से कोई भी नहीं

Q.86) Solution (a)

राजकोषीय घाटा	उधार को छोड़कर, सरकार की कुल प्राप्तियों और कुल व्यय के बीच अंतर।
राजस्व घाटा	राजस्व प्राप्तियों और राजस्व व्यय के बीच अंतर।
प्राथमिक घाटा	ब्याज आय और भुगतान को छोड़कर सरकार की कुल आय और व्यय के बीच अंतर।

राजकोषीय घाटा

- राजकोषीय घाटा एक आर्थिक क्रिया है, जहां सरकार का कुल व्यय उत्पन्न राजस्व से अधिक होती है।
- राजकोषीय घाटा सरकार को सभी स्रोतों से कुल उधार आवश्यकताओं के बारे में संकेत देता है।

Q.87) निम्नलिखित कथनों पर विचार करें

1. कर प्लवनशीलता (Tax Buoyancy) जीडीपी में परिवर्तन के लिए कर राजस्व वृद्धि की जवाबदेही को संदर्भित करता है।
2. कर लोचशीलता (Tax elasticity) में कर दर में परिवर्तन के प्रतिउत्तर में कर राजस्व में परिवर्तन को संदर्भित करता है।

नीचे दिए गए कूट का उपयोग करके सही उत्तर चुनें

a) केवल 1
b) केवल 2
c) 1 और 2 दोनों
d) न तो 1 और न ही 2

Q.87) Solution (c)

कथन 1	**कथन 2**
सत्य	**सत्य**

कर प्लवनशीलता (Tax Buoyancy) जीडीपी में परिवर्तन के लिए कर राजस्व वृद्धि की जवाबदेही को संदर्भित करता है। कर प्लवनशीलता = कर राजस्व में परिवर्तन / सकल घरेलू उत्पाद में अनुपात में परिवर्तन का अनुपात।	कर लोचशीलता (Tax elasticity) में कर दर में परिवर्तन के प्रतिउत्तर में कर राजस्व में परिवर्तन को संदर्भित करता है।

Q.88) वस्तु एवं सेवा कर (GST) निम्नलिखित में से किस पर लागू होता है?

1. एक कर्मचारी द्वारा नियोक्ता को उसके रोजगार के संबंध में सेवाएं।
2. एक नए भवन के निर्माण में एक बिल्डर द्वारा सेवाएं।
3. दूध बूथों और किराने की दुकानों में उपलब्ध स्वादिष्ट दूध (flavoured milk)।

ऊपर दिए गए कथनों में से कौन सा सही है / हैं?

a) केवल 1 और 2
b) केवल 1 और 3
c) केवल 2 और 3
d) उपरोक्त सभी

Q.88) Solution (c)

विकल्प 1	विकल्प 2	विकल्प 3
असत्य	सत्य	सत्य
एक कर्मचारी द्वारा नियोक्ता को उसके रोजगार के संबंध में सेवाएं जीएसटी के अंतर्गत नहीं आती हैं। हालांकि, कर्मचारी कमाए गए वेतन पर आयकर का भुगतान करेगा।	एक नए भवन का निर्माण जीएसटी (कार्य अनुबंध होने के नाते) के अधीन है।	गैर-स्वाद वाले दूध और दूध पाउडर को जीएसटी से छूट दी गई है लेकिन स्वादिष्ट दूध पर 12% स्लैब के तहत जीएसटी कर लगाया जाता है।

Q.89) विनिवेश (Disinvestment) के संबंध में, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें

1. कार्यवाही राष्ट्रीय निवेश कोष में अलग से की जाती है।
2. निजी क्षेत्र को स्वामित्व और नियंत्रण का हस्तांतरण रणनीतिक विनिवेश के रूप में जाना जाता है।

नीचे दिए गए कूट का उपयोग करके सही उत्तर चुनें

a) केवल 1
b) केवल 2
c) 1 और 2 दोनों
d) न तो 1 और न ही 2

Q.89) Solution (c)

कथन 1	कथन 2
सत्य	सत्य
कार्यवाही राष्ट्रीय निवेश कोष में अलग से की जाती	रणनीतिक विनिवेश किसी अन्य इकाई (ज्यादातर

है। अर्जित निधि का उपयोग चयनित केंद्रीय सामाजिक कल्याण योजनाओं के लिए किया जाता है। यह कोष भारत के समेकित कोष से बाहर रखा गया है।	निजी क्षेत्र की इकाई) के लिए सार्वजनिक क्षेत्र की इकाई के स्वामित्व और नियंत्रण का हस्तांतरण है। साधारण विनिवेश के विपरीत, रणनीतिक विनिवेश का अर्थ एक तरह का निजीकरण है।

Q.90) निम्नलिखित में से कौन सा कथन, एफआरबीएम अधिनियम समीक्षा समिति की सिफारिशें हैं?

1. सरकार को सलाह देने के लिए राजकोषीय परिषद का गठन।
2. राजकोषीय नीति के लिए सार्वजनिक ऋण से जीडीपी अनुपात (Public debt to GDP ratio) को एक मध्यम अवधि के उद्घोषक के रूप में माना जाता है।
3. एफआरबीएम अधिनियम को ऋण प्रबंधन और राजकोषीय उत्तरदायित्व अधिनियम से प्रतिस्थापित किया जाए।

ऊपर दिए गए कथनों में से कौन सा सही है / हैं?

a) केवल 1 और 2
b) केवल 1 और 3
c) केवल 2 और 3
d) उपरोक्त सभी

Q.90) Solution (d)

कथन 1	कथन 2	कथन 3
सत्य	सत्य	सत्य
'राजकोषीय परिषद' की स्थापना, एक स्वतंत्र निकाय, जो किसी भी वर्ष के लिए सरकार की राजकोषीय घोषणाओं की निगरानी का काम करेगा।	राजकोषीय नीति के लिए सार्वजनिक ऋण से जीडीपी अनुपात को एक मध्यम अवधि के एंकर के रूप में माना जाता है। केंद्र सरकार के लिए 38.7% का ऋण-से-जीडीपी अनुपात है, यह राज्य सरकारों के लिए 20% है	एफआरबीएम अधिनियम को ऋण प्रबंधन और राजकोषीय उत्तरदायित्व अधिनियम से प्रतिस्थापित किया जाए।

Q.91) अग्रिम मूल्य समझौता (Advance pricing Agreement) के बारे में, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें

1. यह एक करदाता और कर प्राधिकरण के बीच एक संभावित समझौता है।
2. इसका उपयोग भविष्य के विवादों से बचने के लिए करदाताओं के अंतरराष्ट्रीय लेनदेन के मामले में हस्तांतरण मूल्य निर्धारण पद्धति और देनदारियों के निर्धारण के लिए किया जाता है।

नीचे दिए गए कूट का उपयोग करके सही उत्तर चुनें

a) केवल 1
b) केवल 2
c) 1 और 2 दोनों
d) न तो 1 और न ही 2

Q.91) Solution (c)

कथन 1	कथन 2
सत्य	सत्य
यह एक करदाता और कर प्राधिकरण के बीच एक संभावित समझौता है। हाल ही में केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड ने कई संस्थाओं के साथ एक एपीए पर हस्ताक्षर किए हैं।	इसका उपयोग भविष्य के विवादों से बचने के लिए करदाताओं के अंतरराष्ट्रीय लेनदेन के मामले में हस्तांतरण मूल्य निर्धारण पद्धति और देनदारियों के निर्धारण के लिए किया जाता है। यह बेहतर अनुपालन के साथ-साथ बेहतर कर निगरानी दोनों में मदद करता है।

Q.92) निम्नलिखित में से कौन 15 वें वित्त आयोग के संदर्भ की शर्तें (terms of reference) हैं

1. राज्य सरकारों द्वारा प्रत्यक्ष लाभ अंतरण को अपनाना।
2. बिजली क्षेत्र में हानि का उन्मूलन।
3. जीएसटी के विस्तार के लिए किए गए प्रयास।

ऊपर दिए गए कथनों में से कौन सा सही है / हैं?

a) केवल 1 और 2
b) केवल 1 और 3
c) केवल 2 और 3
d) उपरोक्त सभी

Q.92) Solution (d)

15 वां वित्त आयोग - संदर्भ की शर्तें (Terms of reference)

- जीएसटी के विस्तार के लिए किए गए प्रयास
- जनसंख्या नियंत्रण के उपाय
- बिजली क्षेत्र में हानि का उन्मूलन
- प्रत्यक्ष लाभ अंतरण को अपनाना
- स्थानीय निकायों को अनुदान
- स्वच्छता और ठोस अपशिष्ट प्रबंधन में प्रगति
- लोकलुभावन उपायों पर नियंत्रण।

Q.93) वित्तीय समावेशन सूचकांक (Financial Inclusion Index) के बारे में, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें

1. यह राज्यों को अंतिम-छोर तक बैंकिंग सेवा उपलब्धता पर उनके प्रदर्शन पर आधारित होता है।
2. यह भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी किया गया है।

नीचे दिए गए कूट का उपयोग करके सही उत्तर चुनें

a) केवल 1
b) केवल 2
c) 1 और 2 दोनों
d) न तो 1 और न ही 2

Q.93) Solution (a)

कथन 1	कथन 2
सत्य	असत्य
एफआईआई राज्यों को अंतिम-छोर तक बैंकिंग सेवा उपलब्धता पर उनके प्रदर्शन पर आधारित होता है। 3 आयाम - पहुंच, उपयोग और गुणवत्ता	यह वित्तीय सेवा विभाग, वित्त मंत्रालय द्वारा जारी किया जाता है।

Q.94) आधार क्षरण और लाभ हस्तांतरण (BEPS) परियोजना के बारे में, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें

1. यह परियोजना बीईपीएस से निपटने के लिए ओईसीडी का एक परिणाम है।
2. भारत ने कर चोरी की जाँच पर ओईसीडी की परियोजना को लागू करने के लिए बहुपक्षीय कन्वेंशन की पुष्टि की है।

नीचे दिए गए कूट का उपयोग करके सही उत्तर चुनें

a) केवल 1
b) केवल 2
c) 1 और 2 दोनों
d) न तो 1 और न ही 2

Q.94) Solution (c)

कथन 1	कथन 2
सत्य	सत्य
आधार क्षरण और लाभ हस्तांतरण (BEPS) से निपटने के लिए यह परियोजना आर्थिक सहयोग और विकास संगठन (OECD) / G20 का एक परिणाम है।	भारत इस परियोजना का संस्थापक सदस्य था। भारत ने 2016 में इस कन्वेंशन पर हस्ताक्षर किए थे।

Q.95) निम्न में से किसे पिगोवियन कर (Pigovian tax) माना जाता है

a) अमीरों पर संपत्ति कर
b) कोयले पर स्वच्छ ऊर्जा उपकर
c) विलासिता की वस्तुओं पर वस्तु एवं सेवा कर
d) इनमें से कोई भी नहीं

Q.95) Solution (b)

पिगोवियन कर (Pigovian tax)

- एक पिगोवियन (Pigouvian) कर एक ऐसा कर है, जिसका मूल्यांकन निजी व्यक्तियों या व्यवसायों के खिलाफ उन गतिविधियों में संलग्न होने के लिए किया जाता है, जो समाज के लिए प्रतिकूल प्रभाव पैदा करते हैं।
- इनमें पर्यावरण प्रदूषण, तंबाकू उत्पादों की बिक्री से सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवा पर दबाव तथा बाहरी, नकारात्मक प्रभाव डालने वाले अन्य दुष्प्रभाव शामिल होते हैं।
- पिगोवियन कर का अर्थ उन गतिविधियों को हतोत्साहित करना है जो उत्पादन की लागत को तीसरे पक्ष और समाज पर एक संपूर्ण के रूप में लगाती हैं।

Q.96) बैंकिंग पर्यवेक्षण पर बेसल समिति (BCBS) के बारे में, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें।

1. यह अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष (आईएमएफ) के तहत एक समिति है।
2. बीसीबीएस द्वारा विकसित बेसल III उपायों का उद्देश्य बैंकों के विनियमन, पर्यवेक्षण और जोखिम प्रबंधन को सुदृढ़ करना है।

नीचे दिए गए कूट का उपयोग करके सही उत्तर चुनें

a) केवल 1
b) केवल 2
c) 1 और 2 दोनों
d) न तो 1 और न ही 2

Q.96) Solution (b)

कथन 1	कथन 2
असत्य	सत्य
यह बैंक फॉर इंटरनेशनल सेटलमेंट्स के तहत एक समिति है। बैंकिंग पर्यवेक्षण पर बेसल समिति (BCBS) बैंकों के विवेकपूर्ण नियमन के लिए प्राथमिक वैश्विक मानक-सेटर है	बैंकिंग पर्यवेक्षण पर बेसल समिति (BCBS) द्वारा विकसित बेसल III उपायों का उद्देश्य बैंकों के विनियमन, पर्यवेक्षण और जोखिम प्रबंधन को सुदृढ़ करना है।

Q.97) निम्नलिखित कथनों पर विचार करें

1. लोकसभा में बिना किसी चर्चा के लेखानुदान (Vote on account) पारित किया जाता है
2. पूर्ण बजट, व्यय और राजस्व पक्ष दोनों से संबंधित होता है, लेकिन लेखानुदान केवल सरकार के बजट के व्यय पक्ष से संबंधित होता है
3. चुनावी वर्ष में सरकार को लेखानुदान प्रस्तुत करना अनिवार्य नहीं होता है

उपरोक्त कथनों में से कौन सा सही हैं?

a) केवल 1 और 2
b) केवल 2 और 3
c) केवल 1 और 3
d) उपरोक्त सभी

Q.97) Solution (d)

लेखानुदान अनुदान देने तथा विनियोग विधेयक और वित्त विधेयक के पारित होने तक सरकार को कार्यप्रणाली संचालित करने में सक्षम बनाने के लिए अग्रिम रूप में एक अनुदान है। यह सरकार को कम समय के लिए या एक पूर्ण-बजट पारित होने तक खर्च करने में सक्षम बनाता है। एक कन्वेंशन के रूप में, एक लेखानुदान को औपचारिक मामला माना जाता है और बिना चर्चा के लोकसभा द्वारा पारित किया जाता है।

पूर्ण बजट और लेखानुदान के बीच अंतर

पूर्ण बजट, व्यय और राजस्व पक्ष दोनों से संबंधित है, लेकिन लेखानुदान केवल सरकार के बजट के व्यय पक्ष से संबंधित है।

लेखानुदान आम तौर पर दो महीने के लिए वैध होता है लेकिन एक पूर्ण बजट 12 महीने (एक वित्तीय वर्ष) के लिए मान्य होता है।

एक लेखानुदान प्रत्यक्ष करों में बदलाव नहीं कर सकता क्योंकि उन्हें एक वित्त बिल के माध्यम से पारित करने की आवश्यकता होती है। नियमित बजट के तहत, नए कर लगाए जा सकते हैं और पुराने समाप्त किये जा सकते हैं।

सभी व्यावहारिक अर्थों में एक अंतरिम बजट एक पूर्ण बजट होता है लेकिन सरकार द्वारा अपने कार्यकाल के अंतिम वर्ष के दौरान - अर्थात् चुनाव से ठीक पहले बनाया गया होता है। एक अंतरिम बजट खातों का एक पूरा सेट है, जिसमें व्यय और प्राप्तियां दोनों शामिल होती हैं। लेकिन इसमें बड़े नीतिगत प्रस्ताव नहीं हो सकते हैं।

चुनावी वर्ष में सरकार को लेखानुदान प्रस्तुत करना अनिवार्य नहीं होता है।

Q.98) आभासी मुद्राओं (Virtual Currencies) पर अंतर-मंत्रालयी समिति की अध्यक्षता किसके द्वारा की गई थी

a) उदय कोटक समिति
b) नंदन नीलेकणी समिति
c) नचिकेत मोर समिति
d) सुभाष चंद्र गर्ग

Q.98) Solution (d)

- आभासी मुद्राओं पर अंतर-मंत्रालयी समिति की अध्यक्षता वित्त सचिव सुभाष चंद्र गर्ग ने की थी।
- **मुख्य सिफारिशें**
  - निजी क्रिप्टो-मुद्राओं के सभी रूपों पर प्रतिबंध।
  - देश में एक आधिकारिक डिजिटल मुद्रा की शुरूआत को देखना।
  - डेटा संरक्षण विधेयक में प्रस्तावित डेटा स्थानीयकरण आवश्यकताओं को सावधानीपूर्वक लागू करने की आवश्यकता हो सकती है।
- केंद्र द्वारा गठित समिति ने एक मसौदा विधेयक-क्रिप्टो-मुद्रा का प्रतिबंध और आधिकारिक डिजिटल मुद्रा विधेयक, 2019 के विनियमन 'का भी प्रस्ताव किया है।

Q.99) भारत सरकार ने हाल ही में नई दिल्ली अंतर्राष्ट्रीय मध्यस्थता केंद्र (NDIAC) की स्थापना के लिए मसौदा नियम जारी किए हैं। NDIAC के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें

1. NDIAC एक पेशेवर रूप से मध्यस्थता और सुलह के संचालन की सुविधा प्रदान करेगा।
2. NDIAC अधिनियम NDIAC को राष्ट्रीय महत्व की संस्था घोषित करता है।

नीचे दिए गए कूट का उपयोग करके सही उत्तर चुनें

a) केवल 1
b) केवल 2
c) 1 और 2 दोनों
d) न तो 1 और न ही 2

Q.99) Solution (c)

कथन 1	कथन 2

सत्य	सत्य
NDIAC एक पेशेवर, लागत प्रभावी और समय पर ढंग से मध्यस्थता और सुलह के संचालन की सुविधा प्रदान करेगा।	NDIAC अधिनियम, 2019 में संसद द्वारा पारित किया गया था। यह NDIAC को राष्ट्रीय महत्व के संस्थान के रूप में घोषित करता है।

- NDIAC अधिनियम ने मौजूदा अंतर्राष्ट्रीय केंद्र वैकल्पिक विवाद समाधान (ICADR) को केंद्र सरकार को हस्तांतरित कर दिया है।
- NDIAC मध्यस्थता का एक स्थायी पैनल बनाए रखेगा जो चैंबर ऑफ़ आर्बिट्रेशन की स्थापना करेगा।
- NDIAC मध्यस्थों को प्रशिक्षित करने तथा वैकल्पिक विवाद समाधान के क्षेत्र में अनुसंधान करने के लिए एक मध्यस्थता अकादमी भी स्थापित कर सकता है।

Q.100) मानक कटौती (Standard Deduction) के बारे में, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें

1. यह वेतनभोगी व्यक्तियों को उन खर्चों के लिए आय से एक फ्लैट कटौती का दावा करने की अनुमति देता है, जो उसके या उसके रोजगार के संबंध में खर्च होंगे
2. इस कटौती का दावा करने के लिए किसी प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती है
3. इसे पहली बार बजट 2019 में प्रस्तुत किया गया था

उपरोक्त कथनों में से कौन सा सही हैं?

a) केवल 1 और 2
b) केवल 2 और 3
c) केवल 1 और 3
d) उपरोक्त सभी

Q.100) Solution (a)

कथन 1	कथन 2	कथन 3
सत्य	सत्य	असत्य
अपने बजट 2018 के भाषण में, वित्त मंत्री ने कर्मचारियों को वेतन आय से 40,000 रुपये की मानक कटौती प्रदान करने (पुनः प्रदान करने) का प्रस्ताव दिया था। मानक कटौती से वेतनभोगी व्यक्तियों को अपने या अपने रोजगार के संबंध में होने वाले खर्चों के लिए आय से एक फ्लैट कटौती का दावा करने की अनुमति मिलती है।	इस कटौती का दावा करने के लिए किसी प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती है।	वर्ष 1974 में आयकर अधिनियम की धारा 16 के तहत वेतनभोगी करदाताओं के लिए मानक कटौती की शुरुआत की गई थी, लेकिन बाद में आकलन वर्ष 2006-07 से इसे समाप्त कर दिया गया। पूर्व केंद्रीय वित्त मंत्री पी. चिदंबरम द्वारा मानक कटौती को वापस लेने का यह निर्णय इस आधार पर लिया गया था कि बुनियादी छूट सीमा और धारा 80C की कटौती में बराबर वृद्धि हुई है। वेतनभोगी कर्मचारियों के लिए

		कर योग्य वेतन मानक कटौती के कारण नीचे आ जाएगा।

Q.101) पेंशन फंड नियामक और विकास प्राधिकरण (PFRDA) के बारे में, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें।

1. यह PFRDA अधिनियम, 2003 के तहत स्थापित एक वैधानिक निकाय है।
2. यह राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली (NPS) का प्रबंधन और नियमन करता है।

नीचे दिए गए कूट का उपयोग करके सही उत्तर चुनें

a) केवल 1
b) केवल 2
c) 1 और 2 दोनों
d) न तो 1 और न ही 2

Q.101) Solution (c)

कथन 1	कथन 2
सत्य	सत्य
यह PFRDA अधिनियम, 2003 के तहत स्थापित एक वैधानिक निकाय है। यह वित्तीय सेवा विभाग, वित्त मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण में है।	PFRDA भारत का एक पेंशन नियामक है। यह राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली (एनपीएस) का प्रबंधन और नियमन करता है तथा अटल पेंशन योजना (एपीवाई) को भी प्रशासित करता है।

Q.102) राष्ट्रीय वित्तीय रिपोर्टिंग प्राधिकरण (NFRA) के बारे में, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें।

1. यह ऑडिटिंग पेशे की देखरेख करने वाला एक स्वतंत्र नियामक होगा।
2. इसमें सिविल न्यायालय के समान शक्तियां होंगी।
3. इसमें कंपनी अधिनियम 2013 के तहत पंजीकृत किसी भी कंपनी की जांच करने की शक्ति होगी।

ऊपर दिए गए कथनों में से कौन सा सही है / हैं?

a) केवल 1 और 2
b) केवल 1 और 3
c) केवल 2 और 3
d) उपरोक्त सभी

Q.102) Solution (a)

- ऑडिट फर्में हाल ही में पंजाब नेशनल बैंक धोखाधड़ी मामले जैसे विभिन्न कॉर्पोरेट घोटालों में कथित चूक के लिए जांच के दायरे में है।
- इस प्रकार केंद्रीय मंत्रिमंडल ने राष्ट्रीय वित्तीय रिपोर्टिंग प्राधिकरण (NFRA) की स्थापना के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है।
- एनएफआरए का निर्माण कंपनी अधिनियम, 2013 द्वारा लाया गया प्रमुख परिवर्तनों में से एक था।
- NFRA ऑडिटिंग पेशे के लिए एक स्वतंत्र नियामक के रूप में कार्य करेगा।

कथन 1	कथन 2	कथन 3
सत्य	सत्य	असत्य
NFRA ऑडिटिंग पेशे की देखरेख करने वाला एक स्वतंत्र नियामक होगा। यह इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया (आईसीएआई) से सभी अधिकार लेगा।	इसमें सिविल कोर्ट के समान शक्तियां होंगी।	इसमें चार्टर्ड अकाउंटेंट एक्ट, 1949 के तहत पंजीकृत ऑडिटर्स की जांच करने की शक्ति होगी

Q.103) निम्नलिखित युग्मों पर विचार करें

	समिति	अध्यक्ष
1	म्युनिसिपल बांड विकास समिति	सुजीत प्रसाद
2	प्राथमिक बाजार सलाहकार समिति	जयंत आर वर्मा
3	द्वितीयक बाजार सलाहकार समिति	टी वी मोहनदास पई

ऊपर दी गई कौन सी जोड़ी गलत तरीके से मेल खाती है?

a) केवल 1 और 2
b) केवल 3
c) केवल 2 और 3
d) 1, 2 और 3

Q.103) Solution (c)

युग्म 1	युग्म 2	युग्म 3
सत्य	असत्य	असत्य
इसकी अध्यक्षता सुजीत प्रसाद कर रहे हैं समिति के लिए संदर्भ की शर्तें: a. म्युनिसिपल ऋण प्रतिभूतियों के प्राथमिक और द्वितीयक बाजार के विनियमन और विकास से संबंधित मुद्दों पर सेबी को सलाह देना। b. प्राथमिक और द्वितीयक बाजार में प्रणालियों और प्रक्रियाओं में सरलीकरण और पारदर्शिता लाने के लिए कानूनी ढांचे में बदलाव के	इसका नेतृत्व टी वी मोहनदास पई कर रहे हैं समिति के लिए संदर्भ की शर्तें: 1. भारत में प्राथमिक बाजार के विनियमन और विकास से संबंधित मुद्दों पर सेबी को सलाह देना। 2. प्राथमिक बाजार में प्रणालियों और प्रक्रियाओं में सरलीकरण और पारदर्शिता लाने के लिए कानूनी ढांचे में बदलाव के लिए जरूरी मामलों पर सेबी को सलाह देना। 3. प्राथमिक बाजार में निवेशक	इसकी अध्यक्षता जयंत आर वर्मा कर रहे हैं समिति के लिए संदर्भ की शर्तें: 1. माध्यमिक बाजार में विकास की समीक्षा करना; 2. आसन्न परिवर्तनों को देखते हुए बाजार संरचना में परिवर्तन और सुधार के उपायों की सिफारिश करना; 3. बाजार की सुरक्षा, दक्षता, पारदर्शिता और अखंडता में सुधार के उपायों की सिफारिश

लिए जरूरी मामलों पर सेबी को सलाह देना। c. प्राथमिक और द्वितीयक बाजार में निवेशक सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए बिचौलियों के विनियमन से संबंधित मामलों पर सेबी को सलाह देना। d. म्युनिसिपल ऋण प्रतिभूतियों को जारी करने के लिए जारीकर्ताओं (यानी नगर पालिकाओं) को सुविधाजनक बनाने के उपायों पर सेबी की सिफारिश करना।	सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए बिचौलियों के विनियमन से संबंधित मामलों पर सेबी को सलाह देना।	करना; 4. लेनदेन लागत को कम करने के उपाय सुझाना; 5. यदि जोखिम प्रबंधन / मार्जिन प्रणाली में आवश्यक हो तो परिवर्तन की सिफारिश करना; 6. द्वितीयक बाजार में नियामक ढांचे में आवश्यकता होने पर परिवर्तन की सिफारिश करना;

Q.104) वरिष्ठ पेंशन बीमा योजना के बारे में, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें

1. योजना का कार्यान्वयन निकाय भारतीय जीवन बीमा निगम (LIC) होगा
2. इसका उद्देश्य 60 वर्ष से अधिक आयु के बुजुर्गों को उनके बुढ़ापे के दौरान सामाजिक सुरक्षा प्रदान करना है
3. इस योजना के तहत, प्रति वर्ष 8% के लाभ की गारंटी दर के साथ एक सुनिश्चित पेंशन दस वर्ष की अवधि के लिए प्रदान की जाएगी

उपरोक्त कथन में से कौन सा सही है / हैं?

a) केवल 1 और 2
b) केवल 2 और 3
c) केवल 3
d) उपरोक्त सभी

Q.104) Solution (d)

वित्तीय समावेशन और सामाजिक सुरक्षा के लिए सरकार की प्रतिबद्धता के एक भाग के रूप में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने वरिष्ठ पेंशन बीमा योजना को आरंभ करने के लिए अपनी वास्तविक स्वीकृति दी है।

कथन 1	**कथन 2**	**कथन 3**
सत्य	**सत्य**	**सत्य**
भारतीय जीवन बीमा निगम (LIC) चालू वित्त वर्ष के दौरान योजना का कार्यान्वयन निकाय होगा।	इस योजना का उद्देश्य 60 वर्ष से अधिक आयु के बुजुर्गों को उनके बुढ़ापे के दौरान सामाजिक सुरक्षा प्रदान करना है।	इस योजना के तहत, प्रति वर्ष 8% के लाभ की गारंटी दर के साथ एक सुनिश्चित पेंशन दस वर्ष की अवधि के लिए प्रदान की जाएगी। इसके अलावा, नॉमिनी के पास मासिक / त्रैमासिक / अर्धवार्षिक और वार्षिक आधार पर पेंशन का विकल्प होगा।

Q.105) 2018-19 में भारत को अपने एफडीआई इक्विटी अंतर्वाह के बढ़ते क्रम में निम्नलिखित देशों को व्यवस्थित करें

1. अमेरीका
2. मॉरीशस
3. सिंगापुर
4. नीदरलैंड

सही कूट चुनें

a) 1-4-2-3
b) 4-1-3-2
c) 3-2-4-1
d) 4-1-2-3

Q.`105) Solution (a)

भारत का विदेशी प्रत्यक्ष निवेश (एफडीआई) इक्विटी अन्तर्वाह 2018-19 में छह वर्ष में पहली बार टेलीकॉम, फार्मास्युटिकल और पावर में विदेशी फंडों की अधिक गिरावट के साथ नीचे गया है।

मंगलवार को उद्योग और आंतरिक व्यापार को बढ़ावा देने के लिए विभाग द्वारा जारी किए गए आंकड़ों से पता चलता है कि भारत में एफडीआई इक्विटी प्रवाह 1% घटकर 44.4 बिलियन डॉलर 2018-19 हो गया, जो पिछले वित्त वर्ष में 44.8 बिलियन डॉलर था।

एफडीआई प्रवाह दूरसंचार में 56% गिरकर $ 2.7 बिलियन तथा 74% फार्मास्यूटिकल्स में गिरकर 266 मिलियन डॉलर हो गया है।

इसके अलावा, सिंगापुर ने मॉरीशस को एफडीआई के साथ विदेशी निवेश के शीर्ष स्रोत के रूप में प्रतिस्थापित किया, जो मॉरीशस से $ 8.1 बिलियन की तुलना में $ 16.2 बिलियन के साथ वर्ष के दौरान मॉरिशस से दोगुना है।

नीदरलैंड (3,870 मिलियन डॉलर), इसके बाद यूएसए (3,139 मिलियन डॉलर) और जापान पांचवें (2,965 मिलियन डॉलर) स्थान पर रहा

Q.106) निम्नलिखित में से किसने विश्व निवेश रिपोर्ट 2019 प्रकाशित की है?

a) अंकटाड (UNCTAD)
b) विश्व आर्थिक मंच
c) विश्व बैंक
d) UNDESA

Q.106) Solution (a)

विश्व निवेश रिपोर्ट वैश्विक और क्षेत्रीय प्रत्यक्ष विदेशी निवेश के रुझानों की निगरानी तथा राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय निवेश नीति के विकास का दस्तावेजीकरण करके नीति निर्माताओं का समर्थन करती है।

इस वर्ष की रिपोर्ट का नीति अध्याय अंतरराष्ट्रीय निवेश समझौतों के सुधार और नए उपायों का सर्वेक्षण करने के लिए किए जा रहे प्रयासों का निरिक्षण करता है।

समावेशी सतत विकास एक वैश्विक नीति वातावरण पर निर्भर करता है, जो सीमा पार निवेश के लिए अनुकूल होता है।

विश्व निवेश रिपोर्ट 2019 वैश्विक एसईजेड परिदृश्य का अवलोकन प्रदान करता है तथा सतत विकास अनिवार्यता, नई औद्योगिक क्रांति और अंतर्राष्ट्रीय उत्पादन के बदलते पैटर्न द्वारा उत्पन्न क्षेत्रों के लिए मूलभूत चुनौतियों का प्रतिउत्तर देने के बारे में सलाह देता है।

Q.107) भारतीय संदर्भ में, छाया बैंकिंग (Shadow Banking) के घटकों में शामिल हैं

1. मुद्रा बाजार फंड (Money Market Funds)
2. क्रेडिट निवेश कोष (Credit investment Fund)
3. हेज फंड (Hedge Funds)
4. एनबीएफसी

सही कूट चुनें

a) केवल 1, 2 और 3
b) केवल 2, 3 और 4
c) केवल 1, 3, और 4
d) उपरोक्त सभी

Q.107) Solution (d)
भारतीय संदर्भ में छाया बैंकिंग

'छाया बैंकिंग प्रणाली' शब्द का पहली बार उपयोग 2007 में किया गया था तथा यह नियमित बैंकिंग प्रणाली के बाहर संस्थाओं द्वारा किए गए बैंक जैसे कार्यों को संदर्भित करता है।

वित्तीय स्थिरता बोर्ड (FSB), यानी, 'क्रेडिट मध्यस्थता जिसमें संस्थाओं और गतिविधियों (पूरी तरह या आंशिक रूप से नियमित बैंकिंग प्रणाली से बाहर)' शामिल हैं, द्वारा अपनाया गया है और अधिक व्यापक परिभाषा, विश्व स्तर पर स्वीकार की गई है। इस परिभाषा के दो महत्वपूर्ण घटक हैं:

बैंकिंग प्रणाली के बाहर गैर-बैंक वित्तीय संस्थाएँ या संस्थान जो परिपक्वता परिवर्तन की गतिविधियों जैसे 'बैंक' में संलग्न हैं, क्रेडिट जोखिम हस्तांतरण तथा प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष वित्तीय उत्तोलन (financial leverage) का उपयोग करती हैं।

गैर-बैंक संस्थाओं के लिए धन के महत्वपूर्ण स्रोतों के रूप में कार्य करने वाले प्रतिभूतिकरण, प्रतिभूतियों को उधार देने और रेपो लेनदेन जैसी गतिविधियाँ होती हैं। इस प्रकार, छाया बैंकों में ऐसी संस्थाएं शामिल होती हैं जो सीधे वित्तीय मध्यस्थता का संचालन करती हैं, जैसे कि वित्त कंपनियां या एनबीएफसी, तथा ऐसी संस्थाएं जो ऐसी संस्थाओं को म्युचुअल फंड जैसे वित्त प्रदान करती हैं। वैश्विक स्तर पर, छाया बैंकिंग संस्थाओं को व्यापक प्रमुखों के अंतर्गत शामिल किया जा सकता है

- मुद्रा बाजार फंड (Money Market Funds) ,
- क्रेडिट निवेश कोष
- हेज फंड
- वित्त कंपनियों का फंडिंग की तरह जमा स्वीकार करना
- क्रेडिट बीमाकर्ता, वित्तीय गारंटी प्रदाता
- प्रतिभूतिकरण वाहन (Securitisation vehicles)

छाया बैंकिंग संस्थान निवेशकों और उधारकर्ताओं के बीच मध्यस्थ के रूप में कार्य करते हैं, ऋण प्रदान करते हैं और प्रणाली में तरलता उत्पन्न करते हैं। हालांकि ये संस्थाएं बैंकों द्वारा दी जाने वाली पारंपरिक मांग जमा को स्वीकार नहीं करती हैं, लेकिन वे व्यावसायिक बैंकों के समान सेवाएं प्रदान करती हैं। तथा यह एक कारण था कि वे विदेश में विनियमन से बच गए हैं। छाया बैंकिंग प्रणाली 2008 में वित्तीय संकट से पहले अमेरिका में ऋण की पेशकश में नियमित बैंकिंग प्रणाली से आगे निकल गई थी।

Q.108) 'क्षेत्रक कोष' (Sector Funds) के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें।

1. क्षेत्रक कोष, ओपन एंडेड म्यूचुअल फंड होते हैं
2. क्षेत्रक कोष, इक्विटी म्यूचुअल फंड की तुलना में अधिक जोखिम रखते हैं

उपरोक्त कथनों में से कौन सा सही है / हैं?

a) केवल 1
b) केवल 2
c) 1 और 2 दोनों
d) इनमें से कोई भी नहीं

Q.108) Solution (b)

कथन 1	कथन 2
असत्य	सत्य
क्षेत्रक कोष (Sector funds) वे म्यूचुअल फंड होते हैं जो पूरी तरह से उन व्यवसायों में निवेश करते हैं जो किसी विशेष उद्योग या अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में काम करते हैं। पहला कथन गलत है क्योंकि सेक्टर फंड्स क्लोज-एंड फंड होते हैं	चूंकि वे क्लोज-एंड फंड (closed ended funds) होते हैं, इसलिए उनके पास विविधीकरण का अभाव होता है, तथा वे विविध इक्विटी म्यूचुअल फंडों की तुलना में अधिक जोखिम भरे होते है।

Q.109) भारत में पार्टिसीपेटरी नोट्स (Participatory Notes) के बारे में, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें

1. भारतीय शेयर बाजार में निवेश करने के लिए विदेशी निवेशकों को RBI द्वारा पार्टिसीपेटरी नोट्स जारी किए जाते हैं।
2. पार्टिसीपेटरी नोट्स में निवेश करने वाली किसी भी इकाई को सेबी के साथ पंजीकरण करने की आवश्यकता नहीं होती है।

उपरोक्त कथनों में से कौन सा सही है / हैं?

a) केवल 1
b) केवल 2
c) 1 और 2 दोनों
d) इनमें से कोई भी नहीं

Q.109) Solution (b)

कथन 1	कथन 2
असत्य	सत्य

विदेशी निवेशकों को भारतीय शेयर बाजार में निवेश करने के लिए पंजीकृत विदेशी संस्थागत निवेशकों (एफआईआई) द्वारा पार्टिसिपेटरी नोट जारी किए जाते हैं। पार्टिसिपेटरी नोट्स बड़े हेज फंड को उनकी पहचान बताए बिना उनके संचालन को पूरा करने में सक्षम बनाता है।	पी-नोट्स ने हाल ही में इस मार्ग के माध्यम से भारतीय शेयर बाजारों में विदेशी निधियों के विशाल प्रवाह के कारण महत्वपूर्ण बाजार का ध्यान आकर्षित किया है। पार्टिसिपेटरी नोट्स में निवेश करने वाली किसी भी इकाई को सेबी के साथ पंजीकरण करने की आवश्यकता नहीं होती है क्योंकि यह पंजीकृत एफआईआई से खरीदी गई होती है

Q.110) भारत में प्रतिभूति बाजार को नियंत्रित करने वाले मुख्य विधान निम्नलिखित में से कौन से हैं?

1. सेबी अधिनियम, 1992
2. कंपनी अधिनियम, 1956
3. प्रतिभूति संविदा (विनियमन) अधिनियम, 1956
4. निक्षेपागार अधिनियम, 1996 (Depositories Act)

सही कूट चुनें

a) केवल 1, 2 और 3
b) केवल 2, 3 और 4
c) केवल 1, 3 और 4
d) उपरोक्त सभी

Q.110) Solution (d)

प्रतिभूति बाज़ार को नियंत्रित करने वाले चार मुख्य विधान हैं:

- सेबी अधिनियम, 1992 जो निवेशकों की सुरक्षा और प्रतिभूति बाजार को विकसित और विनियमित करने के लिए सेबी की स्थापना करता है;
- कंपनी अधिनियम, 1956, जो प्रतिभूतियों के निर्गमन, आवंटन और हस्तांतरण, तथा सार्वजनिक प्रस्तावों (public issues) में किए जाने वाले निर्गमन के संबंध में कॉर्पोरेट क्षेत्र के लिए आचार संहिता निर्धारित करता है;
- प्रतिभूति संविदा (विनियमन) अधिनियम, 1956, जो स्टॉक एक्सचेंजों पर नियंत्रण के माध्यम से प्रतिभूतियों में लेनदेन के नियमन का प्रावधान करता है; तथा
- डिपॉजिटरी एक्ट, 1996 जो इलेक्ट्रॉनिक रखरखाव और डीमैट सिक्योरिटीज के स्वामित्व के हस्तांतरण का प्रावधान करता है।

Q.111) मुद्रा, सरकारी-प्रतिभूति, विदेशी मुद्रा विनिमय और डेरिवेटिव्स बाजारों में लेनदेन के लिए गारंटीकृत समाशोधन और निपटान कार्य प्रदान करने में निम्नलिखित में से कौन सी संस्था शामिल है?

a) भारतीय समाशोधन निगम लिमिटेड (CCIL)
b) सेबी
c) नेशनल स्टॉक एक्सचेंज
d) भारतीय रिजर्व बैंक

Q.111) Solution (a)

भारतीय समाशोधन निगम लिमिटेड (Clearing Corporation of India Ltd- CCIL) की स्थापना अप्रैल, 2001 में मुद्रा, सरकारी-प्रतिभूति, विदेशी मुद्रा विनिमय और डेरिवेटिव्स बाजारों में लेनदेन के लिए

गारंटीकृत समाशोधन और निपटान कार्य को प्रदान करने के लिए की गई थी। गारंटीकृत समाशोधन और निपटान की शुरूआत से बाजार में दक्षता, पारदर्शिता, तरलता और जोखिम प्रबंधन / माप पद्धतियों में महत्वपूर्ण सुधार हुआ तथा साथ ही साथ, कम निपटान और परिचालन जोखिम, निपटान लागत पर बचत, आदि जैसे अतिरिक्त लाभ हुए हैं।

CCIL रूपए लाभ दर डेरिवेटिव के लिए गैर-गारंटीकृत निपटान भी प्रदान करता है तथा CLS बैंक के माध्यम से क्रास-मुद्रा लेनदेन को संभव करता है। CCIL के वित्तीय बाजार अवसंरचना के रूप में अपने कार्यों को संचालित करने वाले कड़े सिद्धांतों का पालन भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा 2014 में एक योग्य केंद्रीय प्रतिपक्ष (QCCP) के रूप में अपनी मान्यता के परिणामस्वरूप किया गया है। इसने वित्तीय संस्थानों को OTC डेरिवेटिव में उनके लेनदेन रिपोर्ट करने में सक्षम बनाने के लिए एक ट्रेड रिपोजिटरी भी स्थापित की है।

CCIL वित्तीय बाजार में विभिन्न भूमिकाओं को लेने के लिए वित्तीय क्षेत्र के स्थानांतरण प्रतिमानों के साथ वर्ष दर वर्ष विकसित हुआ है। अपनी पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी क्लीयरकॉर्प डीलिंग सिस्टम्स लिमिटेड (सीडीएसएल) के माध्यम से, सीसीआईएल ने विभिन्न बाजार खंडों में समझौतों के इलेक्ट्रॉनिक निष्पादन के लिए विभिन्न प्लेटफॉर्म पेश किए हैं। इसके अलावा, सीडीएसएल ने एनडीएस-ओएम को विकसित, कार्यान्वित और प्रबंधित किया है - आरबीआई के पास सरकारी-प्रतिभूतियों में निपटने के लिए बेनामी इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग सिस्टम है और ओटीसी समझौतों की रिपोर्टिंग के साथ-साथ एनडीएस-कॉल मंच भी है जो कॉल में इलेक्ट्रॉनिक व्यवहार की सुविधा देता है।

Q.112) विदेशी निवेश सुविधा पोर्टल (Foreign Investment Facilitation Portal) निम्नलिखित में से किस मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण में आता है?

a) वित्त मत्रांलय
b) वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय
c) विदेश मंत्रालय
d) कारपोरेट कार्य मंत्रालय

Q.112) Solution (b)
भारत में कोई भी निवेश - या तो स्वचालित रूट के तहत जिसे आरबीआई से अनुमोदन की आवश्यकता नहीं है या सरकारी रूट के तहत, जिसे संबंधित मंत्रालयों / विभागों से एक खिड़की के माध्यम से पूर्व अनुमोदन की आवश्यकता है - उद्योग और आंतरिक व्यापार प्रोत्साहन के लिए विभाग (DPIIT) द्वारा प्रशासित विदेशी निवेश सुविधा पोर्टल (एफआईएफबी) से कर सकता है।

विदेशी निवेश सुविधा पोर्टल (Foreign Investment Facilitation Portal)

- विदेशी निवेश संवर्धन बोर्ड (FIPB) को विदेशी निवेश सुविधा पोर्टल (FIFP) द्वारा प्रतिस्थापित किया गया ताकि FDI अंतर्वाह को गति दी जा सके तथा देश में FDI अनुमोदन में पारदर्शिता बढ़ाई जा सके। FIFP ने मई, 2017 में FIPB का स्थान लिया।
- विदेशी निवेश सुविधा पोर्टल (FIFP) निवेशकों के लिए भारत सरकार का नया ऑनलाइन एकल बिंदु इंटरफेस है, जो प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की सुविधा देता है। यह पोर्टल उद्योग और आंतरिक व्यापार के संवर्धन विभाग (DPIIT), वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय द्वारा प्रशासित किया जा रहा है।

- यह पोर्टल उन अनुप्रयोगों की एकल खिड़की निकासी की सुविधा जारी रखेगा जो अनुमोदन मार्ग से होते हैं। एफडीआई आवेदन प्राप्त होने पर, संबंधित प्रशासनिक मंत्रालय / विभाग मानक संचालन प्रक्रिया (एसओपी) के अनुसार आवेदन की प्रक्रिया करेगा।

Q.113) अवसंरचनात्मक निवेश ट्रस्ट्स (InvITs) के बारे में, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें।

1. वे संस्थानों की तरह म्यूचुअल फंड हैं जो व्यक्तिगत निवेशकों की भीड़ से पैसे की छोटी रकम जमा करके बुनियादी ढांचा क्षेत्र में निवेश को सक्षम बनाते हैं
2. वे रियल एस्टेट विनियामक प्राधिकरण (RERA)) द्वारा विनियमित होते हैं
3. InvITs केवल विशेष प्रयोजन वाहन (SPV) के माध्यम से बुनियादी ढांचा परियोजनाओं में निवेश कर सकते हैं

उपरोक्त कथनों में से कौन सा सही है / हैं?

a) केवल 1
b) केवल 2 और 3
c) केवल 1 और 3
d) केवल 1 और 2

Q.113) Solution (a)

कथन 1	कथन 2	कथन 3
सत्य	असत्य	असत्य
अवसंरचनात्मक निवेश ट्रस्ट्स (InvITs) म्यूचुअल फंड जैसी संस्थाएं हैं, जो अवसंरचनात्मक क्षेत्र में निवेश करने में सक्षम बनाती हैं, ताकि बुनियादी ढांचा में सीधे निवेश के लिए व्यक्तिगत निवेशकों की भीड़ से छोटी रकम जुटाई जा सके, ताकि यूनिट के आय का एक हिस्सा (व्यय में कटौती के बाद), InvITs के धारक, जो पैसे में जमा हुए हैं, उन्हें लाभ का अंश वापस किया जा सके। InviTs के प्रकार दो प्रकार के InviTs को अनुमति दी गई है, एक जो मुख्य रूप से पूर्ण और राजस्व सृजन करने वाली बुनियादी ढांचा परियोजनाओं में निवेश करने की अनुमति है तथा दूसरी जिसमें पूर्ण / निर्माणाधीन परियोजनाओं में निवेश करने की	भारत में प्रतिभूतियों के बाजार नियामक- भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (SEBI) द्वारा InviTs का विनियमन किया जाता है। SEBI ने SEBI (Infrastructure Investment Trusts) विनियम, 2014 को 26 सितंबर 2014 को अधिसूचित किया, जो भारत में InvITs के पंजीकरण और विनियमन के लिए प्रावधान प्रदान करता है। InvIT का उद्देश्य भारत में बुनियादी ढांचा क्षेत्र में निवेश की सुविधा प्रदान करना है। संरचना और परिचालनों में InvITs रियल एस्टेट इनवेस्टमेंट ट्रस्ट्स (REITs) से बहुत मिलते-जुलते हैं। InvITs संशोधित REITs हैं जिन्हें भारत में विशिष्ट परिस्थितियों के अनुरूप बनाया गया है।	InvITs बुनियादी ढांचे की परियोजनाओं में निवेश कर सकते हैं, या तो सीधे या एक विशेष उद्देश्य वाहन (एसपीवी) के माध्यम से। पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप (पीपीपी) परियोजनाओं के मामले में, ऐसे निवेश केवल एसपीवी के माध्यम से हो सकते हैं।

सुविधा है। जबकि पूर्व को अपनी इकाइयों की सार्वजनिक पेशकश करनी होती है, बाद वाले को अपनी इकाइयों के निजी प्लेसमेंट का विकल्प चुनना होता है। दोनों संरचनाओं को सूचीबद्ध करने की आवश्यकता होती है। चुनिंदा राज्य संचालित कंपनियों के विमुद्रीकरण के लिए अवसंरचनात्मक निवेश ट्रस्ट्स (InvITs) की घोषणा बजट 2018-19 में की गई थी।		

Q.114) निम्नलिखित कथनों पर विचार करें

1. भुगतान संतुलन देश के नागरिकों और संसार के बाकी हिस्सों के बीच लेनदेन की गणना करता है।
2. पूंजीगत खाते में बड़े बदलाव यह संकेत दे सकते हैं कि विदेशी निवेशकों के लिए एक देश कितना आकर्षक है और विनिमय दरों पर बड़ा प्रभाव डाल सकते हैं।
3. किसी देश के अधिशेष पूंजीगत खाते के ज़रिए उसकी परिसंपत्तियों के बढ़ते विदेशी स्वामित्व का संकेत मिलता है।

उपरोक्त कथन में से कौन सा सही है / हैं?

a) केवल 1 और 2
b) केवल 2 और 3
c) केवल 1 और 3
d) केवल 2

Q.114) Solution (b)

कथन 1	कथन 2	कथन 3
असत्य	सत्य	सत्य
भुगतान संतुलन (बीओपी) एक देश के निवासियों के बीच वस्तुओं, सेवाओं और परिसंपत्तियों के लेनदेन को निर्दिष्ट समय अवधि के लिए संसार के बाकी हिस्सों के साथ होता है, जिसे आम तौर पर एक वर्ष में रिकॉर्ड किया जाता है। भुगतान संतुलन (बीओपी), जिसे अंतर्राष्ट्रीय भुगतान संतुलन के रूप में भी जाना जाता है, सभी लेनदेन को संक्षेप में बताता है कि देश के	भुगतान संतुलन एक पूंजी खाते और एक चालू खाते से बना होता है - हालांकि एक संकीर्ण परिभाषा पूंजी खाते को एक वित्तीय खाते और एक पूंजी खाते में तोड़ देती है। लेखांकन में, पूंजी खाता एक विशिष्ट समय में एक व्यापार के निवल मूल्य को दर्शाता है - और अन्यथा शेयरधारकों की इक्विटी के रूप में जाना जाता है। भुगतान संतुलन में परिवर्तन से देश के आर्थिक स्वास्थ्य	क्योंकि सभी लेन-देन शून्य से भुगतान राशि में दर्ज किए गए हैं, जो देश बड़े व्यापार घाटे (चालू खाता घाटे) में रहते हैं, परिभाषा के अनुसार बड़े पूंजी खाता अधिशेष भी रहने चाहिए - जिसका अर्थ है कि किसी देश के अधिशेष पूंजीगत खाते के ज़रिए उसकी परिसंपत्तियों के बढ़ते विदेशी स्वामित्व का संकेत मिलता है। एक बड़े व्यापार

व्यक्ति, कंपनियां और सरकारी निकाय देश के बाहर व्यक्तियों, कंपनियों और सरकारी निकायों के साथ लेनदेन को सारांशित करते हैं। इन लेनदेन में माल, सेवाओं और पूंजी के आयात और निर्यात के साथ-साथ विदेशी सहायता और प्रेषण जैसे हस्तांतरण भुगतान शामिल होते हैं।	के सापेक्ष स्तर और भविष्य की स्थिरता के बारे में कई साक्ष्य मिल सकते हैं। पूंजी खाता इंगित करता है कि कोई देश पूंजी का आयात या निर्यात कर रहा है या नहीं। पूंजी खाते में बड़े बदलाव यह संकेत दे सकते हैं कि विदेशी निवेशकों के लिए एक देश कितना आकर्षक है और विनिमय दरों पर बड़ा प्रभाव डाल सकता है।	अधिशेष वाला देश पूंजी निर्यात कर रहा है, और पूंजी खाता घाटा हो रहा है - जिसका अर्थ है मुद्रा, देश से बाहर जा रही है।

Q.115) निम्नलिखित कथनों पर विचार करें

1. भारत ने वित्तीय वर्ष 2018-19 में अपना अब तक का सबसे अधिक प्रत्यक्ष विदेशी निवेश प्राप्त किया है
2. भारत में पिछले 5 वर्षों में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश लगातार बढ़ा है

उपरोक्त कथनों में से कौन सा सही है / हैं?

a) केवल 1
b) केवल 2
c) 1 और 2 दोनों
d) इनमें से कोई भी नहीं

Q.115) Solution (a)

कथन 1	**कथन 2**
सत्य	**असत्य**
एफडीआई आर्थिक विकास का एक प्रमुख चालक है तथा देश के आर्थिक विकास के लिए गैर-ऋण वित्त का एक स्रोत है। सरकार ने एफडीआई पर एक निवेशक-अनुकूल नीति रखी है, जिसके तहत अधिकांश क्षेत्रों / गतिविधियों में स्वचालित मार्ग पर 100 प्रतिशत तक निवेश की अनुमति है। उन्होंने कहा कि इन सुधारों के कारण भारत में 2014-15 से 2018-19 तक पाँच वर्षों में कुल एफडीआई बढ़कर 286 बिलियन डॉलर तक पहुंच गया, जबकि पिछले पांच वर्षों में 189 बिलियन अमेरिकी डॉलर था। USD 64.37 बिलियन, 2018-19 में FDI किसी भी वित्तीय वर्ष के लिए प्राप्त किया गया सबसे अधिक निवेश है।	एक स्थिर और अनुमानित विनियामक शासन, एक बढ़ती अर्थव्यवस्था और मजबूत बुनियादी बातों के कारण, भारत पिछले पांच वर्षों के दौरान विदेशी प्रत्यक्ष निवेश की बड़ी मात्रा को आकर्षित कर सका है, जोकि एफडीआई के रूप में प्राप्त 239 बिलियन अमरीकी डालर है। इस अवधि में एफडीआई नीति का तेजी से उदारीकरण भी देखा गया, जिससे अधिकांश एफडीआई स्वत: मार्ग से आने लगे। लेकिन एफडीआई लगातार नहीं बढ़ा है।

Q.116) शुद्ध अदृश्य (Net Invisibles) किसी निश्चित समय में किसी देश के अदृश्य निर्यात और आयात मूल्य के बीच का अंतर है। इस संदर्भ में, गैर-कारक आय का गठन कौन करता है

1. श्रम पर अंतर्राष्ट्रीय आय

2. पूंजी पर अंतर्राष्ट्रीय आय
3. शिपिंग
4. बैंकिंग
5. पर्यटन

सही कूट चुनें

a) केवल 1, 2, 3 और 4
b) केवल 2, 3, 4 और 5
c) केवल 3, 4 और 5
d) उपरोक्त सभी

Q.116) Solution (c)

शुद्ध अदृश्य (Net Invisibles) एक निश्चित समय में किसी देश के निर्यात के मूल्य और आयात के मूल्य के बीच का अंतर है। अदृश्य योग्य में विभिन्न देशों के बीच होने वाली सेवाओं, स्थानांतरण और प्रवाह की आय शामिल होती हैं। सेवा व्यापार में कारक और गैर-कारक आय दोनों शामिल हैं। कारक आय में उत्पादन के कारकों (जैसे श्रम, भूमि और पूंजी) पर शुद्ध अंतर्राष्ट्रीय आय शामिल है। गैर-कारक आय शिपिंग, बैंकिंग, पर्यटन, सॉफ्टवेयर सेवाओं आदि जैसे सेवा उत्पादों की शुद्ध बिक्री है।

Q.117) 'अर्थव्यवस्था के खुलेपन' (openness of an economy) के स्तर को, निम्न में से किस कारक द्वारा मापा जाता है?

a) विश्व जीडीपी में निर्यात और आयात का हिस्सा
b) जीडीपी के प्रतिशत के रूप में वस्तुओं और सेवाओं का निर्यात और आयात
c) जीडीपी के प्रतिशत के रूप में भुगतान संतुलन
d) जीडीपी के प्रतिशत के रूप में व्यापार संतुलन

Q.117) Solution (b)

खुलेपन को किसी देश के माल और सेवाओं के निर्यात और आयात के रूप में मापा जाता है, जो उसके सकल घरेलू उत्पाद के प्रतिशत के रूप में होती है। तो, विकल्प b सही है

व्यापार संतुलन का अर्थ है निर्यात - आयात है, इसलिए विवरण d गलत है।

Q.118) क्रय शक्ति समता (PPP) विनिमय दरों के बारे में, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:

1. यदि दो देशों में मुद्रास्फीति की दर शून्य है, तो उनकी पीपीपी विनिमय दरें स्थिर रहेंगी
2. पीपीपी विनिमय दर पर परिवर्तित होने पर दोनों देशों में सामान की कीमतें समान होंगी

उपरोक्त कथनों में से कौन सा गलत है / हैं?

a) केवल 1
b) केवल 2
c) 1 और 2 दोनों
d) इनमें से कोई भी नहीं

Q.118) Solution (d)

मान लीजिए नॉमिनल विनिमय दर $ 1 = 70 है तथा भारत और अमेरिका सिर्फ पिज्जा का उत्पादन करते हैं

	भारत	यू.एस.
पिज्जा की कीमत	35	$ 1

पीपीपी विनिमय दर की गणना करने के लिए, हमें अमेरिका के साथ भारत में सामान की एक टोकरी की कीमतों की तुलना करने की आवश्यकता है।

भारत और अमेरिका में पिज्जा की कीमतों की तुलना करके उपरोक्त मामले में, हमें $ 1 = 35 रु मिलता है तो, $ 1 = 35 पीपीपी विनिमय दर है। इसका तात्पर्य है कि भारत में जो भी 35 रुपये खरीद सकता है, यूएस में $ 1 खरीद सकता है यानी भारत में 35 रुपये की क्रय शक्ति यूएस में $ 1 की क्रय शक्ति के बराबर है।

इसलिए, अगर देशों में मुद्रास्फीति की दर अलग है, तो पीपीपी विनिमय दर बदल जाएगी। लेकिन अगर कोई मुद्रास्फीति नहीं है (कीमतें समान हैं) तो पीपीपी विनिमय दरें स्थिर रहेंगी।

तो, कथन 1 सही है।

जब हम US में पिज़्ज़ा की कीमत को भारतीय मुद्रा में बदलने के लिए PPP एक्सचेंज ($ 1 = 35 रु।) की दर का उपयोग करते हैं तो यह 1 US में 35 रु. होता है जो भारत में भी वैसा ही है।

तो, कथन 2 भी सही है।

Q.119) भारतीय संदर्भ में, रुपये के मूल्यह्रास (depreciation) का क्या अर्थ है?

a) विनिमय दर में वृद्धि जहां घरेलू मुद्रा (रुपये) के संदर्भ में विदेशी मुद्रा (डॉलर) की कीमत में वृद्धि हुई है
b) विनिमय दर में वृद्धि जहां विदेशी मुद्रा (रुपये) के संदर्भ में भारतीय मुद्रा (डॉलर) की कीमत में वृद्धि हुई है
c) विनिमय दर में कमी जहां विदेशी मुद्रा (रुपये) के संदर्भ में भारतीय मुद्रा (डॉलर) की कीमत में वृद्धि हुई है
d) विनिमय दर में कमी जहां घरेलू मुद्रा (रुपये) के संदर्भ में विदेशी मुद्रा (डॉलर) की कीमत में कमी आई है

Q.119) Solution (a)

विनिमय दर में वृद्धि का अर्थ है कि घरेलू मुद्रा (रुपये) के संदर्भ में विदेशी मुद्रा (डॉलर) की कीमत में वृद्धि हुई है। इसे विदेशी मुद्रा (डॉलर) के संदर्भ में घरेलू मुद्रा (रुपये) का मूल्यह्रास (Depreciation) कहा जाता है।

इसी तरह, एक लचीली विनिमय दर शासन में, जब विदेशी मुद्रा (डॉलर) के संदर्भ में घरेलू मुद्रा (रुपये) की कीमत बढ़ती है, तो इसे विदेशी मुद्रा (डॉलर) के संदर्भ में घरेलू मुद्रा (रुपये) का अभिमूल्यन (Appreciation) कहा जाता है।

Q.120) एक्सचेंज ट्रेडेड फंड (ETF) के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें।

1. भरत 22 (Bharat 22), एक प्रकार का म्यूचुअल फंड है जिसमें केवल 22 सार्वजनिक क्षेत्र की इकाइयाँ (PSU) स्टॉक शामिल हैं

2. ईटीएफ में निवेश कम तरल होते है क्योंकि उन्हें प्रत्यक्ष इक्विटी शेयरों की तरह स्टॉक एक्सचेंज में कारोबार नहीं किया जा सकता है
3. भारत सरकार ने भारत 22 ईटीएफ के प्रबंधन के लिए आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल एएमसी को नियुक्त किया है

उपरोक्त कथनों में से कौन सा सही है / हैं?

a) केवल 1 और 2
b) केवल 2 और 3
c) केवल 1 और 3
d) केवल 3

Q.120) Solution (d)

कथन 1	कथन 2	कथन 3
असत्य	**असत्य**	**सत्य**
ETF एक ओपन-एंडेड म्यूचुअल फंड स्कीम है जिसका उद्देश्य अपने अंतर्निहित सूचकांक के प्रदर्शन को ट्रैक और प्रतिबिंबित करना है। यह उसी स्टॉक में निवेश करने की निष्क्रिय निवेश रणनीति के माध्यम से प्राप्त करता है और उसी अनुपात में जैसा कि वे अंतर्निहित सूचकांक का गठन करते हैं। सूचकांक में केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यम (CPSE), सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों और निजी कंपनियों के 22 स्टॉक शामिल हैं, जो यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया के रणनीतिक होल्डिंग (SUUTI) हैं। उक्त 22 स्टॉक छह क्षेत्रों (मूल सामग्री, ऊर्जा, वित्त, एफएमसीजी, उद्योग और Utilities) में फैले हैं। सूचकांक एकल स्टॉक में अधिकतम 15 प्रतिशत और किसी विशेष क्षेत्र में 20 प्रतिशत निवेश करता है। भारांश प्रतिवर्ष पुनर्संरचित किया जाता है।	ईटीएफ में निवेश अत्यधिक तरल है क्योंकि वे डीमैट खाते के माध्यम से आयोजित किए जाते हैं तथा प्रत्यक्ष इक्विटी शेयरों जैसे स्टॉक एक्सचेंज में कारोबार किया जा सकता है। साथ ही, निष्क्रिय रूप से प्रबंधित होने के कारण, उनके पास सक्रिय रूप से प्रबंधित म्यूचुअल फंडों की तुलना में कम व्यय वाले अनुपात होते हैं। भारत 22 ईटीएफ सरकार को एक ईटीएफ में चयनित सार्वजनिक उपक्रमों में अपनी होल्डिंग संग्रहित करने और एक बार में निवेशकों से विनिवेशित धन जुटाने की अनुमति देता है। यह विशेष रूप से निर्मित S & P BSE Bharat 22 सूचकांक, एशिया इंडेक्स प्राइवेट लिमिटेड द्वारा प्रबंधित करता है। यह सूचकांक 22 पीएसयू शेयरों और कुछ निजी क्षेत्र की कंपनियों से बना है।	भारत सरकार ने भारत 22 ईटीएफ को बनाने, लॉन्च करने और प्रबंधित करने के लिए आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल एएमसी को नियुक्त किया है।

Q.121) राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम (NCDC) के बारे में, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें।

1. एनसीडीसी कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय के तहत एक वैधानिक निगम है।

2. युवाओं को सहकारी व्यवसाय उपक्रमों के प्रति आकर्षित करने के लिए एनसीडीसी द्वारा युवा सहकार योजना (Yuva Sahakar scheme) तैयार की गई।

नीचे दिए गए कूट का उपयोग करके सही उत्तर चुनें

a) केवल 1
b) केवल 2
c) 1 और 2 दोनों
d) न तो 1 और न ही 2

Q.121) Solution (c)

कथन 1	कथन 2
सत्य	सत्य
राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम (NCDC) की स्थापना 1963 में संसद के एक अधिनियम द्वारा कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय के तहत एक सांविधिक निगम के रूप में की गई थी।	युवा सहकार- सहकारी उद्यम सहायता और नवाचार योजना 2019 को एनसीडीसी द्वारा तैयार किया गया है, जो स्टार्ट-अप इंडिया जैसे कार्यक्रमों पर सरकार के फोकस के अनुरूप है। इसका उद्देश्य युवाओं को सहकारी व्यवसाय उपक्रमों की ओर आकर्षित करना है।

Q.122) सार्वजनिक उद्यम सर्वेक्षण 2018-19 के बारे में, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें

1. यह केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यम (CPSEs) के प्रदर्शन पर एक सर्वेक्षण है।
2. यह भारी उद्योग और सार्वजनिक उद्यम मंत्रालय द्वारा संचालित किया जाता है।
3. सर्वेक्षण के अनुसार, बीएसएनएल, एयर इंडिया और एमटीएनएल पीएसयू की शीर्ष 3 घाटे वाली इकाइयाँ हैं।

ऊपर दिए गए कथनों में से कौन सा सही है / हैं?

a) केवल 1 और 2
b) केवल 1 और 3
c) केवल 2 और 3
d) उपरोक्त सभी

Q.122) Solution (d)

विकल्प 1	विकल्प 2	विकल्प 3
सत्य	सत्य	सत्य
सार्वजनिक उपक्रम विभाग (डीपीई), भारी उद्योग और सार्वजनिक उद्यम मंत्रालय, भारत सरकार प्रत्येक वर्ष केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उद्यमों (CPSEs)	सार्वजनिक उपक्रम विभाग (डीपीई), भारी उद्योग और सार्वजनिक उद्यम मंत्रालय, भारत सरकार प्रत्येक वर्ष केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उद्यमों (CPSEs) के	रिपोर्ट के अनुसार, ओएनजीसी, इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन और एनटीपीसी 2018-19 में शीर्ष तीन लाभदायक सार्वजनिक उपक्रम थे, जबकि बीएसएनएल,

के प्रदर्शन पर सार्वजनिक क्षेत्र उद्यम सर्वेक्षण प्रस्तुत करती है।	प्रदर्शन पर सार्वजनिक क्षेत्र उद्यम सर्वेक्षण प्रस्तुत करती है।	एयर इंडिया और एमटीएनएल ने लगातार तीसरे वर्ष में सबसे अधिक नुकसान उठाया।

Q.123) भारत में सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों में, निम्नलिखित में से कौन सी मुख्य समस्या नहीं है?

a) कर्मचारियों की कमी (understaffing)
b) उत्तरदायित्व की कमी
c) अनुचित मूल्य निर्धारण नीति
d) क्षमता के अल्प-उपयोग

Q.123) Solution (a)

सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों की कुछ प्रमुख समस्याएं हैं

- कर्मचारी आधिक्य (Overstaffing)
- स्वायत्तता और उत्तरदायित्व का अभाव
- अनुचित मूल्य निर्धारण नीति
- क्षमता का अल्प- उपयोग
- अनुचित निवेश निर्णय
- ट्रेड यूनियनवाद

Q.124) रक्षा नवोन्मेष संगठन (Defence Innovation Organization) के बारे में, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें

1. यह कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 8 के तहत 'गैर-लाभकारी' कंपनी है।
2. इसे दो सार्वजनिक क्षेत्र के रक्षा उपक्रम अर्थात हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड (HAL) और भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड (BEL) द्वारा वित्त पोषित किया गया है।

उपरोक्त में से कौन सा कथन गलत है?

a) केवल 1
b) केवल 2
c) 1 और 2 दोनों
d) न तो 1 और न ही 2

Q.124) Solution (d)

कथन 1	**कथन 2**
सत्य	**सत्य**
DIO कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 8 के तहत 'गैर-लाभकारी' कंपनी है। रक्षा नवाचार निधि की योजना DIO के माध्यम से कार्यान्वित की जाती है।	DIO को दो सार्वजनिक क्षेत्र के रक्षा उपक्रम अर्थात हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड (HAL) और भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड (BEL) द्वारा वित्त पोषित किया गया है।

Q.125) कॉरपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व (CSR) पर उच्च-स्तरीय समिति की अध्यक्षता किसने की है

a) उदय कोटक
b) इनजेति श्रीनिवास
c) नचिकेत मोर
d) सुभाष चंद्र गर्ग

Q.125) Solution (b)

सीएसआर पर उच्च-स्तरीय समिति का गठन अक्टूबर 2018 में, इंजेति श्रीनिवास, सचिव (कॉर्पोरेट मामलों) की अध्यक्षता में किया गया था।

अनुशंसाएँ

- सीएसआर व्यय कर-कटौती योग्य बनाना।
- 3 - 5 वर्षों की अवधि के लिए अव्ययित शेष (unspent balance) को आगे बढ़ाने का प्रावधान।
- राष्ट्रीय प्राथमिकताओं के साथ स्थानीय क्षेत्रीय वरीयताओं को संतुलित करना।
- एसडीजी प्लस फ्रेमवर्क को अपनाकर अनुसूची 7 को एसडीजी के साथ संरेखित करना।
- सीएसआर अनुपालन के उल्लंघन को एक नागरिक अपराध बनाया जा सकता है और जुर्माना प्रावधान में स्थानांतरित किया जा सकता है।

Q.126) निम्नलिखित गतिविधियों पर विचार करें

1. शिक्षा का प्रोत्साहन
2. मातृ स्वास्थ्य में सुधार
3. कोविड -19 प्रकोप से निपटने के उपाय

उपरोक्त गतिविधियों में से कौन सी कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व के तहत अनुमत है?

a) केवल 1 और 2
b) केवल 1 और 3
c) केवल 2 और 3
d) उपरोक्त सभी

Q.126) Solution (d)

- कॉरपोरेट मामलों के मंत्रालय (MCA) ने घोषणा की कि कोविड -19 प्रकोप से निपटने के उपायों पर व्यय किए गए धन को कंपनियों की कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व (CSR) गतिविधि के अंतर्गत गिना जाएगा।

कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व (CSR) के तहत अन्य गतिविधियाँ

- अत्यधिक भूख और गरीबी का उन्मूलन।
- शिक्षा का प्रोत्साहन।
- लैंगिक समानता को बढ़ावा देना और महिलाओं को सशक्त बनाना।
- बाल मृत्यु दर को कम करना।
- मातृ स्वास्थ्य में सुधार।

- एचआईवी, एक्वायर्ड इम्यून डेफिसिएंसी सिंड्रोम, मलेरिया और अन्य बीमारियों का मुकाबला करना।
- पर्यावरणीय सततता सुनिश्चित करना।
- रोजगार वर्धक व्यावसायिक कौशल, सामाजिक व्यापार परियोजनाओं को बढ़ाना।
- प्रधान मंत्री राष्ट्रीय राहत कोष में योगदान या सामाजिक-आर्थिक विकास के लिए केंद्र सरकार या राज्य सरकारों द्वारा स्थापित कोई अन्य निधि।
- अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों, अल्पसंख्यकों और महिलाओं तथा ऐसे अन्य मामलों के कल्याण के लिए राहत और धन, जो निर्धारित हो सकते हैं।

Q.127) विनिवेश (Disinvestment) के संबंध में, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें

1. राष्ट्रीय निवेश और अवसंरचना कोष (NIIF) में पृथक रूप से प्राप्त राशि रखी जाती है।
2. निजी क्षेत्र को स्वामित्व और नियंत्रण का हस्तांतरण, रणनीतिक विनिवेश के रूप में जाना जाता है।

नीचे दिए गए कूट का उपयोग करके सही उत्तर चुनें

a) केवल 1
b) केवल 2
c) 1 और 2 दोनों
d) न तो 1 और न ही 2

Q.127) Solution (b)

कथन 1	कथन 2
असत्य	सत्य
राष्ट्रीय निवेश कोष (Not NIIF) में पृथक रूप से प्राप्त राशि रखी जाती है। निधि के लाभ का उपयोग चयनित केंद्रीय सामाजिक कल्याण योजनाओं के लिए किया जाता है। यह कोष भारत के समेकित कोष के बाहर रखा गया है।	रणनीतिक विनिवेश किसी अन्य इकाई (ज्यादातर निजी क्षेत्र की इकाई) के लिए सार्वजनिक क्षेत्र की इकाई के स्वामित्व और नियंत्रण का हस्तांतरण है। साधारण विनिवेश के विपरीत, रणनीतिक बिक्री का अर्थ एक तरह का निजीकरण है।

Q.128) समर्पित फ्रेट कॉरिडोर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया (DFCCIL) के बारे में, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें।

1. इसे भारत सरकार द्वारा 'विशेष प्रयोजन वाहन' का दर्जा दिया गया है।
2. यह योजना और विकास, निर्माण, रखरखाव तथा समर्पित फ्रेट कॉरिडोर (DFC) के संचालन में संलग्न है।
3. इसका एक मिशन ग्राहकों को संपूर्ण परिवहन समाधान प्रदान करने के लिए DFC के साथ मल्टीमॉडल लॉजिस्टिक पार्क स्थापित करना है।

ऊपर दिए गए कथनों में से कौन सा गलत है / हैं?

a) केवल 1 और 2
b) केवल 1 और 3
c) इनमे से कोई भी नहीं
d) उपरोक्त सभी

Q.128) Solution (c)

विकल्प 1	विकल्प 2	विकल्प 3
सत्य	सत्य	सत्य
DFCCIL को भारत सरकार द्वारा 'विशेष प्रयोजन वाहन' का दर्जा दिया गया है।	यह योजना और विकास, मौद्रिक संसाधनों की तैनाती, निर्माण, रखरखाव और डीएफसी के संचालन में संलग्न है।	इसका एक मिशन ग्राहकों को संपूर्ण परिवहन समाधान प्रदान करने के लिए डीएफसी के साथ मल्टीमॉडल लॉजिस्टिक पार्क स्थापित करना है।

Q.129) गंभीर धोखाधड़ी जांच कार्यालय (Serious Fraud Investigation Office- SFIO) के बारे में, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें।

1. कंपनी अधिनियम, 2013, ने एसएफआईओ को वैधानिक दर्जा दिया है।
2. यह वित्त मंत्रालय के तहत एक बहु-अनुशासनात्मक संगठन है।

नीचे दिए गए कूट का उपयोग करके सही उत्तर चुनें

a) केवल 1
b) केवल 2
c) 1 और 2 दोनों
d) न तो 1 और न ही 2

Q.129) Solution (a)

कथन 1	कथन 2
सत्य	असत्य
कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 211, ने गंभीर धोखाधड़ी जांच कार्यालय को वैधानिक दर्जा दिया है।	**SFIO** एक बहु-अनुशासनात्मक संगठन है, जो **कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय** के अंतर्गत आता है, जिसमें एकाउंटेंसी, फोरेंसिक ऑडिटिंग, कानून, सूचना प्रौद्योगिकी, जांच, कंपनी कानून और बहुत कुछ शामिल है।

Q.130) कंपनी को इलेक्ट्रॉनिक रूप से निगमित करने के लिए सरलीकृत प्रोफार्मा (SPICe +) वेब फॉर्म किसके द्वारा लॉन्च किया गया है

a) श्रम मंत्रालय
b) कारपोरेट कार्य मंत्रालय
c) वित्त मत्रांलय
d) वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय

Q.130) Solution (b)

कंपनी को इलेक्ट्रॉनिक रूप से निगमित करने के लिए सरलीकृत प्रोफार्मा (SPICe +)

- **कॉरपोरेट मामलों के मंत्रालय (MCA)** ने कंपनी को इलेक्ट्रॉनिक रूप से निगमित करने के लिए सरलीकृत प्रोफार्मा (SPICe +) वेब फॉर्म को लॉन्च किया है।
- SPICe+, तीन केंद्रीय सरकार के मंत्रालयों और विभागों (कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय, श्रम मंत्रालय और वित्त मंत्रालय) और एक राज्य सरकार (महाराष्ट्र) द्वारा 10 सेवाएं प्रदान करेगा।
- नया वेब फॉर्म भारत में व्यवसाय शुरू करने के लिए कई प्रक्रियाओं, समय और लागत को बचाने में सहायता करेगा।

Q.131) यू.के. सिन्हा समिति को RBI द्वारा किस कार्य हेतु नियुक्त किया गया था

a) देश में डिजिटल भुगतान की रक्षा और सुरक्षा को मजबूत करने के उपाय सुझाना।
b) भारत में सार्वजनिक क्रेडिट रजिस्ट्री स्थापित करने की आवश्यकता और कार्यक्षेत्र का आकलन करना।
c) MSMEs का जीर्णोद्धार (rejuvenate) करने के लिए आवश्यक उपायों पर गौर करना।
d) आरबीआई से सरकार को अधिशेष निधियों के हस्तांतरण पर सिफारिशें करना।

Q.131) Solution (c)

अध्यक्ष	समिति
नंदन नीलकाणी	देश में डिजिटल भुगतान की रक्षा और सुरक्षा को मजबूत करने के उपाय सुझाना।
वाई.एम. देओस्थली	भारत में सार्वजनिक क्रेडिट रजिस्ट्री स्थापित करने की आवश्यकता और कार्यक्षेत्र का आकलन करना।
यू.के.सिन्हा	MSMEs का जीर्णोद्धार (rejuvenate) करने के लिए आवश्यक उपायों पर गौर करना।
बिमल जालान	आरबीआई से सरकार को अधिशेष निधियों के हस्तांतरण पर सिफारिशें करना।

Q.132) सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों (MSMEs) के वर्गीकरण के बारे में, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें।

1. MSMEs को MSME अधिनियम -2016 के अनुसार वर्गीकृत किया गया है।
2. MSMEs को संयंत्र और मशीनरी / उपकरण में निवेश के आधार पर परिभाषित किया गया है।

नीचे दिए गए कूट का उपयोग करके गलत उत्तर चुनें

a) केवल 1
b) केवल 2
c) 1 और 2 दोनों
d) न तो 1 और न ही 2

Q.132) Solution (b)

कथन 1	कथन 2
सत्य	असत्य

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों (MSMEs) को MSME अधिनियम -2016 के अनुसार वर्गीकृत किया गया है। सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम (MSME) को दो श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया है: विनिर्माण उद्यम और सेवा उद्यम।	फरवरी 2018 में, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने MSMEs की परिभाषा में बदलाव को मंजूरी दी। MSMEs को अब संयंत्र और मशीनरी / उपकरण में निवेश के बजाय 'वार्षिक कारोबार' के आधार पर परिभाषित किया जाएगा।

Q.133) निम्नलिखित में से कौन, 1991 के आर्थिक सुधारों का कारण है?

1. राजकोषीय घाटे में वृद्धि
2. प्रतिकूल भुगतान संतुलन में वृद्धि
3. सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों का निराशाजनक प्रदर्शन

नीचे दिए गए कूट का उपयोग करके सही उत्तर चुनें

a) केवल 1 और 2
b) केवल 1 और 3
c) केवल 2 और 3
d) उपरोक्त सभी

Q.133) Solution (d)

भारत में आर्थिक सुधारों के मुख्य कारण

- कीमतों में वृद्धि
- राजकोषीय घाटे में वृद्धि
- प्रतिकूल भुगतान संतुलन में वृद्धि
- सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों का निराशाजनक प्रदर्शन
- विदेशी मुद्रा भंडार में गिरावट

Q.134) व्यापार करने में आसानी (Ease of Doing Business) रैंकिंग के बारे में, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें

1. यह विश्व बैंक द्वारा वार्षिक रूप से जारी किया जाता है।
2. रैंकिंग के सभी दस मापदंडों में भारत का प्रदर्शन बेहतर हुआ है।

नीचे दिए गए कूट का उपयोग करके सही उत्तर चुनें

a) केवल 1
b) केवल 2
c) 1 और 2 दोनों
d) न तो 1 और न ही 2

Q.134) Solution (a)

कथन 1	**कथन 2**
सत्य	**असत्य**
विश्व बैंक की 2019 की रिपोर्ट व्यापार करने में	भारत की रैंकिंग दो मापदंडों पर खराब हुई है -

आसानी (EODB) रैंकिंग के लिए 190 देशों में भारत 14 स्थान आगे बढ़कर 63 वें स्थान पर पहुंच गया है। रिपोर्ट में दिल्ली और मुंबई में व्यापार करने में आसानी (EODB) पर्यावरण बनाने में सुधार का आकलन किया गया है। EODB विश्व बैंक द्वारा प्रतिवर्ष जारी किया जाता है।	"अल्पसंख्यक निवेशकों की सुरक्षा" (7 वें से 13 वें स्थान पर) और "बिजली प्राप्त करने में" (22 वें से 25 वें स्थान पर)।

Q.135) राष्ट्रीय वित्तीय रिपोर्टिंग प्राधिकरण (NFRA) के बारे में, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें।

1. यह केंद्र सरकार को लेखांकन और लेखा परीक्षा नीतियों के निर्माण और लागु करने पर सिफारिशें देगा।
2. इसमें चार्टर्ड अकाउंटेंट एक्ट, 1949 के तहत पंजीकृत ऑडिटर्स की जांच करने की शक्ति होगी।

नीचे दिए गए कूट का उपयोग करके गलत उत्तर चुनें

a) केवल 1
b) केवल 2
c) 1 और 2 दोनों
d) न तो 1 और न ही 2

Q.135) Solution (d)

कथन 1	**कथन 2**
सत्य	**सत्य**
NFRA होगा - • केंद्र सरकार को लेखांकन और लेखा परीक्षा नीतियों के निर्माण और लागु करने की सिफारिशें करना। • लेखांकन मानकों के अनुपालन की निगरानी और उन्हें लागू करना। • पेशेवरों की सेवा की गुणवत्ता की देखरेख करना	इसकी जांच करने की शक्ति होगी, जो या तो स्वतः संज्ञान या केंद्र सरकार द्वारा इसके लिए किए गए संदर्भ पर आधारित होगी, जो चार्टर्ड अकाउंटेंट अधिनियम, 1949 के तहत पंजीकृत हैं।

Q.136) विश्व सीमा शुल्क संगठन (World Customs Organization) के बारे में, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें

1. यह एक स्वतंत्र अंतर सरकारी निकाय है, जिसका मिशन सीमा शुल्क प्रशासन की प्रभावशीलता और दक्षता को बढ़ाना है।
2. यह एकमात्र वैश्विक संगठन है जो सीमा शुल्क मंजूरी के लिए वैश्विक मानकों और प्रक्रियाओं को परिभाषित करता है।
3. भारत WCO का संस्थापक सदस्य है।

ऊपर दिए गए कथनों में से कौन सा सही है / हैं?

a) केवल 1 और 2
b) केवल 1 और 3
c) केवल 2 और 3
d) उपरोक्त सभी

Q.136) Solution (a)

विकल्प 1	विकल्प 2	विकल्प 3
सत्य	**सत्य**	**असत्य**
यह एक स्वतंत्र अंतर सरकारी निकाय है जिसका मिशन सीमा शुल्क प्रशासन की प्रभावशीलता और दक्षता को बढ़ाना है।	यह एकमात्र वैश्विक संगठन है जो सीमा शुल्क मंजूरी के लिए वैश्विक मानकों और प्रक्रियाओं को परिभाषित करता है।	भारत एक सदस्य है, लेकिन एक संस्थापक सदस्य नहीं है। विश्व सीमा संगठन (WCO) के नीति आयोग (Policy Commission) का 80 वां सत्र भारत में आयोजित किया गया था।

Q.137) निम्नलिखित में से कौन, नई औद्योगिक नीति 1991 की विशेषता नहीं है

a) विदेशी निवेश का उदारीकरण
b) सार्वजनिक क्षेत्र के सभी उद्योगों का अनारक्षण (De-Reservation)
c) सार्वजनिक क्षेत्र का विनिवेश
d) औद्योगिक लाइसेंसिंग प्रणाली का उन्मूलन

Q.137) Solution (c)

नई औद्योगिक नीति 1991 में सुधार

- औद्योगिक लाइसेंसिंग प्रणाली का उन्मूलन
- सार्वजनिक क्षेत्र का विनिवेश
- औद्योगिक लाइसेंसिंग प्रणाली का उन्मूलन
- सार्वजनिक क्षेत्र के अधिकांश उद्योगों का अनारक्षण
    - दो क्षेत्र- परमाणु ऊर्जा और रेलवे संचालन- विशेष रूप से सार्वजनिक क्षेत्र के लिए आरक्षित हैं।

Q.138) ICEGATE पोर्टल, निम्नलिखित में से किससे संबंधित है?

a) व्यापार और कार्गो वाहक तथा सीमा शुल्क विभाग के अन्य ग्राहकों के लिए ई-फाइलिंग सेवाएं।
b) सीमाओं के पार कागज रहित प्रसंस्करण और व्यापार की सुविधा के लिए सहायक दस्तावेजों को अपलोड करना।
c) व्यापार को सुविधाजनक बनाने के लिए सिंगल विंडो इंटरफ़ेस।
d) करदाता की फास्ट-ट्रैकिंग शिकायत निवारण।

Q.138) Solution (a)

- ICEGATE का अर्थ 'भारतीय सीमा शुल्क इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स / इलेक्ट्रॉनिक डेटा इंटरचेंज (EC / EDI) गेटवे' है।
- नेशनल गेटवे, केंद्रीय सीमा शुल्क और उत्पाद शुल्क बोर्ड (CBEC) के अधीन है।
- यह भारतीय सीमा शुल्क का एक ई-कॉमर्स पोर्टल है जो व्यापार और कार्गो वाहक तथा सीमा शुल्क विभाग के अन्य ग्राहकों को ई-फाइलिंग सेवाएं प्रदान करता है।
- इस सुविधा के द्वारा, विभाग बिल ऑफ एंट्री, शिपिंग बिल और संबंधित इलेक्ट्रॉनिक संदेश कस्टम और ट्रेडिंग पार्टनर्स के बीच इलेक्ट्रॉनिक फाइलिंग प्रदान करता है।

Q.139) स्फूर्ति (SFURTI) योजना के बारे में, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें

1. इसे खादी और ग्रामोद्योग आयोग (KVIC) और कॉयर बोर्ड (Coir Board) द्वारा कार्यान्वित किया जा रहा है।
2. इसका उद्देश्य पारंपरिक उद्योग कारीगरों और ग्रामीण उद्यमियों के लिए सतत रोजगार प्रदान करना है।

नीचे दिए गए कूट का उपयोग करके सही उत्तर चुनें

a) केवल 1
b) केवल 2
c) 1 और 2 दोनों
d) न तो 1 और न ही 2

Q.139) Solution (c)

कथन 1	कथन 2
सत्य	सत्य
नोडल एजेंसियों में KVIC, कॉयर बोर्ड, IIE गुवाहाटी, NIMSME हैदराबाद, NIESBUD नोएडा, सभी MSME DIs और राज्य सरकारों के सभी DICs शामिल हैं।	इस योजना का उद्देश्य पारंपरिक उद्योगों और कारीगरों को समूहों में संगठित करना है ताकि उन्हें प्रतिस्पर्धी बनाया जा सके तथा ऐसे समूहों के पारंपरिक कारीगरों से लैस करने के लिए इस तरह के समूहों के उत्पादों की विपणन क्षमता बढ़ाने हेतु उनके दीर्घकालिक स्थायित्व, सतत रोजगार के लिए सहायता प्रदान की जा सके। इसमें बेहतर कौशल, कारीगरों के लिए सामान्य सुविधाओं और बेहतर उपकरणों के लिए प्रावधान करना, हितधारकों की सक्रिय भागीदारी के साथ क्लस्टर शासन प्रणालियों को मजबूत करना, तथा नए और पारंपरिक कौशल, उन्नत प्रौद्योगिकियों, उन्नत प्रक्रियाओं, बाजार आसूचना और नए सार्वजनिक-निजी भागीदारी के मॉडल का निर्माण करना, ताकि धीरे-धीरे क्लस्टर-आधारित पुनर्जीवित पारंपरिक उद्योगों के समान मॉडल को दोहराया जा सके

Q.140) निम्नलिखित में से किस कंपनी को सार्वजनिक उद्यम विभाग द्वारा "महारत्न" का दर्जा दिया गया है?

1. भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड
2. भारत संचार निगम लिमिटेड
3. तेल और प्राकृतिक गैस निगम

नीचे दिए गए कूट का उपयोग करके सही उत्तर चुनें

a) केवल 1 और 2
b) केवल 1 और 3
c) केवल 2 और 3
d) उपरोक्त सभी

Q.140) Solution (b)

महारत्न कंपनी

- भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड
- भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड
- कोल इंडिया लिमिटेड
- गेल (इंडिया) लिमिटेड
- हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड
- इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड
- एनटीपीसी लिमिटेड
- तेल और प्राकृतिक गैस निगम लिमिटेड
- पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड
- स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड

Q.141) निम्नलिखित में से कौन, देश के भुगतान संतुलन का अदृश्य खाता (invisible account) है?

1. सेवाओं में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार।
2. ऋण पर ब्याज।
3. श्रमिक आय का प्रेषण।

नीचे दिए गए कूट का उपयोग करके सही उत्तर चुनें

a) केवल 1 और 2
b) केवल 1 और 3
c) केवल 2 और 3
d) उपरोक्त सभी

Q.141) Solution (d)

भुगतान संतुलन (BOP) एक देश और विश्व के बाकी हिस्सों के बीच एक निर्धारित अवधि में किए गए सभी लेन-देन का एक विवरण होता है, जो एक तिमाही या एक वर्ष के रूप में होता है।

यह उन सभी लेनदेन को सारांशित करता है जो किसी देश के व्यक्तियों, कंपनियों, और सरकारी निकायों द्वारा देश के बाहर व्यक्तियों, कंपनियों और सरकारी निकायों के साथ लेनदेन किए जाते हैं। इन लेनदेन में माल, सेवाओं और पूंजी के आयात और निर्यात के साथ-साथ विदेशी सहायता और प्रेषण जैसे हस्तांतरण भुगतान शामिल होते हैं।

भुगतान संतुलन का अदृश्य खाता

- एक देश से दूसरे देश में की गयी सभी सेवाएँ जैसे परिवहन, पर्यटन आदि।
- भुगतान का एक देश से दूसरे देश में हस्तांतरण जैसे प्रेषण, व्यक्तिगत हस्तांतरण आदि।
- एक देश से दूसरे देश में कारक आय जैसे मजदूरी, निवेश पर ब्याज, ऋण आदि।

Q.142) निम्नलिखित में से कौन सा, देश के पूंजीगत खाते का एक हिस्सा है?

a) माल का निर्यात और आयात
b) सेवाओं का निर्यात और आयात
c) एनआरआई जमा
d) एक देश से दूसरे देश में एकतरफा स्थानांतरण

Q.142) Solution (c)

भुगतान संतुलन दो खातों में लेनदेन को विभाजित करता है: चालू खाता और पूंजीगत खाता। कभी-कभी पूंजी खाते को वित्तीय खाता कहा जाता है, जो एक अलग से, आमतौर पर बहुत छोटा, अलग से सूचीबद्ध पूंजी खाता होता है। चालू खाते में माल, सेवाओं, निवेश आय और वर्तमान हस्तांतरण में लेनदेन शामिल होते हैं। व्यापक तौर पर परिभाषित पूंजी खाते में वित्तीय साधन और केंद्रीय बैंक रिज़र्व लेनदेन में शामिल होते हैं। संकीर्ण रूप से परिभाषित, इसमें वित्तीय साधनों में केवल लेनदेन शामिल होते है। चालू खाता राष्ट्रीय उत्पादन की गणना में शामिल होता है, जबकि पूंजी खाता नहीं।

किसी देश का पूंजीगत खाता

- शुद्ध बाह्य सहायता
- शुद्ध बाह्य वाणिज्यिक उधार
- **शुद्ध अनिवासी जमा**
- शुद्ध विदेशी निवेश
- अन्य प्रवाह

Q.143) विशेष आहरण अधिकार (SDR) होल्डिंग्स के बारे में, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें

1. सदस्य देशों की एसडीआर होल्डिंग्स को विश्व बैंक द्वारा आवंटित किया जाता है।
2. एसडीआर होल्डिंग्स किसी देश के विदेशी मुद्रा रिजर्व का एक घटक होते हैं।

नीचे दिए गए कूट का उपयोग करके सही उत्तर चुनें

a) केवल 1
b) केवल 2
c) 1 और 2 दोनों
d) न तो 1 और न ही 2

Q.143) Solution (b)

कथन 1	कथन 2
असत्य	सत्य
1. विशेष आहरण अधिकार (SDR) 1969 में अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष (आईएमएफ) द्वारा निर्मित एक अंतरराष्ट्रीय प्रकार के मौद्रिक आरक्षित मुद्रा	1. SDR होल्डिंग्स किसी देश के विदेशी मुद्रा रिजर्व का एक घटक होते हैं।

का उल्लेख करता है जो सदस्य देशों के मौजूदा मुद्रा भंडार के पूरक के रूप में कार्य करता है। अंतरराष्ट्रीय खातों के निपटान के एकमात्र साधन के रूप में सोने और डॉलर की सीमाओं के बारे में चिंताओं के प्रतिउत्तर में बनाया गया है, SDR ने मानक आरक्षित मुद्राओं को पूरक करके अंतरराष्ट्रीय तरलता को बढ़ाया है। 2. सदस्य देशों की SDR होल्डिंग्स को अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष (IMF) द्वारा आवंटित किया जाता है। यह विश्व व्यापार में देशों की हिस्सेदारी पर आधारित होता है।	2. एक SDR अनिवार्य रूप से आईएमएफ द्वारा उपयोग किया जाने वाला एक कृत्रिम मुद्रा उपकरण है, तथा इसे महत्वपूर्ण राष्ट्रीय मुद्राओं की एक टोकरी से बनाया गया है। 3. आईएमएफ आंतरिक लेखांकन उद्देश्यों के लिए SDR का उपयोग करता है। SDR आईएमएफ द्वारा अपने सदस्य देशों को आवंटित किए जाते हैं और सदस्य देशों की सरकारों के पूर्ण विश्वास और क्रेडिट द्वारा समर्थित होते हैं। SDR के आधार का हर पांच साल में पुनर्मूल्यांकन किया जाता है।

Q.144) बाह्य वाणिज्यिक उधार (ईसीबी) के बारे में, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें।

1. ईसीबी एक अनिवासी ऋणदाता से भारतीय इकाई द्वारा लिया गया ऋण है।
2. ईसीबी का उपयोग शेयर बाजार में निवेश या रियल स्टेट में सट्टेबाज़ी (speculation) के लिए नहीं किया जा सकता है।
3. सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यम, बाह्य वाणिज्यिक उधार के लिए पात्र नहीं हैं।

ऊपर दिए गए कथनों में से कौन सा सही है / हैं?

a) केवल 1 और 2
b) केवल 1 और 3
c) केवल 2 और 3
d) उपरोक्त सभी

Q.144) Solution (a)

कथन 1	कथन 2	कथन 3
सत्य	सत्य	असत्य
ईसीबी एक अनिवासी ऋणदाता से भारतीय इकाई द्वारा लिया गया ऋण है। इनमें से अधिकांश ऋण विदेशी वाणिज्यिक बैंकों द्वारा प्रदान किए जाते हैं।	ईसीबी का उपयोग शेयर बाजार में निवेश या रियल स्टेट में सट्टेबाज़ी (speculation) के लिए नहीं किया जा सकता है।	सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यम बाह्य वाणिज्यिक उधार के लिए पात्र हैं।

Q.145) यदि किसी देश के पास पूंजीगत खाता घाटा (Capital account deficit) है, तो इसका अर्थ है कि

a) देश अन्य देशों में परिसंपत्ति खरीद रहा है।
b) देश में विदेशी लोग परिसंपत्ति खरीद रहे हैं।
c) विदेशियों के प्रति देश की देयता बढ़ रही है।
d) देश के अदृश्य आयात का मूल्य, इसके निर्यात के मूल्य से अधिक है।

Q.145) Solution (a)

- पूंजीगत खाता पूंजी के अन्तर्वाह और बहिर्वाह का एक रिकॉर्ड है जो सीधे किसी देश की विदेशी संपत्ति और देनदारियों को प्रभावित करता है।
- यह एक देश के नागरिकों और दूसरे देशों के लोगों के बीच सभी अंतरराष्ट्रीय व्यापार लेनदेन से संबंधित है।
- पूंजीगत खाते में अधिशेष का अर्थ है कि देश में धन का अन्तर्वाह है, जबकि घाटा देश से धन के बहिर्वाह का संकेत देता है।
- इसलिए, पूंजीगत खाता घाटा का अर्थ है कि देश अन्य देशों में अपनी संपत्ति का विस्तार कर रहा है।

Q.146) भारत में पूर्ण पूंजी परिवर्तनीयता (full capital convertibility) होने के निम्नलिखित में से कौन से लाभ हैं?

1. मुद्रा की अस्थिरता को कम करता है।
2. विदेशी निवेशकों का विश्वास बढ़ाता है।
3. विदेशी बाजारों तक बेहतर पहुंच होती है।

नीचे दिए गए कूट का उपयोग करके सही उत्तर चुनें

a) केवल 1 और 2
b) केवल 1 और 3
c) केवल 2 और 3
d) उपरोक्त सभी

Q.146) Solution (c)

भारत में पूर्ण पूंजी परिवर्तनीयता होने के लाभ

- विदेशी निवेशकों का विश्वास बढ़ना। यह विभिन्न व्यवसायों और क्षेत्रों के लिए पूंजी तक आसान पहुंच की अनुमति देता है, जो देश की अर्थव्यवस्था को सकारात्मक रूप से प्रभावित करता है।
- विदेशी बाजारों तक बेहतर पहुंच। स्थानीय व्यवसाय तुलनात्मक रूप से कम लागत पर विदेशी ऋण की आसान पहुंच से लाभ उठा सकते हैं।
- तारापोर समिति, जिसे रुपये की पूर्ण परिवर्तनीयता का आकलन करने का काम सौंपा गया था, ने पूर्ण रुपये परिवर्तनीयता के बाद कई लाभों का उल्लेख किया है।

भारत में पूर्ण पूंजी परिवर्तनीयता होने के नुकसान

- उच्च अस्थिरता - उच्च स्तर की अस्थिरता, अवमूल्यन, या विदेशी मुद्रा दरों में मुद्रास्फीति, देश की अर्थव्यवस्था को चुनौती दे सकती है।
- विदेशी ऋण बोझ - व्यवसाय विदेशी ऋण को आसानी से बढ़ा सकते हैं, लेकिन यदि विनिमय दरें प्रतिकूल हो जाती हैं, तो वे उच्च भुगतान के जोखिम से ग्रस्त होती हैं।

Q.147) मुद्रा के मूल्यह्रास (depreciation of currency) के निम्नलिखित में से कौन से प्रभाव हैं?

1. आयातित सामान अधिक महंगे हो जाते हैं।
2. मुद्रास्फीति में वृद्धि।
3. अंतर्राष्ट्रीय बाजार में माल की मांग में वृद्धि।

नीचे दिए गए कूट का उपयोग करके सही उत्तर चुनें

a) केवल 1 और 2
b) केवल 1 और 3
c) केवल 2 और 3
d) उपरोक्त सभी

Q.147) Solution (a)

विकल्प 1	विकल्प 2	विकल्प 3
सत्य	सत्य	असत्य
घरेलू मुद्रा के मूल्य में गिरावट आने पर आयातित माल और अधिक महंगा हो जाता है।	मूल्यह्रास लागत प्रेरित मुद्रास्फीति और मांग-प्रेरित मुद्रास्फीति दोनों को बढ़ाता है।	मूल्यह्रास घरेलू वस्तुओं का अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में अधिक प्रतिस्पर्धी बनने का कारण बनता है।

Q.148) भारत के विदेशी मुद्रा भंडार (foreign exchange reserves) में शामिल हैं

1. RBI के पास विदेशी मुद्रा आस्तियाँ।
2. व्यक्तिगत नागरिकों द्वारा आयोजित विदेशी मुद्रा संपत्ति।
3. RBI के पास स्वर्ण भंडार।

नीचे दिए गए कूट का उपयोग करके सही उत्तर चुनें

a) केवल 1 और 2
b) केवल 1 और 3
c) केवल 2 और 3
d) उपरोक्त सभी

Q.148) Solution (b)

किसी देश का विदेशी मुद्रा भंडार

- RBI के पास विदेशी मुद्रा आस्तियाँ।
- RBI के पास स्वर्ण भंडार।
- विशेष आहरण अधिकार होल्डिंग्स
- रिवर्स ट्रेन्च (Reverse Tranche)

Q.149) कृषि निर्यात नीति 2018 के बारे में, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें

1. इसका लक्ष्य 2022 तक कृषि निर्यात को दोगुना करना है।
2. कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय इसके कार्यान्वयन के लिए नोडल मंत्रालय है

नीचे दिए गए कूट का उपयोग करके सही उत्तर चुनें

a) केवल 1
b) केवल 2
c) 1 और 2 दोनों
d) न तो 1 और न ही 2

Q.149) Solution (a)

कथन 1	कथन 2
सत्य	असत्य
इसका लक्ष्य 2022 तक $ 60 बिलियन से कृषि निर्यात को	वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय इसके कार्यान्वयन के लिए

दोगुना करना है।	नोडल मंत्रालय है

Q.150) निर्यात-आयात बैंक (EXIM) के बारे में, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें।

1. EXIM बैंक संसद के एक अधिनियम द्वारा बनाया गया था।
2. बैंक का प्राथमिक उद्देश्य देश के आयातकों और निर्यातकों की सहायता करना है।

उपरोक्त कथनों में से कौन गलत है / हैं?

a) केवल 1
b) केवल 2
c) 1 और 2 दोनों
d) न तो 1 और न ही 2

Q.150) Solution (d)

कथन 1	कथन 2
सत्य	सत्य
भारतीय निर्यात-आयात बैंक, भारत में एक वित्तीय संस्थान है, जिसकी स्थापना 1982 में भारतीय निर्यात-आयात बैंक अधिनियम 1981 के तहत की गई थी	भारतीय निर्यात और आयात बैंक का मुख्य कार्य देश के आयातकों और निर्यातकों को वित्तीय और अन्य सहायता प्रदान करना है।

Q.151) भारत की 7 वीं व्यापार नीति समीक्षा सितंबर 2020 में आयोजित होने वाली है। निम्नलिखित में से कौन सा संगठन व्यापार नीति की समीक्षा करता है?

a) विश्व व्यापार संगठन
b) विश्व सीमा शुल्क संगठन
c) व्यापार और विकास पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन
d) अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष

Q.151) Solution (a)

व्यापार नीति की समीक्षा (Trade Policy Review)

- विश्व व्यापार संगठन द्वारा किसी देश की व्यापार नीति समीक्षा अक्सर आयोजित की जाती है।
- सभी विश्व व्यापार संगठन के सदस्यों की समीक्षा की जाती है, प्रत्येक देश की समीक्षा की आवृत्ति विश्व व्यापार के अपने हिस्से के अनुसार बदलती है।
- TPRM के उद्देश्यों में सदस्यों की व्यापार नीतियों की पारदर्शिता को बढ़ाकर बहुपक्षीय व्यापार प्रणाली के सुचारू संचालन को सुगम बनाना शामिल है।
- डब्ल्यूटीओ में भारत की सातवीं व्यापार नीति की समीक्षा 15 और 17 सितंबर 2020 को होने वाली है।

Q.152) अंतर्राष्ट्रीय ऋण सांख्यिकी (International Debt Statistics) रिपोर्ट, किसके द्वारा जारी किया जाता है

a) विश्व व्यापार संगठन
b) विश्व बैंक
c) विश्व आर्थिक मंच
d) अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष

Q.152) Solution (b)

अंतर्राष्ट्रीय ऋण सांख्यिकी

- अंतर्राष्ट्रीय ऋण सांख्यिकी (आईडीएस) विश्व बैंक की देनदार रिपोर्टिंग प्रणाली में 128 देशों के बाह्य ऋण और वित्तीय प्रवाह (ऋण और इक्विटी) पर विश्व बैंक का डेटाबेस है।
- यह प्रत्येक वर्ष प्रकाशित होता है।

Q.153) निम्नलिखित कथनों पर विचार करें

1. सेवाओं में व्यापार को अदृश्य व्यापार के रूप में निरूपित किया जाता है क्योंकि वे राष्ट्रीय सीमाओं को पार करते नहीं दिखाई देते हैं।
2. जीडीपी के अनुपात के रूप में कुल विदेशी व्यापार एक अर्थव्यवस्था के खुलेपन की डिग्री की एक सामान्य माप है।

ऊपर दिए गए कथनों में से कौन सा सही है / हैं?

a) केवल 1
b) केवल 2
c) 1 और 2 दोनों
d) न तो 1 और न ही 2

Q.153) Solution (c)

कथन 1	कथन 2
सत्य	सत्य
सेवाओं में व्यापार को अदृश्य व्यापार के रूप में निरूपित किया जाता है क्योंकि वे राष्ट्रीय सीमाओं को पार करते नहीं दिखाई देते हैं। इसमें कारक आय और शुद्ध गैर-कारक आय दोनों शामिल होती हैं।	जीडीपी के अनुपात के रूप में कुल विदेशी व्यापार एक अर्थव्यवस्था के खुलेपन की डिग्री की एक सामान्य माप है।

Q.154) निम्नलिखित कथनों पर विचार करें

1. वास्तविक विनिमय दर (real exchange rate) को अक्सर देश की अंतरराष्ट्रीय प्रतिस्पर्धा की माप के रूप में लिया जाता है।
2. यदि वास्तविक विनिमय दर शून्य के बराबर है, तो मुद्राएं क्रय शक्ति समता (PPP) पर होती हैं।

ऊपर दिए गए कथनों में से कौन सा सही है / हैं?

a) केवल 1
b) केवल 2
c) 1 और 2 दोनों
d) न तो 1 और न ही 2

Q.154) Solution (a)

कथन 1	कथन 2
सत्य	असत्य

वास्तविक विनिमय दर को अक्सर देश की अंतरराष्ट्रीय प्रतिस्पर्धा के माप के रूप में लिया जाता है।	यह आवश्यक नहीं है कि यदि वास्तविक विनिमय दर शून्य के बराबर है, तो मुद्राएं क्रय शक्ति समता पर होंगी।

Q.155) हाल ही में, भारत ने निम्नलिखित में से किस देश के साथ मुद्रा विनिमय समझौते (currency swap agreement) पर हस्ताक्षर किए हैं?

a) अमेरीका
b) चीन
c) ब्राज़ील
d) जापान

Q.155) Solution (d)

भारत-जापान मुद्रा विनिमय समझौता (India-Japan Currency Swap Agreement)

- एक द्विपक्षीय मुद्रा विनिमय एक निश्चित विनिमय दर पर एक देश से दूसरे देश में एक ओपन-एंडेड क्रेडिट लाइन है।
- जबकि भारत में कई एशियाई देशों के साथ ऐसी व्यवस्था है, लेकिन जापान इस तरह के समझौतों में सबसे बड़ी व्यवस्था है, जो 75 बिलियन डॉलर की है।
- मुद्रा विनिमय की व्यवस्था भारतीय केंद्रीय बैंक को जापानी सरकार से ऋण के रूप में $ 75 बिलियन येन या डॉलर तक लेने की अनुमति देगा, जब भी उसे इस धन की आवश्यकता होगी।

Q.156) प्रबंधित फ्लोटिंग विनिमय दर प्रणाली (Managed floating exchange rate system) के बारे में, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें

1. यह एक लचीली विनिमय दर प्रणाली और एक निश्चित दर प्रणाली का मिश्रण है।
2. इसमें, केंद्रीय बैंक तभी हस्तक्षेप करते हैं, जब आवश्यकता होती है, जैसे विदेशी मुद्राओं को खरीदने और बेचने के लिए विनिमय दर संचलन को मध्यम करने के प्रयास में।

नीचे दिए गए कूट का उपयोग करके सही उत्तर चुनें

a) केवल 1
b) केवल 2
c) 1 और 2 दोनों
d) न तो 1 और न ही 2

Q.156) Solution (c)

विनिमय दर (विदेशी विनिमय दर) वह दर है जिस पर घरेलू मुद्रा का विदेशी मुद्रा के साथ कारोबार किया जाता है। इसी तरह, यह वह दर है जो अन्य मुद्राओं के संदर्भ में घरेलू मुद्रा के मूल्य को दर्शाती है।

कथन 1	**कथन 2**
सत्य	**सत्य**
प्रबंधित फ्लोटिंग विनिमय दर प्रणाली एक लचीली विनिमय दर प्रणाली और एक निश्चित दर प्रणाली का मिश्रण है। 1. इस संकर विनिमय दर प्रणाली में, विनिमय दर मूल	इसमें, केंद्रीय बैंक तभी हस्तक्षेप करते हैं, जब आवश्यकता होती है, जैसे विदेशी मुद्राओं को खरीदने और बेचने के लिए विनिमय दर संचलन को मध्यम करने के प्रयास में। इसलिए, आधिकारिक आरक्षित लेनदेन शून्य के बराबर

रूप से विदेशी मुद्रा बाजार में बाजार शक्तियों के संचालन के माध्यम से निर्धारित की जाती है। बाजार की शक्तियों का अर्थ विभिन्न व्यक्तियों और संस्थानों द्वारा बेचने और खरीदने की गतिविधियां हैं। अब तक, प्रबंधित फ्लोटिंग विनिमय दर प्रणाली लचीली विनिमय दर प्रणाली के समान है। 2. लेकिन अत्यधिक उतार-चढ़ाव के दौरान, एक प्रबंधित फ्लोटिंग विनिमय दर प्रणाली (RBI जैसे) के तहत केंद्रीय बैंक विदेशी मुद्रा बाजार में हस्तक्षेप करता है। इस हस्तक्षेप का उद्देश्य रुपये की विनिमय दर में उतार-चढ़ाव को कम करना है।	नहीं होता हैं।

Q.157) भारत के व्यापार संबंधों के बारे में, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें

1. भारत का 2018-19 में चीन सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार था।
2. भारत का 2018-19 में यूएसए के साथ व्यापार अधिशेष था।

नीचे दिए गए कूट का उपयोग करके गलत उत्तर चुनें

a) केवल 1
b) केवल 2
c) 1 और 2 दोनों
d) न तो 1 और न ही 2

Q.157) Solution (a)

कथन 1	कथन 2
असत्य	**सत्य**
वाणिज्य मंत्रालय के आंकड़ों के अनुसार, 2018-19 में, यूएसए और भारत के बीच द्विपक्षीय व्यापार 87.95 बिलियन अमरीकी डॉलर था, जबकि चीन के साथ भारत का व्यापार 87.07 बिलियन अमरीकी डॉलर था। इस प्रकार यूएसए भारत का शीर्ष व्यापारिक भागीदार बनते हुए लिए चीन से आगे निकल गया है।	2018-19 में, भारत के पास अमेरिका के साथ 16.85 बिलियन डॉलर का व्यापार अधिशेष था।

Q.158) निम्नलिखित में से कौन सा कारक, मुद्रा की विनिमय दर निर्धारित करता है?

1. बाजार की धारणा
2. ब्याज दर
3. राजकोषीय नीति

नीचे दिए गए कूट का उपयोग करके सही उत्तर चुनें

a) केवल 1
b) केवल 1 और 2
c) केवल 2 और 3
d) उपरोक्त सभी

Q.158) Solution (d)

कथन 1	कथन 2	कथन 3
सत्य	सत्य	सत्य
अशांत बाजारों के दौरान, निवेशक स्थिर मुद्राओं में निवेश करना चाहेंगे।	सरकारी बॉन्ड के लिए उच्च-ब्याज दरें अधिक विदेशी निवेशकों को आकर्षित करती हैं। इससे मुद्रा में उतार-चढ़ाव हो सकता है।	सरकार अंतर्राष्ट्रीय संस्थानों जैसे WB, IMF से व्यय आपूर्ति के लिए पैसे उधार लेती है। इससे मुद्रा में उतार-चढ़ाव हो सकता है।

Q.159) निम्न में से कौन मुद्रा के अवमूल्यन होने पर लागत-प्रेरित मुद्रास्फीति (Cost-push inflation) की ओर जाता है?

a) आयातित कच्चे माल की कीमतों में वृद्धि।
b) विदेशी वस्तुओं के महंगे हो जाने के कारण स्थानीय वस्तुओं की मांग में वृद्धि।
c) स्थानीय वस्तुओं की मांग में वृद्धि क्योंकि अधिक वस्तुओं को निर्यात किया जाता है।
d) विदेशी निवेश में वृद्धि।

Q.159) Solution (a)

- मुद्रा के अवमूल्यन से लागत-प्रेरित मुद्रास्फीति और मांग-प्रेरित मुद्रास्फीति दोनों हो जाते हैं।
- लागत - प्रेरित मुद्रास्फ़ीति -
  - आयातित कच्चे माल की कीमतों में वृद्धि। यह उत्पादन की कीमत को बढ़ाता है।
- मांग -प्रेरित मुद्रास्फीति -
  - विदेशी वस्तुओं के महंगे हो जाने के कारण स्थानीय वस्तुओं की मांग में वृद्धि।
  - स्थानीय वस्तुओं की मांग में वृद्धि क्योंकि अधिक वस्तुओं को निर्यात किया जाता है।

Q.160) भुगतान संतुलन (BoP) के संदर्भ में, लेन-देन समायोजन (accommodating transaction) क्या हैं?

a) भुगतान संतुलन (BoP) रिकॉर्ड में असंतुलन
b) चालू खाता लेनदेन।
c) भुगतान संतुलन अधिशेष या घाटे को संतुलित करने के लिए किए गए लेन-देन।
d) लेन-देन, जो लाभ अधिकतम करने के उद्देश्य से किए जाते हैं।

Q.160) Solution (c)

समायोजित लेनदेन (Accommodating Transactions)

- चालू खाते (Current account) और स्वायत्त लेनदेन (autonomous transactions) के कारण भुगतान संतुलन (BoP) के अधिशेष या घाटे को संतुलित करने के लिए किए गए लेन-देन को समायोजित लेनदेन कहा जाता है।
- इसमें शामिल है -
  - विदेशी मुद्रा रिज़र्व
  - आईएमएफ या विदेशी मौद्रिक प्राधिकरणों से उधार

Q.161) ओपेक (OPEC) के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें

1. पेट्रोलियम निर्यातक देशों का संगठन (OPEC) एक स्थायी, संयुक्त राष्ट्र संगठन है, जिसे 1960 में बगदाद सम्मेलन में स्थापित किया गया था।
2. ओपेक का वर्तमान मुख्यालय जिनेवा, स्विट्जरलैंड में है।
3. हाल ही में, भारत ओपेक का सहयोगी सदस्य बना है।

उपरोक्त कथनों में से कौन सा सही है / हैं?

a) केवल 1 और 2
b) केवल 1
c) केवल 1 और 3
d) इनमें से कोई भी नहीं

Q.161) Solution (d)

कथन 1	कथन 2	कथन 3
असत्य	असत्य	असत्य
पेट्रोलियम निर्यातक देशों का संगठन (OPEC) एक स्थायी, अंतर सरकारी संगठन है, जिसे ईरान, इराक, कुवैत, सऊदी अरब और वेनेजुएला द्वारा 10 से 14 सितंबर, 1960 को बगदाद सम्मेलन में स्थापित किया गया था।	OPEC का मुख्यालय जिनेवा, स्विट्जरलैंड में अपने अस्तित्व के पहले पांच वर्षों में था। इसे 1 सितंबर, 1965 को ऑस्ट्रिया के वियना ले जाया गया। OPEC का उद्देश्य पेट्रोलियम उत्पादकों के लिए उचित और स्थिर कीमतों को सुरक्षित करने के लिए, सदस्य देशों के बीच पेट्रोलियम नीतियों का समन्वय और एकीकरण करना है; जिससे उपभोक्ता राष्ट्रों को पेट्रोलियम की एक कुशल, आर्थिक और नियमित आपूर्ति; और उद्योग में निवेश करने वालों के लिए पूंजी पर एक उचित लाभ प्राप्त हो सके।	भारत OPEC का सहयोगी सदस्य नहीं है

Q.162) निम्नलिखित कथनों पर विचार करें

1. व्यापार की शर्तें (TOT) भुगतान संतुलन के लिए, व्यापार संतुलन के बीच अनुपात का प्रतिनिधित्व करती हैं
2. जब किसी देश का TOT, 100% से कम होता है, तो देश अपने आयात पर व्यय की तुलना में, निर्यात से अधिक पूंजी संग्रहित कर रहा होता है।

उपरोक्त कथनों में से कौन सा सही है / हैं?

a) केवल 1
b) केवल 2
c) 1 और 2 दोनों
d) इनमें से कोई भी नहीं

Q.162) Solution (d)

कथन 1	कथन 2
असत्य	असत्य
व्यापार की शर्तें (TOT) किसी देश की निर्यात कीमतों और उसके आयात की कीमतों के बीच के अनुपात का प्रतिनिधित्व करती हैं। आयात की कीमत से निर्यात की कीमत को विभाजित करके और परिणाम को 100 से गुणा करके अनुपात की गणना की जाती है।	जब किसी देश का TOT 100% से कम होता है, तो देश में प्रवेश करने की तुलना में अधिक पूंजी देश को छोड़ रही होती है। जब टीओटी 100% से अधिक हो जाता है, तो देश निर्यात से अधिक पूंजी संग्रहित कर रहा होता है, जितना कि वह आयात पर व्यय कर रहा होता है।

Q.163) निम्नलिखित कथनों पर विचार करें

1. शहरी पर्यटन पर 2019 UNWTO वैश्विक शिखर सम्मेलन दक्षिण कोरिया की राजधानी सियोल में आयोजित किया गया था।
2. शिखर सम्मेलन का विषय 'स्मार्ट शहर, स्मार्ट गंतव्य' (Smart Cities, Smart Destinations) था।

उपरोक्त कथनों में से कौन सा सही है / हैं?

a) केवल 1
b) केवल 2
c) 1 और 2 दोनों
d) इनमें से कोई भी नहीं

Q.163) Solution (b)

UNWTO और नूर-सुल्तान के मेयर्स कार्यालय (Mayor's Office) ने, स्मार्ट शहर, स्मार्ट गंतव्य' विषय के तहत 9-12 अक्टूबर, 2019 को नूर-सुल्तान, कजाकिस्तान में शहरी पर्यटन पर 8 वें यूएनडब्ल्यूटीओ वैश्विक शिखर सम्मलेन का आयोजन किया। 80 से अधिक देशों के प्रतिनिधि, जिनमें 10 महापौर, उप-महापौर और साथ ही पर्यटन मंत्री और निजी क्षेत्र के प्रतिनिधि शामिल थे, ने बताया कि स्मार्ट शहरी गंतव्य विकसित करने से विश्व भर में आज हो रही जटिल शहरी पर्यटन चुनौतियों का सामना करने में योगदान कैसे हो सकता है।

सततता, पहुंच, शहरी प्रबंधन, नवाचार और प्रौद्योगिकी में सबसे महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा की गई, जबकि व्यापक शहरी एजेंडे में पर्यटन को शामिल करने के महत्व के रूप में पर्यटन को शामिल करके, समावेशी, लचीला और सतत शहरों के विकास में एक सच्चे योगदानकर्ता के रूप में महत्व दिया गया।

शिखर सम्मेलन में राष्ट्रीय और शहरों के प्रतिनिधियों ने आधिकारिक तौर पर 'स्मार्ट शहर, स्मार्ट गंतव्य' पर नूर-सुल्तान घोषणा को अपनाया। घोषणा में पर्यटन स्थलों के रूप में शहरों की बढ़ती लोकप्रियता और सामाजिक-आर्थिक विकास को बढ़ावा देने तथा अद्वितीय संस्कृति को बढ़ावा देने और संरक्षित करने की उनकी क्षमता को मान्यता दी गई है।

Q.164) निम्नलिखित में से कौन सी, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष द्वारा प्रकाशित रिपोर्टें हैं?

1. विश्व आर्थिक आउटलुक
2. राजकोषीय निगरानी (Fiscal monito)
3. वैश्विक वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट
4. वैश्विक वित्तीय प्रणाली रिपोर्ट

सही कूट चुनें

a) केवल 1, 2 और 3
b) केवल 1, 2 और 4
c) केवल 1, 3 और 4
d) उपरोक्त सभी

Q.164) Solution (a)
अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष द्वारा प्रकाशित रिपोर्टों में शामिल हैं

1. विश्व आर्थिक आउटलुक
2. राजकोषीय निगरानी
3. वैश्विक वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट

बीआईएस (बैंक फॉर इंटरनेशनल सेटलमेंट्स) -वैश्विक वित्तीय प्रणाली रिपोर्ट

Q.165) अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष और विश्व बैंक, दोनों में शामिल होने वाला नवीनतम देश कौन सा है?
a) नाउरू
b) दक्षिण सूडान
c) तुवालु
d) लाइबेरिया

Q.165) Solution (a)
प्रशांत महासागर में एक छोटा सा दक्षिणी प्रशांत द्वीपीय राष्ट्र नाउरू गणराज्य, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष (IMF) और विश्व बैंक यानी ब्रेटन-वुड्स संस्थान का 189 वां सदस्य बन गया।

तुवालु के बाद नाउरू IMF का दूसरा सबसे छोटा सदस्य होगा। यह 14 वीं सामान्य समीक्षा के तहत अपने कोटा में वृद्धि का भुगतान करने के बाद सदस्य होगा (जो कि एसडीआर 2.8 मिलियन तक अपने कोटा में वृद्धि करेगा)। नाउरू की एसडीआर की आरंभिक सदस्यता 2 मिलियन यानी लगभग 2.81 मिलियन अमेरिकी डॉलर है।

जून 2015 में बेंडिगो बैंक एजेंसी खोलने तक पिछले एक दशक के दौरान देश में लगभग कोई बैंक नहीं था।

नाउरू की अर्थव्यवस्था फॉस्फेट खनन और मछली पकड़ने के लाइसेंस शुल्क से राजस्व पर निर्भर करती है। हाल के वर्षों में, विकास मजबूत रहा है, मुख्य रूप से फॉस्फेट निर्यात द्वारा संचालित है, हालांकि 2015 में मध्यम स्तर पर फॉस्फेट निर्यात को कम करने वाली समस्याओं के कारण इसमें कमी आई है।

सदस्यता कोष और अन्य विकास साझेदारों को अनुमति देता है - देश विश्व बैंक में भी शामिल हो गया है - जो अधिकारियों को आर्थिक सुधारों को लागू करने और नाउरू के सामने आने वाली विकास चुनौतियों से निपटने में मदद करेगी। आईएमएफ (जिसे अनुच्छेद IV परामर्श कहा जाता है), अंतर-राष्ट्र विश्लेषण और आईएमएफ उधार का उपयोग करके देश अब अपनी अर्थव्यवस्था की वार्षिक समीक्षा या "स्वास्थ्य जांच" से लाभान्वित हो सकता है। फ़िरोजी स्थित प्रशांत वित्तीय तकनीकी सहायता केंद्र (PFTAC) के माध्यम से नाउरू को तकनीकी सहायता प्राप्त होती रहेगी।

नाउरू अब ब्रेटन वुड्स परिवार के एक पूर्ण सदस्य के रूप में संयुक्त आईएमएफ-विश्व बैंक स्प्रिंग और वार्षिक बैठकों में भी भाग ले सकते हैं, जहां अधिकारी अन्य प्रतिनिधिमंडलों के साथ विचारों का आदान-प्रदान कर सकते हैं। 2016 स्प्रिंग मीटिंग्स इस सप्ताह, 15-17 अप्रैल को आयोजित की जाएगी।

विश्व व्यापार संगठन में शामिल होने वाला लाइबेरिया नवीनतम देश है।

Q.166) निम्नलिखित में से कौन वैश्विक दासता सूचकांक (Global slavery Index) रिपोर्ट प्रकाशित करता है?

a) अंतर्राष्ट्रीय श्रम ब्यूरो
b) वॉक फ्री फाउंडेशन
c) जर्मनवाच
d) अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक संगठन

Q.166) Solution (b)
वैश्विक दासता सूचकांक 2018 ने अपनी नवीनतम रिपोर्ट में अनुमान लगाया है कि 2016 में किसी भी दिन भारत में "आधुनिक दासता" में लगभग 8 मिलियन लोग रहते थे।

वॉक फ्री फाउंडेशन द्वारा निर्गत रिपोर्ट में कहा गया है कि प्रचलन के संदर्भ में, हर हजार लोगों पर 6.1 पीड़ित थे। 167 देशों में, भारत सूची में सबसे ऊपर उत्तर कोरिया के साथ 53 वें स्थान पर 104.6 प्रति 1,000 तथा जापान सबसे कम प्रसार दर 03 प्रति 1,000 दर्ज किया है।

Q.167) निम्नलिखित कथनों पर विचार करें

1. विश्व विकास सूचना दिवस 24 अक्टूबर को संयुक्त राष्ट्र दिवस के साथ मनाया जाता है
2. यह व्यापार और विकास पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन (UNCTAD) द्वारा सूचना प्रसार तथा व्यापार और विकास समस्याओं के सापेक्ष जनता की राय के एकत्रीकरण के लिए आरंभ किया गया था।

उपरोक्त कथनों में से कौन सा सही है / हैं?

a) केवल 1
b) केवल 2
c) 1 और 2 दोनों
d) इनमें से कोई भी नहीं

Q.167) Solution (c)

कथन 1	**कथन 2**
सत्य	**सत्य**
17 मई, 1972 को, व्यापार और विकास पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन (UNCTAD) ने सूचना प्रसार तथा व्यापार और विकास समस्याओं के सापेक्ष जनता की राय के एकत्रीकरण के लिए उपायों का प्रस्ताव रखा। इन्हें संकल्प 3038 (XXVII) के रूप में जाना जाता है, जिसे संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 19 दिसंबर 1972 को पारित किया था। 1972 में महासभा ने विकास समस्याओं के लिए संसार का ध्यान आकर्षित करने और उन्हें हल करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को मजबूत करने की आवश्यकता के लिए विश्व विकास सूचना दिवस की	महासभा ने माना कि सूचना के प्रसार और जनता की राय में सुधार, विशेष रूप से युवा लोगों के बीच, विकास की समस्याओं के बारे में अधिक जागरूकता पैदा करेगा, इस प्रकार, विकास के लिए अंतर्राष्ट्रीय सहयोग के क्षेत्र में प्रयासों को बढ़ावा देगा।

स्थापना की (संकल्प 3038 (XXVII)) थी। महासभा ने निर्णय लिया कि विश्व विकास सूचना दिवस 24 अक्टूबर को संयुक्त राष्ट्र दिवस के साथ मनाया जाता है।	

Q.168) सबसे पसंदीदा राष्ट्र (MFN) स्थिति के संदर्भ में, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें

1. यह एक गैर-भेदभावपूर्ण व्यापार नीति है जो विशिष्ट व्यापार विशेषाधिकारों के बजाय सभी डब्ल्यूटीओ सदस्य देशों के बीच समान व्यापार सुनिश्चित करता है
2. एमएफएन की स्थिति विश्व व्यापार संगठन (WTO) के शुल्क और व्यापार पर सामान्य समझौते (GATT) द्वारा संचालित है।
3. वर्तमान में भारत ने पाकिस्तान को छोड़कर सभी डब्ल्यूटीओ सदस्यों को 'सबसे पसंदीदा राष्ट्र' का दर्जा दिया है

उपरोक्त कथन में से कौन सा सही है / हैं?

a) केवल 1 और 2
b) केवल 2 और 3
c) केवल 1 और 3
d) उपरोक्त सभी

Q.168) Solution (d)

कथन 1	कथन 2	कथन 3
सत्य	सत्य	सत्य
एमएफएन स्थिति के तहत, एक डब्ल्यूटीओ सदस्य देश अन्य व्यापारिक देशों के साथ गैर-भेदभावपूर्ण तरीके से व्यवहार करने के लिए बाध्य है, विशेष रूप से सीमा शुल्क और अन्य लेवी के संबंध में। 2. विश्व व्यापार संगठन का कहना है कि अगर एक देश दूसरे देश के पक्ष में विस्तार करता है, तो देश को रियायत वापस करना चाहिए। 3. यद्यपि एमएफएन विशेष उपचार की तरह लगता है, परन्तु इसका वास्तव में अर्थ, गैर-भेदभाव - लगभग सभी के साथ समान रूप से व्यवहार करना है।	एमएफएन स्थिति विश्व व्यापार संगठन (WTO) के शुल्क और व्यापार पर सामान्य समझौते (GATT) द्वारा शासित है। समझौते पर हस्ताक्षर करने वाले देश एक-दूसरे और विश्व व्यापार संगठन के सदस्य देशों के साथ विभेद करते हैं।	1996 में शुल्क और व्यापार पर सामान्य समझौते, 1994 के अनुच्छेद 1 के प्रावधानों के अनुसार, भारत ने पाकिस्तान को छोड़कर, सभी डब्ल्यूटीओ सदस्यों को 'सबसे पसंदीदा राष्ट्र' का दर्जा दिया है।

एमएफएन सिद्धांत यह सुनिश्चित करता है कि प्रत्येक देश अपने 140 से अधिक साथी सदस्यों के साथ समान व्यवहार करे। लेकिन कुछ अपवाद हैं। उदाहरण के लिए:

1. देश एक मुक्त व्यापार समझौता कर सकते हैं जो केवल समूह के भीतर व्यापार किए गए माल पर लागू होता है - बाहरी माल के विरुद्ध विभेद
2. या वे विकासशील देशों को अपने बाजारों तक विशेष पहुंच दे सकते हैं
3. या एक देश उन उत्पादों के खिलाफ बाधाओं को बढ़ा सकता है जिन्हें विशिष्ट देशों से गलत तरीके से कारोबार करने के लिए माना जाता है
4. और सेवाओं में, देशों को, सीमित परिस्थितियों में, भेदभाव करने की अनुमति है
5. लेकिन समझौते केवल इन अपवादों को सख्त शर्तों के तहत अनुमति देते हैं

सामान्य तौर पर, एमएफएन का अर्थ है कि जब भी कोई देश किसी व्यापार अवरोध को कम करता है या एक बाजार खोलता है, तो उसे अपने सभी व्यापारिक भागीदारों से समान वस्तुओं या सेवाओं के लिए ऐसा करना पड़ता है - चाहे वह अमीर हो या गरीब, कमजोर हो या मजबूत हो।

Q.169) एशियाई विकास बैंक के बारे में, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें

1. यह एक क्षेत्रीय विकास बैंक है जिसका मुख्यालय मनीला, फिलीपींस में है, तथा यह एशिया में सामाजिक और आर्थिक विकास को बढ़ावा देने का कार्य करता है।
2. चीन के पास, सदस्यों के बीच शेयरों का सबसे बड़ा अनुपात है।
3. बैंक केवल एशिया-प्रशांत क्षेत्र से सदस्यों को स्वीकार करता है।

उपरोक्त कथनों में से कौन सा सही है / हैं?

a) केवल 1 और 2
b) केवल 2 और 3
c) केवल 1
d) केवल 1 और 3

Q.169) Solution (c)

कथन 1	कथन 2	कथन 3
सत्य	असत्य	असत्य
एशियाई विकास बैंक (ADB) 19 दिसंबर 1966 को स्थापित एक क्षेत्रीय विकास बैंक है, जिसका मुख्यालय फ़िलीपीन्स, मनीला, फिलिपींस के मंडलायुंग शहर में स्थित ऑर्टिगस सेंटर में है। बैंक एशिया में सामाजिक और आर्थिक विकास को बढ़ावा देने के लिए विश्व भर में 31 क्षेत्रीय कार्यालय भी चलाता है। बैंक एशिया और प्रशांत के लिए संयुक्त राष्ट्र आर्थिक और सामाजिक आयोग (UNESCAP), पूर्वी एशिया और सुदूर पूर्व के लिए आर्थिक आयोग (ECAFE) और गैर-क्षेत्रीय	एडीबी को विश्व बैंक की तर्ज पर बनाया गया था, और इसमें एक समान भारित मतदान प्रणाली होती है, जहां सदस्यों के क्षेत्रीय विवरणों के अनुपात में वोट वितरित किए जाते हैं। 31 दिसंबर 2016 तक, जापान के पास शेयरों का सबसे बड़ा अनुपात 15.677% था, इसके बाद संयुक्त राज्य अमेरिका के पास 15.567% पूंजी शेयर थे। चीन के पास 6.473%, भारत के पास 6.359% और ऑस्ट्रेलिया के पास 5.812% था।	एडीबी एक आधिकारिक संयुक्त राष्ट्र पर्यवेक्षक है। 1966 में अपनी स्थापना के समय 31 सदस्यों से एडीबी 68 सदस्यों को शामिल करते हुए विस्तृत हुआ है, जिनमें से 49 एशिया और प्रशांत क्षेत्र के हैं और 19 बाहरी हैं।

विकसित देशों के सदस्यों को स्वीकार करता है। इसकी स्थापना के समय 31 सदस्यों से अब एडीबी के 68 सदस्य हैं।		

Q.170) विशेष आर्थिक क्षेत्रों (SEZ) के तहत क्षेत्र को शुल्कों और करों के उद्देश्य से `विदेशी क्षेत्र' (foreign territory) घोषित किया गया है। निम्नलिखित में से कौन इसके लिए सही कारण बताता है?

1. SEZ से घरेलू टैरिफ क्षेत्र (DTA) के लिए लाए गए सामान को आयातित माल के रूप में माना जाना है
2. SEZ सामान, उत्पाद शुल्क (excise duty) से मुक्त होते हैं
3. DTA से SEZ क्षेत्र में जाने वाली वस्तुओं और सेवाओं को निर्यात के रूप में माना जाता है

सही कूट चुनें

a) केवल 1 और 2
b) केवल 1 और 3
c) केवल 2 और 3
d) उपरोक्त सभी

Q.170) Solution (b)

विशेष आर्थिक क्षेत्र (SEZ) विकास इंजन होते हैं, जो विनिर्माण को बढ़ावा दे सकते हैं, निर्यात बढ़ा सकते हैं और रोजगार पैदा कर सकते हैं। निजी क्षेत्र SEZ के विकास के साथ सक्रिय रूप से जुड़ा हुआ है। SEZ को विशेष राजकोषीय और विनियामक शासन की आवश्यकता होती है ताकि आधुनिक अवसंरचना और समर्थन सेवाओं की स्थिति को शामिल करते हुए एक परेशानी मुक्त परिचालन व्यवस्था प्रदान की जा सके। विशेष आर्थिक क्षेत्र (SEZ) एक विशेष रूप से निरूपित शुल्क मुक्त एन्क्लेव होते है तथा इसे व्यापार संचालन और टैरिफों और शुल्कों के प्रयोजनों हेतु विदेशी क्षेत्र माना जाता है।

विशेष आर्थिक क्षेत्रों के तहत क्षेत्र को शुल्कों और करों के उद्देश्य के लिए 'विदेशी क्षेत्र' के रूप में घोषित किया गया है। डीटीए से एसईजेड क्षेत्र में जाने वाली वस्तुओं और सेवाओं को निर्यात के रूप में माना जाएगा तथा एसटीजेड क्षेत्र से डीटीए में आने वाले सामानों को ऐसे माना जाएगा जैसे कि ये आयात किए जा रहे हैं।

Q.171) सामान्यीकृत वरीयता प्रणाली (Generalized System of Preferences- GSP) के बारे में, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें।

1. यह एक तरजीही टैरिफ प्रणाली है, जो विकसित देशों द्वारा विकासशील देशों (जिसे वरीयता प्राप्त देशों या लाभकारी देशों के रूप में भी जाना जाता है) के लिए विस्तारित किया जाता है।
2. इसमें GSP प्रदान करने वाले देशों के बाजारों में लाभार्थी देशों द्वारा निर्यात किए गए सभी उत्पादों के कम / शून्य टैरिफ शामिल होते हैं।
3. GSP लाभ को वापस लेने से, भारतीय निर्यात कम प्रतिस्पर्धी होकर प्रतिकूल रूप से प्रभावित होता है।

उपरोक्त कथनों में से कौन सा सही है / हैं?

a) केवल 1
b) केवल 1 और 3
c) केवल 2 और 3
d) केवल 1 और 2

Q.171) Solution (a)

कथन 1	कथन 2	कथन 3
सत्य	असत्य	सत्य
सामान्यीकृत वरीयता प्रणाली (GSP) एक तरजीही टैरिफ प्रणाली है जो विकसित देशों द्वारा विकासशील देशों (जिसे वरीयता प्राप्त देशों या लाभार्थी देशों के रूप में भी जाना जाता है) द्वारा विस्तारित किया जाता है। यह इस अर्थ में एक तरजीही व्यवस्था है कि यह विकासशील देशों से रियायती कम / शून्य शुल्क आयात की अनुमति देता है।	अमेरिका, यूरोपीय संघ, ब्रिटेन, जापान आदि सहित विकसित देश, विकासशील देशों से आयात करने के लिए जीएसपी देते हैं। जीएसपी में जीएसपी प्रदान करने वाले देशों के बाजारों में लाभार्थी देशों द्वारा निर्यात किए गए **पात्र उत्पादों** के कम / शून्य टैरिफ शामिल होते हैं।	"जीएसपी विश्व के कई सबसे गरीब देशों को अपनी अर्थव्यवस्थाओं को विकसित करने और गरीबी से बाहर निकलने के लिए व्यापार का उपयोग करने के अवसर प्रदान करता है" - USTR। भारत उन 94 उत्पादों के लगभग 50 उत्पादों का निर्यात करता है जिन पर जीएसपी लाभ रोक दिया गया है। जीएसपी हटाने से भारत पर एक उचित प्रभाव पड़ेगा क्योंकि देश ने 2017-18 में 48 बिलियन अमेरिकी डॉलर के कुल निर्यात में से जीएसपी मार्ग के तहत लगभग 5. 6 बिलियन अमेरिकी डॉलर के निर्यात पर तरजीही शुल्क का आनंद लिया है। जीएसपी लाभ को वापस लेने से भारत से निर्यात पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की आशंका है।

Q.172) ब्रिक्स कृषि अनुसंधान मंच (BRICS-ARP) की घोषणा, निम्नलिखित में से किस शिखर सम्मेलन के दौरान की गई थी?

a) रूस के ऊफ़ा में 7 वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2015
b) चीन के शियामेन में 9 वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2017
c) दक्षिण अफ्रीका के जोहान्सबर्ग में 10 वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2018
d) ब्राजील के ब्रासीलिया में 11 वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2019

Q.172) Solution (b)

रूस के ऊफ़ा में 9 वें जुलाई 2015 को आयोजित 7 वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के दौरान, भारतीय प्रधान मंत्री ने ब्रिक्स-कृषि अनुसंधान केंद्र की स्थापना का प्रस्ताव रखा, जो समग्र विश्व के लिए एक उपहार होगा। केंद्र ब्रिक्स सदस्य देशों में खाद्य सुरक्षा प्रदान करने के लिए कृषि में रणनीतिक सहयोग के माध्यम से सतत कृषि विकास और गरीबी उन्मूलन को बढ़ावा देगा।

ब्रिक्स देशों में कृषि अनुसंधान नीति, विज्ञान और प्रौद्योगिकी, नवाचार और क्षमता निर्माण में ब्रिक्स देशों के बीच सहयोग को और अधिक तीव्र करने के लिए छोटे जोत धारक किसानों के लिए प्रौद्योगिकियों सहित

कृषि अनुसंधान मंच की स्थापना पर, गोवा में 16 अक्टूबर, 2016 को आयोजित 8 वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में ब्रिक्स देशों के विदेश मंत्रियों द्वारा एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए।

ब्रिक्स-कृषि अनुसंधान केंद्र विशेष रूप से किसानों की और गैर-किसानों की आय के बीच, विश्व भूख, अल्प पोषण, गरीबी और असमानता, जैव सुरक्षा और जलवायु लचीला कृषि के मुद्दों के समाधान के लिए विज्ञान-आधारित कृषि-आधारित सतत विकास का प्राकृतिक वैश्विक मंच होगा।

Q.173) निम्नलिखित में से किस परिस्थिति में सरकार "सुरक्षा शुल्क" (safeguard duty) लगाती है?

a) जब एक निर्यातक देश की सरकार, अपने व्यापारी के उत्पादों को निर्यात सब्सिडी देती है
b) जब किसी विशेष निर्यातक देश पर आधारित न होकर, किसी विशेष उत्पाद के आयात में वृद्धि होती है
c) जब सामान एक देश द्वारा दूसरे देश को उसके सामान्य मूल्य से कम कीमत पर निर्यात किया जाता है
d) इनमें से कोई भी नहीं

Q.173) Solution (b)

जब कोई सरकार निर्यात सब्सिडी देती है तो इस तरह की सब्सिडी के प्रतिउत्तर में प्रतिकारी शुल्क (countervailing duty) लगाने के माध्यम से कार्रवाई की जाती है।

किसी विशेष देश पर आधारित न होकर किसी विशेष उत्पाद के आयात में वृद्धि होने पर सुरक्षा शुल्क (Safeguard duty) लागू किया जाता है।

डंपिंग (Dumping) तब कहा जाता है जब सामान किसी देश द्वारा दूसरे देश को उसके सामान्य मूल्य से कम कीमत पर निर्यात किया जाता है। यह एक अनुचित व्यापार अभ्यास है जो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार पर एक विकृत प्रभाव डाल सकता है। एंटी-डंपिंग माल की डंपिंग और उसके व्यापार के विकृत प्रभाव से उत्पन्न स्थिति को सुधारने के लिए एक उपाय है।

Q.174) "कृषि विकास के लिए अंतर्राष्ट्रीय कोष" (IFAD) के बारे में, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है?

1. यह विश्व बैंक समूह की एक विशेष एजेंसी है
2. यह विकासशील देशों में खाद्य उत्पादन पर केंद्रित है
3. यह विकासशील देशों में ग्रामीण गरीबी उन्मूलन पर केंद्रित है

सही कूट चुनें

a) केवल 1
b) केवल 2 और 3
c) केवल 3
d) केवल 1 और 2

Q.174) Solution (b)

कथन 1	कथन 2	कथन 3
असत्य	सत्य	सत्य

संयुक्त राष्ट्र की एक विशेष एजेंसी, कृषि विकास के लिए अंतर्राष्ट्रीय कोष (IFAD) को एक प्रमुख के रूप में 1977 में एक अंतरराष्ट्रीय वित्तीय संस्थान के रूप में स्थापित किया गया था, जो 1974 के विश्व खाद्य सम्मेलन का परिणाम है। यह सम्मेलन 1970 के दशक की शुरुआत में खाद्य संकट के जवाब में आयोजित किया गया था, जो मुख्य रूप से अफ्रीका के साहिली देशों को प्रभावित किया था।	इसने यह संकल्प किया कि "कृषि विकास के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय कोष, कृषि विकास परियोजनाओं को विकसित करने के लिए मुख्य रूप से विकासशील देशों में खाद्य उत्पादन के लिए स्थापित किया जाना चाहिए।"	कम ब्याज ऋण और अनुदान के माध्यम से, आईएफएडी सरकारों के साथ मिलकर विकास और वित्त कार्यक्रमों और परियोजनाओं को विकसित करता है जो ग्रामीण गरीब लोगों को गरीबी से उबरने में सक्षम बनाते हैं।

Q.175) शंघाई सहयोग संगठन (SCO) के बारे में, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें।

1. यह चीन के नेतृत्व में एक सैन्य और सुरक्षा गठबंधन है
2. हाल ही में, भारत और पाकिस्तान पर्यवेक्षक राज्यों के रूप में SCO में शामिल हुए हैं
3. 19 वीं SCO की बैठक किर्गिस्तान के बिश्केक में हुई थी।

उपरोक्त कथन में से कौन सा सही है / हैं?

a) केवल 1 और 2
b) केवल 2 और 3
c) केवल 2
d) केवल 3

Q.175) Solution (d)

कथन 1	**कथन 2**	**कथन 3**
असत्य	**असत्य**	**सत्य**
शंघाई सहयोग संगठन (SCO) या शंघाई पैक्ट एक यूरेशियाई राजनीतिक, आर्थिक और सुरक्षा गठबंधन है, जिसके निर्माण की घोषणा 15 जून 2001 को शंघाई, चीन में चीन, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, रूस, ताजिकिस्तान , और उजबेकिस्तान के नेताओं द्वारा की गई थी। औपचारिक रूप से संगठन की स्थापना करने वाले शंघाई सहयोग संगठन चार्टर को जून 2002 में हस्ताक्षरित किया गया और 19 सितंबर 2003 को लागू हुआ।	मूल पाँच राष्ट्र, उज्बेकिस्तान के बाहर निकलने के साथ, पहले शंघाई पाँच समूह के सदस्य थे, जिसकी स्थापना 26 अप्रैल 1996 को हुई थी। तब से, संगठन ने आठ देशों में अपनी सदस्यता का विस्तार किया है, जब 9 जून 2017 कजाखस्तान के अस्ताना में एक शिखर सम्मेलन में भारत और पाकिस्तान एससीओ में पूर्ण सदस्य के रूप में शामिल हुए थे। स्टेट काउंसिल के प्रमुख (HSC) SCO में सर्वोच्च निर्णय लेने वाली संस्था है, यह वर्ष में एक बार बैठक करती	19 वीं एससीओ की बैठक किर्गिस्तान के बिश्केक में हुई थी। यह दूसरी बार था जब भारत ने पूर्ण सदस्य के रूप में भाग लिया था। बैठक आर्थिक मामलों में और आतंकवाद का मुकाबला करने में सहयोग बढ़ाने के तरीकों पर केंद्रित थी।

	है तथा संगठन के सभी महत्वपूर्ण मामलों पर निर्णय और दिशानिर्देश अपनाती है।	

Q.176) विश्व बैंक द्वारा निम्नलिखित में से कौन सी रिपोर्ट प्रकाशित नहीं की जाती है?

1. विश्व विकास रिपोर्ट
2. ईज़ ऑफ़ लिविंग इंडेक्स
3. सार्वभौमिक स्वास्थ्य कवरेज सूचकांक
4. प्रेषण रिपोर्ट

सही कूट चुनें

a) केवल 2 और 4
b) केवल 4
c) केवल 1 और 3
d) इनमें से कोई भी नहीं

Q.176) Solution (d)

विश्व बैंक की रिपोर्ट

1. व्यापार करने में आसानी रिपोर्ट
2. विश्व विकास रिपोर्ट
3. ईज़ ऑफ़ लिविंग इंडेक्स
4. सार्वभौमिक स्वास्थ्य कवरेज सूचकांक
5. प्रेषण रिपोर्ट
6. वैश्विक आर्थिक संभावनाएं- विश्व बैंक समूह

Q.177) विश्व सीमा शुल्क संगठन (WCO) के संबंध में, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें।

1. यह सीमा शुल्क प्रशासन की प्रभावशीलता और दक्षता को बढ़ाने के लिए एक संयुक्त राष्ट्र निकाय है
2. इसका मुख्यालय ब्रुसेल्स, बेल्जियम में है
3. यह सीमा शुल्क के मामलों में सक्षमता वाला एकमात्र अंतर्राष्ट्रीय संगठन है

उपरोक्त कथनों में से कौन सा सही है / हैं?

a) केवल 1 और 2
b) केवल 2 और 3
c) केवल 1 और 3
d) उपरोक्त सभी

Q.177) Solution (b)

कथन 1	कथन 2	कथन 3
असत्य	सत्य	सत्य
सीमा शुल्क सहयोग परिषद (CCC) के रूप में 1952 में स्थापित विश्व सीमा शुल्क संगठन	इसका मुख्यालय ब्रुसेल्स, बेल्जियम में है। डब्ल्यूसीओ ने अपनी सदस्यता को	सीमा शुल्क विशेषज्ञता के वैश्विक केंद्र के रूप में, WCO सीमा शुल्क के मामलों में सक्षमता के साथ

(WCO) एक स्वतंत्र अंतर सरकारी निकाय है जिसका उद्देश्य सीमा शुल्क प्रशासन की प्रभावशीलता और दक्षता को बढ़ाना है।	छह क्षेत्रों में विभाजित किया है। छह क्षेत्रों में से प्रत्येक को WCO परिषद के एक क्षेत्रीय रूप से चुने गए उपाध्यक्ष द्वारा प्रतिनिधित्व किया जाता है। भारत जुलाई, 2018 से जून, 2020 तक, दो वर्षों की अवधि के लिए विश्व सीमा शुल्क संगठन (डब्ल्यूसीओ) के एशिया प्रशांत क्षेत्र का उपाध्यक्ष (क्षेत्रीय प्रमुख) बन गया है।	एकमात्र अंतर्राष्ट्रीय संगठन है तथा स्वयं को अंतरराष्ट्रीय सीमा शुल्क समुदाय की आवाज के रूप में वर्णित कर सकता है। डब्ल्यूसीओ विश्व भर में 182 सीमा शुल्क प्रशासन का प्रतिनिधित्व करता है जो सामूहिक रूप से लगभग 98% विश्व व्यापार की प्रक्रिया करता है

Q.178) अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के बारे में, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें

1. यह 1919 के बाद से एकमात्र त्रिपक्षीय यूएन एजेंसी है, जो 187 सदस्य राष्ट्रों की सरकारों, नियोक्ताओं और श्रमिकों को एक साथ लाती है।
2. ILO 1946 में UN की पहली विशिष्ट एजेंसी बन गई थी।
3. अंतर्राष्ट्रीय श्रम सम्मेलन का शताब्दी सत्र नीदरलैंड के हेग में आयोजित हुआ था।

उपरोक्त कथनों में से कौन सा गलत है / हैं?

a) केवल 1 और 2
b) केवल 2 और 3
c) केवल 1 और 3
d) केवल 3

Q.178) Solution (d)

कथन 1	कथन 2	कथन 3
सत्य	सत्य	असत्य
एकमात्र त्रिपक्षीय संयुक्त राष्ट्र एजेंसी, 1919 के बाद से ILO 187 सदस्य राष्ट्रों की सरकारों, नियोक्ताओं और श्रमिकों को एक साथ लाता है, श्रम मानकों को निर्धारित करने, नीतियों को विकसित करने तथा सभी महिलाओं और पुरुषों के लिए सभ्य काम को बढ़ावा देने वाले कार्यक्रमों का विकास करता है। ILO की अद्वितीय त्रिपक्षीय संरचना श्रमिकों, नियोक्ताओं और सरकारों को एक समान आवाज देती है ताकि यह सुनिश्चित किया	ILO की स्थापना 1919 में एक विनाशकारी युद्ध के मद्देनजर की गई थी, जो इस आधार पर एक दृष्टि को आगे बढ़ाने के लिए थी कि सार्वभौमिक, स्थायी शांति की स्थापना तभी की जा सकती है, जब वह सामाजिक न्याय पर आधारित हो। ILO 1946 में UN की पहली विशिष्ट एजेंसी बन गई थी।	अंतर्राष्ट्रीय श्रम सम्मेलन का 108 वां (शताब्दी) सत्र 10 -21 जून 2019 के बीच जिनेवा, स्विट्जरलैंड में हुआ। इस सम्मेलन में भविष्य के कार्य, 2019 के लिए ILO शताब्दी घोषणा को अपनाया गया।

जा सके कि सामाजिक साझेदारों के विचार श्रम मानकों और नीतियों तथा कार्यक्रमों को आकार देने में पारस्परिकता दिखाई दे।		

Q.179) विश्व बैंक एक अंतरराष्ट्रीय वित्तीय संस्थान है जो विश्व के देशों को पूंजी परियोजनाओं के लिए ऋण प्रदान करता है। निम्नलिखित में से कौन सी संस्था इसकी अंग हैं?

1. पुनर्निर्माण और विकास के लिए अंतर्राष्ट्रीय बैंक (IBRD)
2. अंतर्राष्ट्रीय विकास संघ (IDA)
3. अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम (IFC)
4. बहुपक्षीय निवेश गारंटी एजेंसी (MIGA)
5. निवेश विवादों के निपटारे के लिए अंतर्राष्ट्रीय केंद्र (ICSID)

सही कूट चुनें

a) केवल 1 और 2
b) केवल 1, 2, 3 और 4
c) केवल 1 और 3
d) उपरोक्त सभी

Q.179) Solution (a)

विश्व बैंक एक अंतरराष्ट्रीय वित्तीय संस्थान है जो विश्व के देशों को पूंजी परियोजनाओं के लिए ऋण प्रदान करता है। इसमें **दो संस्थान शामिल हैं: पुनर्निर्माण और विकास के लिए अंतर्राष्ट्रीय बैंक (IBRD), और अंतर्राष्ट्रीय विकास संघ (IDA)**। विश्व बैंक, विश्व बैंक समूह का एक घटक है।

विश्व बैंक का हालिया घोषित लक्ष्य गरीबी में कमी करना है। नवंबर 2018 तक, IBRD से ऋण के माध्यम से विश्व बैंक ऋणों के सबसे बड़े प्राप्तकर्ता भारत (2018 में 859 मिलियन डॉलर) और चीन (2018 में $ 370 मिलियन) थे।

विश्व बैंक समूह (WBG) पाँच अंतर्राष्ट्रीय संगठनों का एक परिवार है जो विकासशील देशों के लिए ऋण प्रदान करता है। यह विश्व का सबसे बड़ा और सबसे प्रसिद्ध विकास बैंक है तथा संयुक्त राष्ट्र विकास समूह में एक पर्यवेक्षक है। बैंक वाशिंगटन, डीसी में स्थित है। बैंक का घोषित मिशन चरम गरीबी को समाप्त करने और साझा समृद्धि के दोहरे लक्ष्यों को प्राप्त करना है।

इसके पांच संगठन पुनर्निर्माण और विकास के लिए अंतर्राष्ट्रीय बैंक (IBRD), अंतर्राष्ट्रीय विकास संघ (IDA), अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम (IFC), बहुपक्षीय निवेश गारंटी एजेंसी (MIGA) और निवेश विवादों के निपटारे के लिए अंतर्राष्ट्रीय केंद्र (ICSID) हैं।

Q.180) निम्नलिखित में से कौन सा संगठन, यात्रा और पर्यटन प्रतिस्पर्धात्मकता रिपोर्ट प्रकाशित करता है?

a) विश्व आर्थिक मंच
b) यूनेस्को
c) संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम
d) संयुक्त राष्ट्र विश्व पर्यटन संगठन

Q.180) Solution (a)

विश्व आर्थिक मंच ने पिछले 11 वर्षों से, विश्व भर में 136 अर्थव्यवस्थाओं की यात्रा और पर्यटन प्रतिस्पर्धा का गहन विश्लेषण करने के लिए यात्रा और पर्यटन में संलग्न नेतृत्वों को शामिल किया है। यात्रा और पर्यटन प्रतिस्पर्धात्मकता सूचकांक "यात्रा और पर्यटन क्षेत्र के सतत विकास को सक्षम करने वाले कारकों और नीतियों के सेट को मापता है, जो बदले में, किसी देश के विकास और प्रतिस्पर्धा में योगदान देता है"। यात्रा और पर्यटन प्रतिस्पर्धात्मकता सूचकांक सभी हितधारकों को अपनी राष्ट्रीय अर्थव्यवस्थाओं में उद्योग की प्रतिस्पर्धा में सुधार करने के लिए एक साथ काम करने में सक्षम बनाता है। 2017 के संस्करण का विषय "अधिक सतत और समावेशी भविष्य के लिए मार्ग बनाना" है, जो प्राकृतिक पर्यावरण और स्थानीय समुदायों को संरक्षित करते हुए एक अनिश्चित सुरक्षा वातावरण में उद्योग के निरंतर विकास को सुनिश्चित करने पर बढ़ते फोकस को दर्शाता है, जिस पर यह बहुत अधिक निर्भर करता है।

Q.181) एक तरलता जाल (Liquidity Trap) निम्नलिखित में से किन परिस्थितियों में घटित हो सकता है?

1. मुद्रास्फीति की अपेक्षा।
2. बांड्स धारण करने की अनिच्छा।
3. बचत के लिए वरीयता।

नीचे दिए गए कूट का उपयोग करके सही उत्तर चुनें

a) केवल 1
b) केवल 1 और 3
c) केवल 2 और 3
d) उपरोक्त सभी

Q.181) Solution (c)

विकल्प 1	विकल्प 2	विकल्प 3
असत्य	सत्य	सत्य
अपस्फीति (deflation) की आशंका होने पर तरलता जाल की घटना हो सकती है। यदि अपस्फीति है या लोग अपस्फीति (कीमतों में गिरावट) की उम्मीद करते हैं तो वास्तविक ब्याज दरें काफी अधिक हो सकती हैं, भले ही नॉमिनल ब्याज दरें शून्य हों। - यदि कीमतें प्रति वर्ष 2% गिर रही हैं, तो नकदी रखने का अर्थ है कि आपके पैसे के मूल्य में वृद्धि होगी।	बांड रखने की अनिच्छा - यदि ब्याज दरें शून्य होती हैं, तो निवेशक कुछ समय में ब्याज दरों में वृद्धि की उम्मीद करेंगे। यदि ब्याज दरें बढ़ती हैं, तो बांड की कीमत गिर जाएंगी। इसलिए, निवेशक बॉन्ड रखने के बजाय नकद बचत रखेंगे।	तरलता जाल मंदी की अवधि और एक उदास आर्थिक दृष्टिकोण के दौरान घटित होता है। उपभोक्ता, फर्म और बैंक भविष्य के बारे में निराशावादी होते हैं, इसलिए वे अपनी एहतियाती बचत को बढ़ाने के लिए देखते हैं तथा उन्हें व्यय करना मुश्किल होता है, जो कि मांग बनाने के लिए आवश्यक है ताकि अर्थव्यवस्था एक बार फिर से जीवित हो सके। बचत अनुपात में इस वृद्धि का अर्थ व्यय में गिरावट है।

Q.182) राजकोषीय घाटे के प्रत्यक्ष मुद्रीकरण (direct monetization of fiscal deficit) के बारे में, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें

1. प्रत्यक्ष मुद्रीकरण एक लॉकडाउन जैसी घटनाओं के कारण होने वाली सकारात्मक मांग झटके की स्थिति में उपयुक्त होता है।
2. इसमें, सरकार RBI को अपने घाटे का वित्तपोषण करने के लिए नई मुद्रा मुद्रित करने के लिए कहती है।
3. यह मुद्रास्फीति में वृद्धि का कारण बन सकता है।

ऊपर दिए गए कथनों में से कौन सा सही है / हैं?

a) केवल 1 और 2
b) केवल 2 और 3
c) केवल 2
d) उपरोक्त सभी

Q.182) Solution (b)

विकल्प 1	विकल्प 2	विकल्प 3
असत्य	**सत्य**	**सत्य**
प्रत्यक्ष मुद्रीकरण एक **नकारात्मक मांग** की स्थिति में उपयुक्त होता है जो लॉकडाउन जैसी घटनाओं के कारण होता है। यह उपकरण सरकार के लिए उस समय समग्र मांग को बढ़ावा देने का अवसर प्रदान करता है जब निजी मांग में गिरावट आई हो।	घाटे के प्रत्यक्ष मुद्रीकरण में, सरकार सीधे आरबीआई के साथ व्यवहार करती है। यह RBI को नए बांडों के बदले नई मुद्रा छापने के लिए कहती है जो सरकार RBI को देती है।	नए धन का उपयोग सरकारी व्यय में वृद्धि करता है तथा अर्थव्यवस्था में निजी मांग को बढ़ाता है। इस प्रकार, यह मुद्रास्फीति को बढ़ावा देता है।

Q.183) मुद्रास्फीति से निपटने के लिए, निम्नलिखित में से कौन सा राजकोषीय उपाय हैं?

1. उधार नियंत्रण
2. कर में वृद्धि
3. अनावश्यक व्यय में कमी

नीचे दिए गए कूट का उपयोग करके सही उत्तर चुनें

a) केवल 1 और 2
b) केवल 1 और 3
c) केवल 2 और 3
d) उपरोक्त सभी

Q.183) Solution (c)

मुद्रास्फीति को मुकाबला करने के लिए राजकोषीय उपाय

- कर में वृद्धि।
- अनावश्यक व्यय में कमी।
- बचत में वृद्धि।
- अधिशेष बजट।

- सार्वजनिक ऋण।

मुद्रास्फीति को कम करने के लिए मौद्रिक उपाय

- उधार नियंत्रण।
- मुद्रा का विमुद्रीकरण।
- नई मुद्रा जारी करना।

अन्य उपाय

- उत्पादन में वृद्धि करना।
- तर्कसंगत वेतन नीति।
- मूल्य नियंत्रण।
- नियंत्रित वितरण (Rationing)।

Q.184) तरीके और साधन अग्रिम (Ways and Means Advances) के बारे में, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें

1. यह एक प्रकार का दीर्घकालिक ऋण है जिसे सरकार केंद्रीय बैंक से उधार ले सकती है।
2. यह सरकार के राजकोषीय घाटे के वित्तपोषण का एक स्रोत है।

ऊपर दिए गए कथनों में से कौन सा सही है / हैं?

a) केवल 1
b) केवल 2
c) 1 और 2 दोनों
d) न तो 1 और न ही 2

Q.184) Solution (d)

विकल्प 1	विकल्प 2
असत्य	असत्य
तरीके और साधन अग्रिम (WMAs), आरबीआई द्वारा सरकार को प्रदान की गई अस्थायी ऋण सुविधाएं हैं, जो इसे राजस्व और व्यय के बीच अस्थायी असंतुलन को पूरा करने में सक्षम बनाती हैं। इन निधियों की उपलब्धता से अल्पकालिक व्यय करने के लिए कुछ जगह मिलेगी।	तरीके और साधन अग्रिम वित्तीय घाटे के वित्तपोषण का एक स्रोत नहीं है। समझौते के अनुसार, अर्थोपाय अग्रिम (WMAs) दिए जाने की तारीख से तीन महीने के भीतर पूरी तरह से भुगतान किया जाएगा।

Q.185) FRBM अधिनियम के तहत पलायन खंड प्रावधान (escape clause provision under the FRBM Act) के बारे में, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें

1. सरकार द्वारा किए गए संरचनात्मक सुधारों के कारण, 2019-20 के लिए राजकोषीय घाटे के लक्ष्य से सरकार विचलित हो गयी है।
2. वर्तमान कोरोनावायरस महामारी वार्षिक राजकोषीय घाटे के लक्ष्य को पूरा नहीं कर पाने के लिए एक वैध आधार है।

ऊपर दिए गए कथनों में से कौन सा सही है / हैं?

a) केवल 1
b) केवल 2
c) 1 और 2 दोनों
d) न तो 1 और न ही 2

Q.185) Solution (c)

विकल्प 1	विकल्प 2
सत्य	**सत्य**
सरकार के अनुसार, 2019-20 के लिए राजकोषीय घाटे के लक्ष्य को जीडीपी के 3.3 प्रतिशत के बजटीय लक्ष्य की तुलना में जीडीपी के 3.8 प्रतिशत पर पुनर्गठित किया गया है। सरकार द्वारा लिए गए निगम कर में कटौती जैसे संरचनात्मक सुधारों के कारण विचलन आवश्यक हो गया है।	कोरोनावायरस महामारी को राष्ट्रीय आपदा माना जा सकता है। इसलिए यह वार्षिक राजकोषीय घाटे के लक्ष्य को पूरा नहीं कर पाने के लिए एक वैध आधार है। पहले से ही केरल जैसे कई राज्यों ने मौजूदा स्थिति के कारण FRBM लक्ष्य पर छूट मांगी है।

FRMB अधिनियम के तहत पलायन खंड

- FRBM अधिनियम के तहत राजकोषीय घाटे के लक्ष्य से ऊपर जाने के रियायती प्रावधान लोकप्रिय रूप से पलायन खंड (escape clause) के रूप में जाने जाते हैं।
- अधिनियम की उप-धारा 4 (2) विभिन्न आधारों के बारे में कहती है, जिन पर FRBM के राजकोषीय घाटे के लक्ष्य को किसी वर्ष के दौरान छूट दी जा सकती है -
    - राष्ट्रीय सुरक्षा, युद्ध का एक कार्य।
    - राष्ट्रीय आपदा।
    - कृषि का पतन जिससे कृषि उत्पादन और आय गंभीर रूप से प्रभावित होती है।
    - अप्रत्याशित राजकोषीय निहितार्थ के साथ अर्थव्यवस्था में संरचनात्मक सुधार।
    - पिछली चार तिमाहियों के औसत से कम से कम तीन प्रतिशत अंकों की वृद्धि से एक तिमाही के वास्तविक उत्पादन वृद्धि में गिरावट।

Q.186) अक्षय ऊर्जा प्रमाणपत्र (Renewable Energy Certificates- REC) के बारे में, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें।

1. एक आरईसी तब प्रदान किया जाता है, जब एक पात्र अक्षय ऊर्जा स्रोत से एक मेगावाट बिजली उत्पन्न होती है।
2. यहां तक कि, छत के सौर पैनलों वाले गृहस्वामी भी आरईसी प्राप्त करने के लिए पात्र हैं।
3. आरईसी की कीमत केंद्रीय विद्युत नियामक आयोग द्वारा तय की जाती है।

ऊपर दिए गए कथनों में से कौन सा सही है / हैं?

a) केवल 1 और 2
b) केवल 1 और 3
c) केवल 1
d) उपरोक्त सभी

Q.186) Solution (a)

विकल्प 1	विकल्प 2	विकल्प 3
सत्य	**सत्य**	**असत्य**
अक्षय ऊर्जा प्रमाणपत्र (RECs) एक बाजार आधारित उपकरण है जो वाहक को प्रमाणित करता है, जो अक्षय ऊर्जा संसाधन से उत्पन्न एक मेगावाट-घंटे (MWh) बिजली उत्पादित करता है। एक बार जब बिजली प्रदाता, ऊर्जा को ग्रिड में फीड कर देता है, तो आरईसी प्राप्त ऊर्जा के रूप में खुले बाजार में बेची जा सकती है।	नवीकरणीय बिजली का प्रदाता, जिसमें छत के सौर पैनलों वाले गृहस्वामी आरईसी प्राप्त करने के पात्र हैं।	अक्षय ऊर्जा प्रमाणपत्र (RECs) एक बाजार आधारित उपकरण है। आपूर्ति और मांग के कारण कीमत भिन्न हो सकती है। हालांकि, वे केंद्रीय विद्युत नियामक आयोग (CERC) द्वारा निर्दिष्ट 'floor price' (न्यूनतम मूल्य) और 'forbearance price' (अधिकतम मूल्य) के बीच समाहित होती हैं।

- REC सौर, पवन और अन्य हरित ऊर्जा के लिए एक ट्रैकिंग तंत्र के रूप में कार्य करता है क्योंकि वे पावर ग्रिड में प्रवाहित होते हैं।
- REC कई नामों से जाते हैं, जिनमें ग्रीन टैग, ट्रेडेबल रिन्यूएबल सर्टिफिकेट (टीआरसी), रिन्यूएबल इलेक्ट्रिसिटी सर्टिफिकेट या रिन्यूएबल एनर्जी क्रेडिट शामिल हैं।
- भारत में, REC का कारोबार दो पावर एक्सचेंजों- Indian Energy Exchange (IEX) और पावर एक्सचेंज ऑफ़ इंडिया (PXIL) पर किया जाता है।

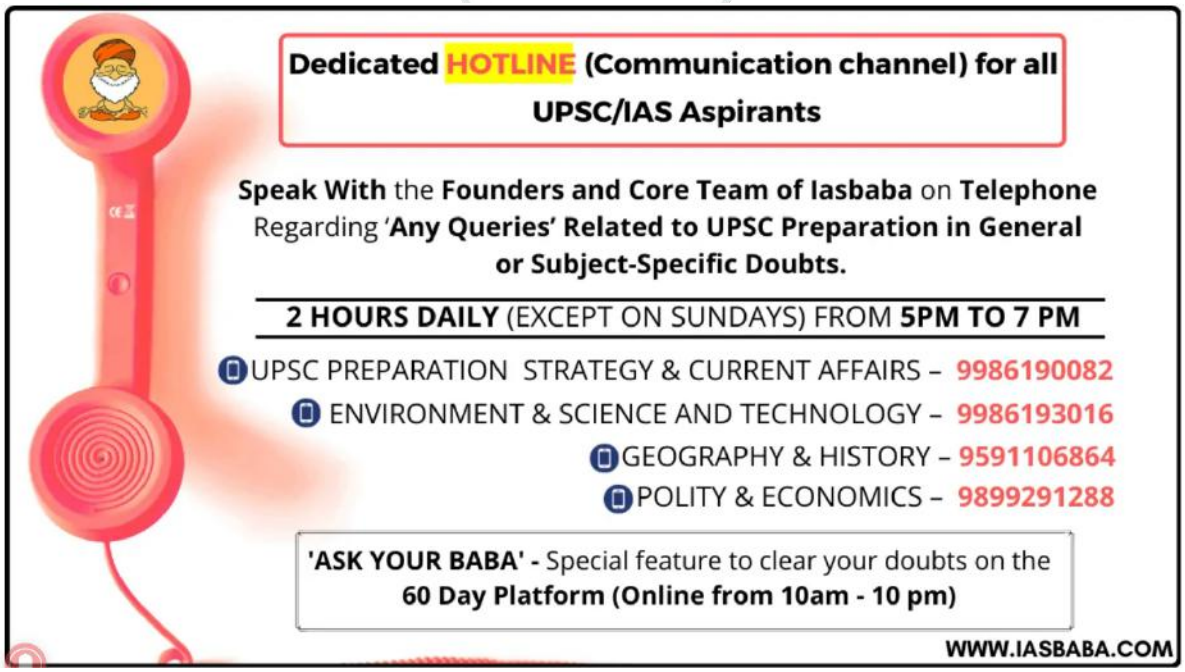

Q.187) RBI द्वारा आयोजित विदेशी मुद्रा विनिमय नीलामी (Foreign exchange swap auction) के बारे में, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें

1. इसका उद्देश्य विदेशी मुद्रा विनिमय बाजार में अस्थिरता को कम करना था।
2. यह प्रणाली में बढ़ती तरलता का प्रभाव है।

ऊपर दिए गए कथनों में से कौन सा सही है / हैं?

a) केवल 1
b) केवल 2
c) 1 और 2 दोनों
d) न तो 1 और न ही 2

Q.187) Solution (b)

विकल्प 1	विकल्प 2
असत्य	**सत्य**
विदेशी मुद्रा विनिमय का उद्देश्य प्रणाली की टिकाऊ तरलता आवश्यकताओं को पूरा करना है।	विनिमय लंबी अवधि के लिए विदेशी मुद्रा खरीदने / बेचने के माध्यम से लंबी अवधि के लिए रुपये की तरलता को इंजेक्ट करता है। विदेशी मुद्रा विनिमय अनिवार्य रूप से बैंकों के हाथों में अधिक पैसा डालता है।

विदेशी मुद्रा विनिमय नीलामी (Forex swap auction)

- आरबीआई ने 3 साल के लिए बैंकों के साथ विदेशी मुद्रा विनिमय नीलामी के माध्यम से प्रणाली में दीर्घकालिक तरलता का समामेलन (injected) किया है।
- विनिमय के तहत, एक बैंक RBI को अमेरिकी डॉलर बेचेगा। यह उसी समय (simultaneously) विनिमय अवधि के अंत में अमेरिकी डॉलर की समान राशि खरीदने के लिए सहमत होगा।
- विनिमय लेनदेन ओएमओ (खुले बाजार के संचालन) से भौतिक रूप से भिन्न होता है जिसमें आरबीआई खुले बाजार में सरकारी प्रतिभूतियों को खरीदता है और बेचता है।

Q.188) दीर्घ आवधिक रेपो संचालन (Long Term Repo Operation- LTRO) के बारे में, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें।

1. LTRO के माध्यम से उधार ली गई निधि पर, बैंक दर से उधार ली गई निधि से कम ब्याज दर होती है।
2. LTRO सुविधा का लाभ उठाने के लिए केवल सरकारी प्रतिभूतियों को संपार्श्विक (collateral) के रूप में स्वीकार किया जाएगा।
3. LTRO कॉर्पोरेट बॉन्ड में निवेश को बढ़ावा देगा।

ऊपर दिए गए कथनों में से कौन सा सही है / हैं?

a) केवल 1
b) केवल 1 और 2
c) केवल 2 और 3
d) उपरोक्त सभी

Q.188) Solution (d)

विकल्प 1	विकल्प 2	विकल्प 3

सत्य	सत्य	सत्य
आमतौर पर, रेपो दर बैंक दर से कम होती है। वर्तमान रेपो दर 4.40% है जबकि बैंक दर 4.65% है।	LTRO एक ऐसा उपकरण है जिसके तहत केंद्रीय बैंक प्रचलित रेपो दर पर बैंकों को एक साल से तीन साल का पैसा मुहैया कराता है, जो सरकारी प्रतिभूतियों को संपार्श्विक के रूप में मिलान या उच्चतर कार्यकाल के साथ स्वीकार करता है।	LTRO से अल्पकालिक दरों को कम करने और कॉर्पोरेट बॉन्ड में निवेश को बढ़ावा देने की उम्मीद होती है

Q.189) सरकार ने हाल ही में आवश्यक वस्तु अधिनियम (ECA) के दायरे में हैंड सैनिटाइजर और मास्क लाए हैं। आवश्यक वस्तु अधिनियम के बारे में निम्नलिखित कथन पर विचार करें

1. अधिनियम राज्य सरकारों को भी कुछ वस्तुओं के उत्पादन, आपूर्ति और वितरण को नियंत्रित करने का अधिकार देता है।
2. औषधि मूल्य नियंत्रण आदेश (DPCO), ECA की शक्तियों के तहत जारी किया जाता है।

ऊपर दिए गए कथनों में से कौन सा सही है / हैं?

a) केवल 1
b) केवल 2
c) 1 और 2 दोनों
d) न तो 1 और न ही 2

Q.189) Solution (c)

विकल्प 1	विकल्प 2
सत्य	सत्य
अधिनियम ECA में सूचीबद्ध कुछ वस्तुओं के उत्पादन, आपूर्ति और वितरण को नियंत्रित करने के लिए केंद्र और राज्य सरकारों को समवर्ती रूप से सशक्त बनाता है। अधिनियम के प्रावधान के तहत जो उपाय किए जा सकते हैं, उनमें लाइसेंसिंग, वितरण और स्टॉक, अन्य सीमाएं शामिल हैं।	औषधि मूल्य नियंत्रण आदेश, 1995 दवाओं की कीमतों को विनियमित करने के लिए आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 की धारा 3 के तहत भारत सरकार द्वारा जारी एक आदेश है। DPCO के प्रावधानों को लागू करने के लिए, सरकार की शक्तियाँ एनपीपीए (राष्ट्रीय औषधि मूल्य निर्धारण प्राधिकरण) में निहित है।

Q.190) कृषि क्षेत्र में हाल के घटनाक्रमों के बारे में, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें

1. एक किसान उत्पादक संगठन कंपनी अधिनियम 2013 के तहत पंजीकृत एक कानूनी संस्था है।
2. पशुधन, मुर्गीपालन और मत्स्य पालन को मॉडल अनुबंध खेती अधिनियम 2018 के दायरे में शामिल किया गया है।
3. हाल ही में, तमिलनाडु अनुबंध खेती पर एक कानून बनाने वाला पहला राज्य बना है।

ऊपर दिए गए कथनों में से कौन सा सही है / हैं?

a) केवल 1 और 2

b) केवल 1 और 3
c) केवल 2 और 3
d) उपरोक्त सभी

Q.190) Solution (c)

विकल्प 1	विकल्प 2	विकल्प 3
असत्य	**सत्य**	**सत्य**
एक उत्पादक संगठन (PO) एक कानूनी संस्था है जिसका गठन प्राथमिक उत्पादकों किसान, दूध उत्पादक, मछुआरे, बुनकर, ग्रामीण कारीगर, शिल्पकार आदि द्वारा किया जाता है। संस्था को सहकारी समितियों अधिनियम के तहत सहकारी समिति के रूप में पंजीकृत किया जा सकता है या कंपनी अधिनियम के तहत उत्पादक कंपनी के रूप में पंजीकृत किया जा सकता है।	मॉडल अनुबंध कृषि अधिनियम 2018 में कृषि और बागवानी फसलों, पशुधन, डेयरी, पोल्ट्री और मत्स्य पालन की सभी श्रेणियां शामिल हैं।	हाल ही में, तमिलनाडु अनुबंध खेती पर एक कानून बनाने वाला पहला राज्य बना है।

Q.191) नामकरण के हार्मोनाइज्ड सिस्टम (Harmonized System of Nomenclature- HSN) के बारे में, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें।

1. यह एक बहुउद्देशीय अंतर्राष्ट्रीय उत्पाद नामकरण है जिसे विश्व सीमा शुल्क संगठन द्वारा विकसित किया गया है।
2. माल-भाड़ा टैरिफ (freight tariffs) जैसे उद्देश्यों के लिए निजी क्षेत्र की फर्मों द्वारा कोड का उपयोग किया जाता है।
3. भारत ने हाल ही में, सीमा शुल्क के प्रयोजनों के लिए माल के वर्गीकरण हेतु HSN का पालन करने का निर्णय किया है।

ऊपर दिए गए कथनों में से कौन सा सही है / हैं?

a) केवल 1 और 2
b) केवल 2
c) केवल 1 और 3
d) उपरोक्त सभी

Q.191) Solution (a)

विकल्प 1	विकल्प 2	विकल्प 3
सत्य	**सत्य**	**असत्य**
यह एक बहुउद्देशीय अंतर्राष्ट्रीय	इसका उपयोग न केवल सरकारों	भारत ने एक दशक से अधिक

उत्पाद नामकरण है जिसे विश्व सीमा शुल्क संगठन द्वारा विकसित किया गया है। यह वस्तु के प्रकार का वर्णन करने के लिए विश्व भर में सामान्य मानक है	और अंतर्राष्ट्रीय संगठनों द्वारा किया जाता है, बल्कि निजी क्षेत्रों द्वारा कई अन्य उद्देश्यों जैसे आंतरिक करों, माल भाड़े के शुल्क, परिवहन सांख्यिकी, अनुसंधान और विश्लेषण के लिए भी किया जाता है।	समय से सीमा शुल्क के प्रयोजनों के लिए माल के वर्गीकरण के लिए एचएसएन का पालन किया है। हाल ही में, सरकार ने HSN कोड के बिना आयात की अनुमति नहीं देने का निर्णय किया है।

Q.192) प्रतिभूतिकरण (Securitization) शब्द कभी-कभी समाचारों में देखा जाता है। यह निम्न में से किसको संदर्भित करता है

a) राजकोषीय घाटे के वित्तपोषण के लिए सरकारी प्रतिभूति जारी करना।
b) समेकित वित्तीय साधन में वित्तीय परिसंपत्तियों की पूलिंग।
c) डिफ़ॉल्ट की अपेक्षा के कारण सरकारी प्रतिभूति रखने की अनिच्छा।
d) गैर-निष्पादित परिसंपत्ति मुद्दे को कम करने के लिए असुरक्षित ऋण से सुरक्षित ऋण में रूपांतरण।

Q.192) Solution (b)

प्रतिभूतिकरण (Securitization)

- प्रतिभूतिकरण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा एक कंपनी एक समेकित वित्तीय साधन बनाने के लिए विभिन्न वित्तीय परिसंपत्तियों / ऋणों को जमा करती है जो निवेशकों को जारी किया जाता है।
- यह फर्म को पूंजी जुटाने में सक्षम बनाता है तथा इस प्रकार बाजार में तरलता को बढ़ाता है।
- प्रतिभूतिकरण में बिक्री योग्य प्रतिभूतियों में कम तरल संपत्तियों का पुन:स्थापन शामिल होता है।

Q.193) भारत ने हाल ही में, कर संधि से संबंधित उपायों (MLI) को लागू करने के लिए बहुपक्षीय कन्वेंशन की पुष्टि की है। इसके बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें।

1. MLI आधार क्षरण और लाभ हस्तांतरण तथा धन शोधन से निपटने के लिए OECD और FATF प्रोजेक्ट का एक परिणाम है।
2. MLI "आरक्षण" जैसे प्रावधानों के माध्यम से लचीलापन प्रदान करता है
3. MLI हस्ताक्षरकर्ता देशों के बीच किसी भी मौजूदा द्विपक्षीय कर संधि समझौतों को संशोधित नहीं करता है।

ऊपर दिए गए कथनों में से कौन सा गलत है / हैं?

a) केवल 1 और 2
b) केवल 1 और 3
c) केवल 2 और 3
d) उपरोक्त सभी

Q.193) Solution (b)

विकल्प 1	विकल्प 2	विकल्प 3
असत्य	सत्य	असत्य

बहुपक्षीय कन्वेंशन आधार क्षरण और लाभ हस्तांतरण से निपटने के लिए OECD/G20 परियोजना का एक परिणाम है।	MLI "आरक्षण" जैसे प्रावधानों के माध्यम से लचीलापन प्रदान करता है। इसके माध्यम से, देश कुछ MLI प्रावधानों को लागू करने का विकल्प चुन सकते हैं।	MLI उन कर संधियों को संशोधित करती है, जो "कवर किए गए कर समझौते" होते हैं।

कवर किए गए कर समझौता (Covered Tax Agreement)

- कवर किए गए कर समझौते का अर्थ है कि दोहरे कराधान से बचने के लिए एक समझौता, जो कि पार्टियों के बीच MLI के लिए लागू होता है, जिसे दोनों पक्षों ने एक अधिसूचना दी है कि वे MLI का उपयोग करके समझौते को संशोधित करना चाहते हैं।

Q.194) ई-नाम (e-NAM) प्लेटफॉर्म में हालिया सुधारों के बारे में, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें

1. किसान अब अपनी उपज को भौतिक रूप से एपीएमसी मंडियों में लाए बिना ई-नाम पर व्यापार कर सकते हैं।
2. सभी किसान उत्पादक संगठनों (FPO) को अपनी उपज को चयनित भण्डारण विकास और नियामक प्राधिकरण (WDRA) के पंजीकृत गोदामों में संग्रहीत करने की आवश्यकता है।
3. बड़े लॉजिस्टिक एग्रीगेटर प्लेटफॉर्म को ई-नाम प्लेटफॉर्म से जोड़ने के लिए प्रावधान किया गया है।

ऊपर दिए गए कथनों में से कौन सा सही है / हैं?

a) केवल 1
b) केवल 1 और 3
c) केवल 2 और 3
d) केवल 3

Q.194) Solution (d)

विकल्प 1	विकल्प 2	विकल्प 3
असत्य	**असत्य**	**सत्य**
केवल वे ही किसान जो अपनी उपज को पंजीकृत भंडारगृहों में संग्रहीत करते हैं तथा e-NWR होने से e-NAM पर व्यापार करने में सक्षम होंगे, ताकि उपज को एपीएमसी में भौतिक रूप से न लाना पड़े।	किसान उत्पादकों के संगठन (FPOs) को अपनी उपज को चयनित WDRA पंजीकृत गोदामों में रखने की आवश्यकता नहीं है। हालांकि, अब वे बोली लगाने के लिए अपने आधार / संग्रह केंद्रों से अपने उत्पादन और गुणवत्ता मानकों की तस्वीर अपलोड कर सकते हैं।	उपयोगकर्ताओं को विकल्प प्रदान करने वाले बड़े लॉजिस्टिक एग्रीगेटर प्लेटफार्मों को जोड़ने के लिए एक प्रावधान किया गया है। व्यापारी रसद प्रदाता की वेबसाइट पर नेविगेट करने और उचित सेवाओं का चयन करने के लिए लिंक का उपयोग करने में सक्षम होंगे।

ई-नाम में हालिया सुधारों के लाभ

- जमाकर्ता लॉजिस्टिक खर्चों को बचा सकता है और बेहतर आय होगी।

- किसान मंडी में जाने की परेशानी के बिना उपज को बेहतर मूल्य पर राष्ट्र भर में बेच सकते हैं।
- यह मंडियों में भीड़ कम करेगा और परेशानी को भी कम करेगा।
- यह एफपीओ को व्यापार करने में आसानी के साथ ऑनलाइन भुगतान सुविधा प्राप्त करने की सुविधा प्रदान करेगा।

Q.195) विशेष आर्थिक क्षेत्रों (SEZs) के बारे में, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें

1. हालांकि SEZ इकाइयां शुल्क के भुगतान के बिना घरेलू टैरिफ क्षेत्र (DTA) से माल आयात कर सकती हैं, हालांकि, वे DTA को माल निर्यात करने के लिए लागू शुल्क का भुगतान करते हैं।
2. सिंगल-ब्रांड खुदरा विक्रेताओं द्वारा SEZ में इकाइयों से खरीदे गए सामान, यदि लागू हो, तो स्थानीय सोर्सिंग मानदंडों को पूरा करने के लिए योग्य होंगे।
3. SEZ इकाइयां जो सकारात्मक शुद्ध विदेशी मुद्रा अर्जन नहीं करती हैं, एक दंड का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी होंगी।

ऊपर दिए गए कथनों में से कौन सा सही है / हैं?

a) केवल 1 और 2
b) केवल 1 और 3
c) केवल 2 और 3
d) उपरोक्त सभी

Q.195) Solution (d)

विकल्प 1	विकल्प 2	विकल्प 3
सत्य	सत्य	सत्य
SEZ इकाइयां ज़ोन में इकाइयों की स्थापना, संचालन और रखरखाव के लिए शुल्क के भुगतान के बिना DTA से वस्तुओं और सेवाओं का आयात / खरीद कर सकती हैं। हालांकि, एक SEZ इकाई लागू शुल्क के भुगतान पर आयात नीति के अनुसार माल, उप-उत्पादों और सेवाओं सहित सामान बेच सकती है।	DPIIT ने हाल ही में स्पष्ट किया कि विदेशी कंपनियों के स्वामित्व वाले एकल-ब्रांड खुदरा विक्रेताओं द्वारा विशेष आर्थिक क्षेत्रों (SEZ) में इकाइयों से खरीदे गए सामान, अनिवार्य 30% स्थानीय सोर्सिंग मानदंडों को पूरा करने के लिए योग्य होंगे। 51% से अधिक एफडीआई के साथ सिंगल ब्रांड रिटेल के लिए 30% स्थानीय सोर्सिंग अनिवार्य है।	SEZ इकाई एक सकारात्मक शुद्ध विदेशी मुद्रा अर्जन होगी। NFE को उत्पादन शुरू होने से पांच वर्ष की अवधि के लिए संचयी रूप से गणना की जाएगी। सकारात्मक विदेशी मुद्रा अर्जित करने में विफलता की स्थिति में यह एक दंड के लिए उत्तरदायी होगी।

Q.196) प्रधान मंत्री अन्नदाता आय संरक्षण अभियान के बारे में, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें

1. यह एक अम्ब्रेला योजना है जो किसानों को आय सहायता प्रदान करेगी।
2. कपास को प्राइस डेफिसिएंसी पेमेंट स्कीम के तहत कवर किया गया है।
3. मूल्य समर्थन योजना के तहत फसलों की भौतिक खरीद नहीं होगी।

ऊपर दिए गए कथनों में से कौन सा सही है / हैं?

a) केवल 1 और 2
b) केवल 2
c) केवल 3

d) इनमें से कोई भी नहीं

Q.196) Solution (b)

विकल्प 1	विकल्प 2	विकल्प 3
असत्य	**सत्य**	**सत्य**
PM-AASHA एक नई अम्ब्रेला योजना है जो किसानों को न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) आश्वासन प्रदान करेगी। **यह एक मूल्य समर्थन योजना है तथा आय समर्थन योजना नहीं है।**	पीडीपीएस में सभी तिलहन शामिल हैं जिनकी एमएसपी अधिसूचित किया गया है। कपास को एक तिलहनी माना जाता है क्योंकि उसमें से तेल निकाला जा सकता है। इसलिए, कपास पीडीपीएस के अंतर्गत आता है।	PSS के तहत, केंद्रीय नोडल एजेंसियां राज्य सरकारों की सक्रिय भूमिका के साथ दालों, तिलहन और कोपरा (copra) की खरीद करेंगी। हालांकि, प्राइस डेफिसिएंसी पेमेंट स्कीम के तहत कवर की गयी फसलों की कोई भौतिक खरीद नहीं होगी।

Q.197) सरकार ने हाल ही में PM-KISAN योजना के तहत 15841 करोड़ रुपये वितरित किए हैं। PM-KISAN योजना के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें।

1. लाभार्थी की पहचान सामाजिक-आर्थिक जाति जनगणना -2011 के आंकड़ों के माध्यम से की जाती है।
2. 4 हेक्टेयर से अधिक भूमि रखने वाले बड़े किसानों को योजना से बाहर रखा गया है।
3. सभी PM-KISAN लाभार्थियों को किसान क्रेडिट कार्ड (KCC) दिया जाएगा।

ऊपर दिए गए कथनों में से कौन सा सही है / हैं?

a) केवल 1 और 2
b) केवल 2 और 3
c) केवल 3
d) उपरोक्त सभी

Q.197) Solution (c)

विकल्प 1	विकल्प 2	विकल्प 3
असत्य	**असत्य**	**सत्य**
यद्यपि पीएम-किसान एक केंद्रीय क्षेत्र योजना है, लाभार्थी किसान परिवारों की पहचान की जिम्मेदारी संबंधित राज्य / संघ राज्य क्षेत्रों के साथ है।	6,000 / - रु. प्रति वर्ष की आय सहायता देश भर के सभी भूमिहीन किसान परिवारों को प्रदान की जाती है, भले ही भूमि का आकार कुछ भी हो, सिवाय इसके कि वे एक अपवर्जन मानदंड (exclusion criteria) के अंतर्गत नहीं आते हों।	सभी पीएम-किसान लाभार्थियों को किसान क्रेडिट कार्ड (केसीसी) दिए जाएंगे ताकि किसान बैंकों से आसानी से कर्ज ले सकें। इससे ऐसे सभी किसानों को फसल और पशु / मछली पालन के लिए अल्पकालिक ऋण प्राप्त करने में मदद मिलेगी।

Q.198) राष्ट्रीय ग्रामीण आर्थिक परिवर्तन परियोजना (National Rural Economic Transformation Project) के बारे में, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें

1. इसके कार्यान्वयन के लिए सरकार पुनर्निर्माण और विकास के लिए अंतरराष्ट्रीय बैंक (IBRD) से ऋण प्राप्त करेगी।
2. परियोजना ग्रामीण बुनियादी ढांचे के विकास कार्यक्रमों का समर्थन करेगी।

ऊपर दिए गए कथनों में से कौन सा सही है / हैं?

a) केवल 1
b) केवल 2
c) 1 और 2 दोनों
d) न तो 1 और न ही 2

Q.198) Solution (a)

विकल्प 1	विकल्प 2
सत्य	असत्य
विश्व बैंक और भारत सरकार ने NREPT के लिए 250 मिलियन अमेरिकी डॉलर के समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। पुनर्निर्माण और विकास के लिए अंतरराष्ट्रीय बैंक (IBRD) से $ 250 मिलियन का ऋण, जिसकी 5 वर्षों की अनुग्रह अवधि और 20 वर्षों की अंतिम परिपक्वता है।	NERTP अपने व्यक्तिगत और / या सामूहिक रूप से स्वामित्व और प्रबंधित उद्यमों के निर्माण के लिए स्टार्ट-अप वित्तपोषण विकल्पों सहित वित्त का उपयोग करने के लिए एक मंच बनाकर ग्रामीण गरीब महिलाओं और युवाओं के लिए उद्यम विकास कार्यक्रमों का समर्थन करेगा। यह युवा कौशल विकास का भी समर्थन करेगा।

Q.199) परियोजना निगरानी समूह (Project Monitoring Group) निम्नलिखित में से किससे संबद्ध है

a) गैर-निष्पादित परिसंपत्ति परियोजनाओं की निगरानी के लिए सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों का एक संघ।
b) सार्वजनिक-निजी भागीदारी परियोजनाओं में बाधाओं का समाधान करने के लिए संस्थागत तंत्र।
c) एक नागरिक समाज संगठन, जो बुनियादी ढांचे के विकास के क्षेत्र में काम करता है।
d) मिशन मोड परियोजनाओं की निगरानी के लिए केंद्र सरकार द्वारा गठित एक विशेष कार्य बल।

Q.199) Solution (b)

परियोजना निगरानी समूह (Project Monitoring Group)

- परियोजना निगरानी समूह (PMG) भारत में 500 करोड़ रुपये के निवेश के साथ परियोजनाओं में मुद्दों और विनियामक बाधाओं के शीघ्र समाधान के लिए एक संस्थागत तंत्र है।
- वर्तमान में, पीएमजी इन्वेस्ट इंडिया, उद्योग विभाग और आंतरिक व्यापार (DPIIT), वाणिज्य मंत्रालय में स्थित है।
- पीएमजी सभी मध्य और बड़े आकार के सार्वजनिक, निजी और ' सार्वजनिक-निजी भागीदारी' (पीपीपी) परियोजनाओं के संबंध में अनसुलझे परियोजना मुद्दों को सूचीबद्ध करना चाहता है।

- DPIIT को चुनौतियों का सामना करने वाली सार्वजनिक और निजी परियोजनाओं की समीक्षा के लिए नोडल निकाय के रूप में प्राधिकृत किया गया है तथा पीएमजी के माध्यम से उनके संकल्प को सुगम बनाता है।
- पीएमजी द्वारा उठाए गए मुद्दे संघ और राज्य-स्तर दोनों पर होते हैं।

Q.200) इन्फ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट्स (InvIts) के बारे में, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें।

1. उन्हें आर्थिक मामलों के विभाग के तहत अवसंरचना नीति और वित्त प्रभाग द्वारा विनियमित किया जाता है।
2. विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों को InvIts में निवेश करने से रोक दिया गया है।

ऊपर दिए गए कथनों में से कौन सा सही है / हैं?

a) केवल 1
b) केवल 2
c) 1 और 2 दोनों
d) न तो 1 और न ही 2

Q.200) Solution (d)

विकल्प 1	**विकल्प 2**
असत्य	**असत्य**
Invits भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड द्वारा विनियमित किया जाता है, न कि आर्थिक मामलों के विभाग द्वारा। वे एक शेयर के समान द्वितीयक बाजार पर कारोबार करते हैं।	विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों को REITs और InvIts की इकाइयों में निवेश करने की अनुमति है।

इन्फ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट्स (Invits)

- एक इन्फ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट (Invits) एक म्यूचुअल फंड की तरह है, जो कि रिटर्न के रूप में आय के एक छोटे हिस्से को अर्जित करने के लिए बुनियादी ढांचे में संभावित व्यक्तिगत / संस्थागत निवेशकों से छोटी मात्रा में धन का प्रत्यक्ष निवेश करने में सक्षम बनाता है।
- बुनियादी ढांचा क्षेत्र की विशिष्ट परिस्थितियों के अनुरूप डिजाइन किए गए REITs के संशोधित संस्करण के रूप में InvITs को माना जा सकता है।
- वे REITs के समान हैं, लेकिन बुनियादी ढांचा परियोजनाओं जैसे कि सड़कों या राजमार्गों में निवेश करते हैं जो स्थिर नकदी प्रवाह उत्पन्न करने में कुछ समय लेते हैं।

Copyright © by IASbaba

All rights are reserved. No part of this document may be reproduced, stored in a retrieval system or transmitted in any form or by any means, electronic, mechanical, photocopying,

recording or otherwise, without prior permission of IASbaba.